राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 5 अंक 33

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 13 जुलाई, 2021

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 14



इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारूमा ने तोड़ा इंग्लैंड का सपना

>> 12

जागरण विशेष

वनारसी साड़ियों पर दमक रहा हुनर का 'पंचकार्ड'



वाराणसी : आइआइटी, धनबाद के पूर्व छात्रों नित्यानंद व शणमुख कृष्णा के एक प्रयास ने बनारसी साड़ी कारोबार को वर्चुअल कर दिया है। कोरोना की मार से बेहाल हथकरघा कारीगरों और बुनकरों के लिए यह बहुत बड़ा सहारा बना है। (पेज-10)

नेपाल में भंग संसद बहाल, देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश

काठमांडू, प्रेट्र: नेपाल में अपनी अल्पमत सरकार बचाने में जुटे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शीर्ष कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए भंग संसद को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा को मंगलवार तक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दिया। पांच महीनों में दूसरी बार भंग प्रतिनिधि सभा (संसद) को बहाल किया गया। कोर्ट ने 23 फरवरी को भी प्रधानमंत्री ओली को झटका देते हुए भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने के आदेश दिए थे।

सोमवार को चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी का निचले सदन को भंग करने का फैसला असंवैधानिक था। पीठ ने मंगलवार तक देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का भी आदेश दिया। 74 वर्षीय देउबा इससे पहले चार बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोर्ट ने संसद का नया सत्र 18 जुलाई की शाम पांच बजे बुलाने का भी आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले को ओली के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो समय पूर्व चुनावों की तैयारी कर रहे थे।

चीफ जस्टिस राणा ने कहा कि जब सांसद संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत नए प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए मतदान में हिस्सा लेते हैं, तब पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। पीठ में चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार करकी, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा और डा. आनंद मोहन भट्टराई शामिल थे। संविधान पीठ ने पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई पूरी की थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 275 सदस्यीय निचले सदन को 22 मई को पांच महीने में दूसरी बार भंग कर दिया था। साथ ही 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते मध्यावधि चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी।

उधर राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में करीब 30 याचिकाएं दायर की गई थीं। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन की तरफ से भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस पर 146 सांसदों के हस्ताक्षर थे। इसमें निचले सदन को फिर से बहाल करने तथा शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अपील की गई थी।

गौरतलब है कि नेपाल में गत वर्ष 20 दिसंबर को तब राजनीतिक संकट गहरा गया था, जब सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया और 30 अप्रैल तथा 10 मई को नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी।

ओली को झटका

- सुप्रीम कोर्ट ने पांच माह में दूसरी बार भंग प्रतिनिधि सभा को किया बहाल
- संसद का नया सत्र 18 जुलाई की शाम पांच बजे बुलाने का भी दिया आदेश



शेर बहादुर देउबा होंगे अगले पीएम (फाइल)

फैसले का स्वागत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने कहा कि अदालत का फैसला सराहनीय है। उसने राजनीतिक तंत्र की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि अब सभी फैसले संसद लेगी। रायटर के मुताबिक, देउबा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शीर्ष कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की है। अब पांच राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे।

शेर बहादुर देउबा के नेपाल का पीएम बनने से भारत को राहत पेज>>11

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▸ पृष्ठ 2

फायरिंग का मन किया तो चौकी से चुरा ली इंसास रायफल

गाजियाबाद: 10वीं कक्षा के छात्र ने पुलिस चौकी से इंसास रायफल चुरा ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया है। उसने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर वीडियो देखकर उसका भी फायरिंग करने का मन हुआ तो रायफल चुरा ली। उधर, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई है। मामला उप्र के साहिबाबाद क्षेत्र का है।

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता पर लाए जाएंगे निजी बिल

नई दिल्ली: गोरखपुर से भाजपा के लोकसभा सदस्य रवि किशन व राजस्थान से राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में क्रमश: जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर निजी सदस्यों के विधेयक पेश करने वाले हैं। एक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी सदस्य के बिल के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रीय फलक ▸ पृष्ठ 5

जैसलमेर पहुंचा मानसून, दिल्ली को अब भी इंतजार

नई दिल्ली: दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को अपने आखिरी पड़ाव में पड़ने वाले राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश का अब भी इंतजार है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में से अलीगढ़ (उप्र) व करनाल (हरियाणा) में बारिश हुई, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में बादल मंडराते ही रहे, बरसे नहीं। इस वजह से यहां गर्मी से राहत नहीं मिली है।

कोरोना से जंग ▸ पृष्ठ 6

पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम संग प्रधानमंत्री की अहम चर्चा आज

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के छोटे-छोटे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं जो चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार कोपूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूत्रों को कहना है कि इस बैठक में मोदी हालात को काबू करने के लिए मुख्यमंत्रियों को कुछ जरूरी निर्देश दे सकते हैं।

गजनी शहर में घुसे तालिबान आतंकी

अफगानिस्तान में जंग ▸ नागरिकों के घरों में ठिकाने बनाकर अफगान सेना पर कर रहे हमले

दूरदराज के क्षेत्रों के बाद अब प्रांतों की राजधानियों और बड़े शहरों पर आतंकियों की नजर

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान में तालिबान ने दूरदराज के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद अब प्रांतीय राजधानी व बड़े शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तालिबानी आतंकियों ने ऐतिहासिक शहर गजनी को चारों ओर से घेर लिया है। शहर पर कब्जे को लेकर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। आतंकी नागरिकों के घरों को ठिकाना बनाकर अफगानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों को आतंकियों को निशाना बनाने में खासी मुश्किल हो रही है।

कंधार शहर से 110 किलोमीटर दूर शोरवाक जिले पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने गजनी प्रांत की राजधानी गजनी शहर पर कब्जे को लेकर लड़ाई छेड़ दी है। प्रांतीय परिषद के एक सदस्य हसन रेजायी के मुताबिक, काबुल से कंधार जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित गजनी शहर की स्थिति बहुत गंभीर है।

कंधार पर पश्चिम से हो रहा हमला : स्थानीय लोगों ने बताया कि कंधार प्रांत में भी कई स्थानों पर सुरक्षा बलों और तालिबानी आतंकियों के बीच संघर्ष चल रहा है। तालिबान के खिलाफ हथियारबंद लड़ाकों के साथ अफगान सुरक्षा बलों का साथ दे रहे पूर्व सांसद हमीदजई ललय ने बताया कि तालिबान कंधार शहर में पश्चिम की तरफ से हमले कर रहा है। अफगानी सुरक्षा बल तालिबान को कंधार से खदेड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

घरों से हमले होने के कारण अफगान सुरक्षा बलों को हो रही मुश्किल



अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तालिबान से मुकाबले के लिए तैयार अफगान स्पेशल फोर्स के जवान। रायटर

सरकार ने कहा, सभी प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण : अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी प्रांतीय राजधानियों पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन तालिबान संघर्ष के जरिये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह तालिबान ने बादगीस की प्रांतीय राजधानी में घुसकर पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था।

पड़ोसी देश हुए सतर्क : 'आइएएनएस' के अनुसार तालिबान ने उज्बेकिस्तान की सीमा के पास बल्ख प्रांत में हेयरटन शहर पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले को विफल कर दिया गया। इस बीच, ईरान ने कहा है कि उसकी अफगानिस्तान से लगती सीमा सुरक्षित है, कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 'एएनआइ' के अनुसार तुर्कमेनिस्तान ने अफगानिस्तान से लगती अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।

40 तालिबानी मारे गए, डिप्टी कमांडर भी शामिल

'एएनआइ' के अनुसार, अफगान सेना ने तालिबान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 40 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर हो गए हैं, जबकि 35 आतंकी घायल हुए हैं। मरने वालों में तालिबान का डिप्टी कमांडर मावलवी हिजरत भी शामिल है।

शीर्ष अमेरिकी जनरल ने छोड़ी अफगानिस्तान की कमान

रायटर के अनुसार, अमेरिकी सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल स्काट मिलर ने सोमवार अफगानिस्तान की कमान छोड़ दी। मिलर यहां 2018 से तैनात थे। इस तरह से उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 20 साल से जारी जंग का अंत कर दिया। मिलर अफगानिस्तान में अमेरिका के अंतिम चार सितारा जनरल बन गए हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित नौसेना की सेंट्रल कमांड के जनरल कैनेथ मैकेंजी काबुल के लिए प्रस्थान कर गए हैं। उनकी कमांड के पास अफगानिस्तान के साथ सीरिया व इराक की भी जिम्मेदारी है। उनके पास 31 अगस्त तक अशरफ गनी सरकार के समर्थन में हवाई हमलों का अधिकार रहेगा।

तालिबान ने कहा, हुक्म चलाने की कोशिश न करे पाक

'एएनआइ' के अनुसार, तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह शांति प्रक्रिया में सहायता करे, हम पर हुक्म चलाने या अपने विचार थोपने की कोशिश न करे। बता दें कि अफगान सरकार और तालिबान के बीच कतर की राजधानी में शांति वार्ता जारी है, लेकिन उसमें मामूली प्रगति ही हुई है।

आधी से ज्यादा अफगान आबादी को मदद की जरूरत : यूएन

'एएनआइ' के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अधिकारियों ने कहा है कि हिंसाग्रस्त देश में आधी से ज्यादा आबादी को मदद की दरकार है। पांच साल से कम उम्र के एक तिहाई से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पाइंदा ने अमेरिका की ओर से 250 मिलियन डालर की मदद की घोषणा की है।

अफगानिस्तान में भारत की 500 परियोजनाएं खतरे में

नई दिल्ली: तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता उन परियोजनाओं को सुरक्षित रखने की है, जिसे लगाने में उसने अरबों डालर खर्च किए हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से 500 परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उन पर काम जारी है। (पेज-3)

सस्पेंस खत्म, 12 सितंबर को नीट का आयोजन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया एलान, आज शाम पांच बजे से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
- अभ्यर्थियों के लिए मास्क अनिवार्य, शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्र और शहर बढ़ाए गए

एमबीबीएस, बीएएमएस समेत चिकित्सा के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट (यूजी) का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इसका एलान किया है। अब तक इस परीक्षा को एक अगस्त को कराने का प्रस्ताव था। आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया मंगलवार शाम पांच बजे से एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, 'कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए देश भर में 12 सितंबर को नीट (यूजी) 2021 का आयोजन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया कल शाम पांच बजे से एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'शारीरिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए जिन शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 2020 के 3,862 केंद्रों की तुलना में बढ़ाई जाएगी।' परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को सितंबर में कराने के एलान को छात्रों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयारी करने का कुछ और वक्त मिल जाएगा। वैसे भी छात्रों का एक बड़ा वर्ग एक अगस्त की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा था। नीट की तारीख को आगे बढ़ाने के पीछे एक और बड़ा कारण मेडिकल कालेजों के सत्र में देरी भी है। पिछले साल भी नीट के सितंबर में कराए जाने से मेडिकल कालेजों में नए सत्र की शुरुआत देर से हुई थी। इस बीच कोरोना संकट के चलते सस्थानों के बंद होने से यह सत्र समय पर पूरा नहीं हो पाया था। इसे लेकर मेडिकल कालेजों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट की थी। खासबात यह है कि इससे पहले एनटीए ने सिर्फ नीट के आयोजन की तारीख का एलान किया था। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं शुरू होने की तारीख नहीं बताई थी।



धर्मेंद्र प्रधान। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

पिछले साल 15 लाख अभ्यर्थी थे

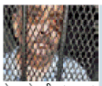
पिछले साल भी नीट का आयोजन 13 सितंबर को हुआ था। तब करीब 15 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे।

नीट-एमडीएस की काउंसलिंग में देरी का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया पेज>>3

चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट से चिकित्सकीय आधार पर जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र: पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट ने सोमवार को चिकित्सकीय आधार पर जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने न्यूरोलाजिकल दिक्कतों के इलाज के लिए एंटीगुआ एवं बरबुडा जाने की इजाजत भी दे दी है। साथ ही डोमिनिका में गैरकानूनी रूप से प्रवेश के मामले की सुनवाई पर भी रोक लगा दी।

भारत से भागने के बाद वर्ष 2018 से चोकसी एंटीगुआ एवं बरबुडा में रह रहा था। अदालत ने उसे जमानत राशि के रूप में 10 हजार ईस्टर्न कैरेबियन डालर जमा करने के बाद एंटीगुआ एवं बरबुडा जाने की अनुमति प्रदान की है।



मेहुल चोकसी (फाइल)

एंटीगुआ जाने की मिली इजाजत, अवैध रूप से प्रवेश के चल रहे केस पर भी लगी रोक

'आइएएनएस' के मुताबिक, चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, बाद में उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया था और अब वह वहां गैरकानूनी रूप से प्रवेश के आरोपों का सामना कर रहा है। चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने खिलाफ कार्यवाही रद करने की मांग की थी। उसका आरोप है कि उसे भारत सरकार के प्रतिनिधियों के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है।

टेलीग्राम एप के जरिये कई राज्यों तक फैला था मिनहाज का नेटवर्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी में रविवार को पकड़े गए दो आतंकियों में एक मिनहाज अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद का लखनऊ में सबसे सक्रिय सदस्य था। एटीएस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि मिनहाज करीब डेढ़ साल पहले टेलीग्राम एप के जरिए अलकायदा के हैंडलरों के संपर्क में आया था। उसके बाद उसके तार जम्मू-कश्मीर व अन्य राज्यों में सक्रिय युवकों से जुड़ गए थे। आशंका है कि मिनहाज व उसके साथी यहां नया माड्यूल तैयार कर चुके थे। हालांकि मिनहाज व मसीरुद्दीन से जुड़े कई सवाल अब भी पहेली हैं। उनके जवाब दोनों से पुलिस रिमांड के दौरान उगलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

- एटीएस मोबाइल का डाटा रिकवर करने का कर रही प्रयास
- कई संदिग्धों से जारी है पूछताछ, कई जिलों में भेजी गईं टीमें
- एटीएस ने कानपुर में बिल्डर समेत तीन अन्य संदिग्ध उठाए, अब तक छह
- बिल्डर ने आतंकियों को वाहन व ठहरने का ठिकाना उपलब्ध कराया था



एटीएस द्वारा गिरफ्तार आतंकी मिनहाज अहमद। सौ. एटीएस

कानपुर से हिरासत में लिए गए छह संदिग्ध

एटीएस द्वारा पकड़े गए आतंकियों ने कानपुर में अन्य दहशतगर्दों और उनके मददगारों के छिपे होने की सूचना दी थी। इसके आधार पर एटीएस ने रविवार देर रात तक छापेमारी करके जाजमऊ व पेचबाग इलाकों से एक-एक संदिग्ध को पकड़ा था। सोमवार सुबह एटीएस ने दोबारा छापेमारी शुरू की और देर शाम तक करीब एक दर्जन ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में चार अन्य को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक चमनगंज का बिल्डर भी है। अवैध इमारतें खड़ी करने में चर्चित इस बिल्डर के बारे में बताया जा रहा है कि इसने आतंकवादियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। आतंकियों के कानपुर में वाहन और ठहरने का ठिकाना भी इसी ने उपलब्ध कराया था।

चुप्पी साधे रहे दोनों : सूत्रों का कहना है कि सोमवार रात की गई पूछताछ के दौरान दोनों अधिकतर सवालों पर चुप्पी साधे रहे। एटीएस ने उनके साथी शकील का घर तलाश लिया है, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा सकी है। उप्र को दहलाने की बड़ी साजिश रचने वाला मिनहाज बेहद चालाक है। उसने मोबाइल फोन से टेलीग्राम एप व अन्य डाटा डिलीट कर दिया था। एटीएस डाटा रिकवर करने का प्रयास कर रही है।

आज से शुरू होगी पूछताछ : ज्ञात हो, एटीएस ने रविवार को अलकायदा के आतंकी मिनहाज व मसीरुद्दीन को लखनऊ में गिरफ्तार किया है। एटीएस दोनों को मंगलवार सुबह रिमांड पर लेकर उनसे नए सिरे से पूछताछ शुरू करेगी।

कई शहरों में डेरा जमाए है टीमें पेज>>5

विरासत

मुस्लिम बनने के 800 साल बाद भी मजबूत है रिश्ते की डोर

नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान के पूर्वज राजस्थान से आकर बिहार में बसे थे, दो पड़ोसी गांवों में एक में हिंदू व दूसरे में मुस्लिम आबादी के बीच कायम है संबंधों की मिठास

अरविंद शर्मा, पटना

बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने खुद को हिंदू पूर्वज की औलाद बताकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत की हिंदू-मुस्लिम का डीएनए एक ही होने वाली बात को आगे बढ़ाया है। जमा खान के पूर्वज भगवान सिंह के राजस्थान से बिहार आने और मु. पहाड़ खान बन जाने की दास्तान आठ सौ वर्षों के बाद भी कैमूर जिले के गांवों में लोगों की जुबान पर है जो हिंदू-मुस्लिम का डीएनए एक होने का सबूत भी है।

एक किलोमीटर के अंतर पर दो गांव हैं- नौघरा और सरैया। दोनों को दो भाइयों ने बसाया। एक में मुस्लिम आबादी है तो दूसरे में हिंदू। दोनों का सदियों का साथ है। रीति-रिवाज में भी बहुत फर्क नहीं है। ईद-होली साथ मनती है। जीवन-मरण में पट्टीदारी (एक-दूसरे के रस्मो-रिवाज में सम्मिलित होना) चलती है। मतांतरण के बाद भी परंपराएं पूरी तरह नहीं बदलीं। पुरोहित को फसल का अग्रभाग दिया जाता है। शादियों में हिंदुओं की तरह ही हल्दी का उबटन लगाया जाता है। मंडप की रस्म होती है। जमा खान के चचेरे भाई राजा खान बताते हैं कि तीन दशक पहले तक निकाह से पहले वैदिक मंत्र भी पढ़े जाते थे। दोनों गांवों के पुरोहित भी एक ही थे-रामप्रसाद तिवारी। उनके पुत्र कैलाश तिवारी तक यह परंपरा चलती रही थी। उसके बाद शिथिल होती गई।



बिहार में कैमूर जिले के चैनपुर में राजा शालिवाहन के किले का मुख्य द्वार। इस्लाम कबूल करने के पहले भगवान सिंह इसी राज के सेनापति थे। जागरण

धर्म बदलकर भगवान सिंह बन गए पहाड़ खान

जमा खान की कहानी महिमन सिंह से शुरू होती है, जो वैस राजपूत थे। सरैया निवासी और जयराम सिंह के वंशज आनंद सिंह के मुताबिक, 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के बख्तियार खिलजी का दौर था। कैमूर जिले के चैनपुर स्टेट में गहरवाल वंश के शालिवाहन का राज था। राजस्थान के बांसवाड़ा से आकर महिमन सिंह ने चैनपुर में शरण ली। उनके दो पुत्र थे भगवान सिंह और जयराम सिंह। भगवान ने चैनपुर स्टेट की सेना में नौकरी कर ली। ओहदा बढ़ा तो सेनापति बन गए। 1199 में नालंदा विवि के पुस्तकालय को जलाने से पूर्व खिलजी ने चैनपुर पर हमला कर दिया और हरा दिया। भगवान को मजबूरन मतांतरण करना पड़ा। विशाल व बलिष्ठ शरीर के कारण उनका नाम पहाड़ खान रखा गया। उनके वंशज नौघरा में बसे हैं। जयराम के वंशज मलिक सराय (सरैया) में हैं।



जमा खान।

बुजुर्ग पहनते धोती कुर्ता, लंबी दाढ़ी से परहेज

सदियों ने दोनों गांवों की आबादी भले बढ़ाई है, फासला नहीं। पैदाइश का मौका हो या मय्यत का, भाई की तरह एक-दूसरे के काम आते हैं। अंतिम यात्रा में मुस्लिमों का भी कंधा नसीब होता है और मय्यत में हिंदू भी मिट्टी देने जाते हैं। परंपराएं परस्पर चलती हैं। खेती-किसानी भी भाईचारे की नजीर है। एक तरफ मुन्ना सिंह का खेत है तो दूसरी तरफ जमा खान का, जो बताता है कि भाइयों में बंटवारा भी उसी तरह से हुआ होगा। रहन-सहन भी समान है। नौघरा के बुजुर्ग आज भी धोती-कुर्ता पहनते हैं। लंबी दाढ़ी रखने से परहेज करते हैं। उन्हें देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। चैनपुर में आज भी राजा शालिवाहन के किले का अवशेष और पहाड़ खान की मजार है। अवसर विशेष पर दोनों गांव के लोग साथ-साथ शिरकत करते हैं।

शायद चार जुलाई से ही शुरू हो चुकी है कोरोना की तीसरी लहर

- देश के शीर्ष विज्ञानी ने किया दावा, लोगों को लापरवाही के प्रति भी किया सावधान
- फरवरी की तरह चार जुलाई से प्रतिदिन होने वाली मौतों की प्रवृति में हुआ है बदलाव

हैदराबाद, प्रेट्र: देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शायद चार जुलाई को ही दस्तक दे चुकी है। यह दावा किया है हैदराबाद विवि के प्रो-वाइस चांसलर और भौतिक विज्ञानी डा. विपिन श्रीवास्तव ने। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का उचित तरीके से पालन करने को भी कहा है।

डा. श्रीवास्तव पिछले 463 दिनों से संक्रमण के आंकड़ों-मृत्युदर का विश्लेषण करते रहे हैं। उन्होंने कहा, चार जुलाई से कोरोना के मामले और मौत के आंकड़े देश में तीसरी लहर के आने का संकेत दे रहे हैं। कुछ इसी तरह के आंकड़े फरवरी के पहले हफ्ते से देखने को मिले थे, तब कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी।

डा. श्रीवास्तव के मुताबिक जब कभी भी रोजाना होने वाली मौतों की प्रवृत्ति में बदलाव होता है यानी एक दिन मौतें कम होती हैं और अगले दिन ज्यादा या एक दिन ज्यादा तो उसके अगले दिन कम, तो डेली डेथ लोड (डीडीएल) में बेतहाशा उतार-चढ़ाव होता है। फरवरी के पहले हफ्ते के अंत में डीडीएल में इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, जबकि उस समय रोजाना सौ मौतें ही हो रही थीं। सभी ने मान लिया था कि महामारी खत्म हो गई, पर उसके बाद क्या हुआ, सबके सामने है।

उन्होंने कहा, कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति चार जुलाई से देखने को मिल रही है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि डीडीएल नकारात्मक बनी रहे। अहम बात यह है कि हम विनाशकारी दूसरी लहर झेल चुके हैं, इसलिए आम लोगों के साथ ही प्रशासन को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

6 मलेरिया के और दो डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है एक सप्ताह में। इस दौरान चिकनगुनिया के भी दो मरीज सामने आए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 13 जुलाई, 2021

न्यूज गैलरी

गोवा बदलाव चाहता है : केजरीवाल

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गोवा जाएंगे। केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि गोवा में काफी गंदी राजनीति है, जिसे वे बदलना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'गोवा बदलाव चाहता है। विधायकों को खरीदने और बेचने वाली पार्टियां काफी हैं। गंदी राजनीति काफी है। गोवा विकास चाहता है। धन की कोई कमी नहीं है, केवल ईमानदार इरादे की कमी है। गोवा ईमानदार राजनीति चाहता है। कल गोवा में मिलते हैं।' गौरतलब है कि गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि हाल ही में केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा किया था और वहां कई घोषणाएं की थीं। (राब्यू)

इस साल सबसे कम एक दिन में कोरोना के 45 नए मामले आए

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना के मामले घटकर 50 से कम हो गए हैं। सोमवार को 45 नए मामले आए, जो इस साल सबसे कम है। वहीं 92 मरीज ठीक हुए। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 700 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से तीन मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14 लाख 35 हजार 128 मामले आए हैं। जिसमें से 14 लाख नौ हजार 417 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.20 फीसद हो गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 25,018 हो गई है। इस वजह से मृत्यु दर 1.74 फीसद है। मौजूदा समय में दिल्ली में 693 सक्रिय मरीज हैं। जिसमें से 397 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी घटकर 526 हो गई है। कोरोना के मरीज कम होने से दिल्ली सरकार ने भी राहत की सांस ली है। (राब्यू)

मेदांता में अपने पिता से मिलने पहुंचे अखिलेश

गुरुग्राम : 30 जून से मेदांता अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का स्वास्थ्य ठीक है। सोमवार को मुलायम सिंह के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। अखिलेश दोपहर 12 बजे के करीब अस्पताल पहुंचे थे और दो घंटे तक अस्पताल में रहे। दिल्ली वापस जाने से पहले अखिलेश ने डाक्टरों से अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की। दरअसल मुलायम सिंह को पेट में संक्रमण के चलते 30 जून को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको कमरे में रखा गया है और अब पहले के मुकाबले आराम बताया जा रहा है। यहां पर वरिष्ठ फिजीशियन डा. सुशीला कटारिया की देख-रेख में इलाज चल रहा है। (जासं)

सत्येंद्र जैन के आवास के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

जल संकट ▸ भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बुलडोजर लेकर पहुंचे थे

48 घंटे में जल संकट दूर नहीं होने पर सीएम आवास का पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

जल संकट के विरोध में दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष व मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास का पानी कनेक्शन काटने गए भाजपाइयों को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटा दिया। पूर्व घोषणा के अनुसार पानी का कनेक्शन काटने के लिए भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बुलडोजर लेकर राजनिवास मार्ग पहुंचे थे। हालांकि, उन्हें रोकने के लिए पहले से ही बैरिकेड लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार डालने के साथ ही हल्का लाठी चार्ज किया। इससे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासु रुखड़ सहित कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। गुप्ता ने अब 48 घंटे में जल संकट दूर नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास का पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। उन्होंने जैन के साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।



दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के आवास के बाहर पानी की समस्या को लेकर भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछार से बचने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी। संजय

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी से राजधानी में जल संकट है। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री व उनकी पार्टी के नेता हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सच्चाई यह है कि हरियाणा के साथ प्रतिमाह पांच सौ एमजीडी पानी देने का समझौता हुआ है, जबकि दिल्ली को 640 एमजीडी पानी मिल रहा है। सरकार पानी का सही तरह से प्रबंधन करने में विफल साबित हुई है। दिल्ली के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और केजरीवाल अपने सरकारी आवास में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कालोनियों में पाइप लाइन से पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। दिल्ली के लोगों की समस्या हल करने के बजाय मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। लोग पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। भाजपा लोगों के साथ मिलकर आंदोलन को तेज करेगी। बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के कारण आठ सौ करोड़ रुपये के लाभ में चलने वाला दिल्ली जल बोर्ड बदहाल हो गया है। राजधानी में 1300 एमजीडी पानी की जरूरत है और जल बोर्ड मात्र 775 एमजीडी पानी ही आपूर्ति कर रहा है। प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, राजन तिवारी व जयवीर राणा, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, भाजपा विधायक अजय महावर, अनिल वाजपेयी एवं मोहन सिंह बिष्ट सहित अन्य नेता मौजूद थे।

दिल्ली के लिए पानी छोड़े हरियाणा : चड्ढा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने सोमवार को वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की ओर से पानी न दिए जाने की वजह से यमुना नदी सूख गई है। इसके चलते दिल्ली में पानी का संकट हो गया है। उन्होंने हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए पानी छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली को पानी दे। अगर हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा तो दिल्ली में विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि सन 1965 के बाद पहली बार यमुना का जल स्तर साढ़े सात फीट घटा है और इसके चलते दिल्ली में रोजाना 100 एमजीडी पानी की आपूर्ति कम हो रही है। चड्ढा ने कहा कि सेंट्रल दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में जल संकट गहरा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय दूतावास शामिल हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1995 में दिए आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार को रोजाना पानी देने के लिए निर्देशित करने की मांग की है।

चड्ढा ने कहा कि वजीराबाद बैराज में हरियाणा की ओर से यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता है। इसके बाद यह पानी साफ कर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। कहा कि हरियाणा ने दिल्ली के अधिकार का 120 एमजीडी पानी रोका हुआ है।

एसटीपी से बदबू रोकने में नाकाम दिल्ली जल बोर्ड पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: कोंडली स्थित एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाली बदबू को नियंत्रित करने में लापरवाही बरतने और अपनी जिम्मेदारी से भागने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को आम दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीजेबी ने पहले कहा था कि एसटीपी में गंध नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उक्त गंभीर टिप्पणी के साथ पीठ ने डीजेबी को एक जून 2021 से आदेश का अनुपालन करने तक प्रति माह पांच लाख रुपये जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि जुर्माना राशि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा की जाए और इसका उपयोग पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। पीठ ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि डीजेबी अब अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा हैं और अब यह कहा जा रहा है इस संबंध में उठाए गए छोटे कदम पर्याप्त हैं और अब गंध नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि डीजेबी का यह स्टैंड जनहित और इस ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ है। यह स्पष्ट है कि डीजेबी एसटीपी से गंध को रोकने के अपने दायित्व को निभाने में विफल रहा है।

जनता को झांसा देना बंद करें केजरीवाल : माकन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोमवार को ट्वीट और वीडियो के जरिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब से क्षेत्रफल में 34 गुना छोटा होने के बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली पर 34 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है, जबकि दिल्ली में पानी नहीं, डीटीसी की बस नहीं, मेट्रो निर्माण ठप, नए अस्पताल नहीं। आप सरकार दिल्ली को मिलने वाले फंड को इश्तहारों में खर्च कर रही है।

माकन ने कहा कि केंद्र सरकार आठ हजार करोड़ रुपये दिल्ली पुलिस पर खर्च करती है। पांच अस्पतालों जिनमें एम्स व सफदरजंग भी शामिल हैं, उन पर भी सात हजार करोड़ खर्च करती है, जिनमें तेरह हजार बेड हैं। डीडीए पर छह हजार करोड़ एवं एनडीएमसी पर चार हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय यूनिवर्सिटी (जेएनयू, जामिया और डीयू) पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ भी खर्च नहीं करती है।

माकन ने कहा कि पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल 1,484 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि से पंजाब दिल्ली से 34 गुना बड़ा है, लेकिन पंजाब में बेहतर बिजली, सड़कें व अन्य सुविधाएं हैं। दिल्ली में पीने के पानी का अभाव है, सैकड़ों लोग टैंकर पर खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बताना होगा कि दिल्ली की जनता का पैसा कहां उड़ा रहे हैं। पंजाब सरकार दिल्ली से बेहतर सेवा दे रही है। इसलिए केजरीवाल झांसा देना बंद करें।

बसों की खरीद प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

डीटीसी की एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद और उसके रखरखाव के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने 3,413 करोड़ के टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सीबीआइ व केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से कराने की मांग की है। सोमवार को पत्रकार वार्ता में चौधरी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार को 24 घंटे का समय देती है कि वह इस घोटाला की विस्तृत जांच के आदेश जारी करे अन्यथा दिल्ली कांग्रेस भ्रष्टाचार के पुख्ता दस्तावेज जुटाकर सीबीआइ तथा सीवीसी के समक्ष स्वयं शिकायत दर्ज कराएगी। चौधरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि अगर उनकी सरकार बस खरीद और रखरखाव टेंडर के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो इसकी जांच सीबीआइ से क्यों नहीं करा रहे हैं।

टीके की कमी से बंद रहे ज्यादातर टीकाकरण केंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी में टीके की कमी के कारण लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सोमवार को ज्यादातर टीकाकरण केंद्र बंद रहे। सिर्फ 36,313 लोगों को टीका लग पाया। लिहाजा टीके की कमी के कारण टीकाकरण का महा अभियान सुस्त पड़ गया है।

23 जून से लेकर तीन जुलाई के बीच प्रतिदिन औसतन डेढ़ लाख लोगों को टीका लग रहा था लेकिन पिछले एक सप्ताह से टीके की कमी बनी हुई है। इस दौरान सिर्फ आठ जुलाई को एक लाख 59 हजार 37 लोगों को टीका लगा था। वहीं नौ जुलाई को एक लाख 31 हजार 156 लोगों को टीका लगा था। बाकी दिन टीकाकरण कम हुआ। दिल्ली में टीकाकरण के लिए 1374 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीके की कमी से 526 केंद्रों पर ही टीका लगाया जा सका। फिलहाल स्थिति यह है कि दिल्ली में कोविशील्ड के टीके की मात्र 19 हजार डोज स्टाक में है।

'जब चीजें खराब होती हैं दिल्ली सरकार आरोप लगाने लगती है'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का समय देते हुए हाई कोट ने उठाए सवाल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित करने पर देरी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने पूछा कि अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीठ ने कहा कि आप समय बर्बाद नहीं कर सकते। आखिर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जब चीजें खराब होती हैं और तब आप सभी पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील रिजवान ने पीठ को बताया कि केंद्र स्थापित करने के लिए संबंधित फाइल पर विचार और अनुमोदन लंबित है। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली सरकार ने कोई स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इस पर पीठ ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

जेएनयू शिक्षक संघ व जेएनयू छात्र संघ और दो फैकल्टी सदस्यों ने याचिका दायर कर परिसर में कोरोना केंद्र स्थापित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अभिक चिमनी ने पीठ को बताया कि दो आदेश पारित होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक केंद्र स्थापित नहीं किया है। जेएनयू की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि विश्वविद्यालय ने केंद्र स्थापित करने के लिए जगह पहले ही निर्धारित कर ली है और पानी और बिजली देने के लिए भी सहमत है। अदालत ने मई माह में कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया था।

साथी दंगाई से बातचीत का आडियो सुन कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से किया इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली दंगा

24 फरवरी को दंगाइयों ने कर दी थी हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या

दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में साथी दंगाई से बातचीत का आडियो सुन कर कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को आरोपित समीर उर्फ साहिल उर्फ मेंढक को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि सह आरोपित के मोबाइल से मिली आडियो रिकार्डिंग दंगे में आरोपित की सक्रियता को बताने के लिए काफी है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

गत वर्ष 24 फरवरी को दयालपुर में चांद बाग के पास वजीराबाद रोड पर हथियारों से लैस दंगाइयों ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपित समीर ने सह आरोपित मंसूर और दानिश को मिली राहत के आधार पर जमानत अर्जी लगाई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील दिनेश कुमार ने कहा कि समीर के खिलाफ घटना में शामिल होने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इस मामले में गवाह के बयान लेने में भी देरी की गई थी। जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपित शाहनवाज के मोबाइल से एक आडियो फाइल बरामद हुई है, जिसमें वह और आरोपित समीर गत वर्ष 24 फरवरी को हुई उस घटना को लेकर बात करते सुनाई दे रहे हैं, जिसमें पुलिस पर हमला किया गया। दोनों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपित मंसूर को मानसिक रोगी और आरोपित दानिश को वीडियो फुटेज न होने पर जमानत दी गई। जबकि, आरोपित समीर के खिलाफ इसी घटना से जुड़ा आडियो है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आरोपित के दावे को भी मानने से इन्कार कर दिया, जिसमें एक वीडियो के हवाले से एक नर्सिंग होम की छत से चलाई गई गोली के लगने से हेड कांस्टेबल की मौत होने की बात कही गई थी।

इशरत की मांग, यूएपीए की हो समीक्षा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत अर्जी पर सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपित इशरत जहां की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में पूछा कि क्या राजनीतिक जुड़ाव होना गलत है। इसी जुड़ाव के चलते जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ झूठी कहानी बुनी है। जहां जरूरत पड़ी, वहां झूठे गवाह भी खड़े किए गए। आवाज दबाने के लिए यूएपीए लगा दिया गया। जबकि जांच एजेंसी के पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। दंगे के मामले में यूएपीए की समीक्षा होनी चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में इशरत के वकील प्रदीप तेवतिया ने कहा कि जांच एजेंसी ने उनकी मुवक्किल पर दंगे भड़काने के लिए वित्त पोषण का झूठा आरोप लगाया है।

जूही चावला के आवेदन पर सुनवाई से न्यायमूर्ति नरुला ने खुद को किया अलग

जासं, नई दिल्ली : देश में 5-जी नेटवर्क के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य के आवेदन पर सुनवाई करने से दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने खुद को अलग कर लिया है। सोमवार को सूचीबद्ध मामले पेश होने पर पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश से यह मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति जेआर मिधा की पीठ ने आवेदन को संजीव नरुला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। जिस दिन उन्होंने आदेश दिया, सेवा में वह उनका अंतिम दिन था। इसके बाद मिधा सेवानिवृत्त हो गए। अब नरुला ने इस मामले से खुद को अलग करते हुए कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश से यह मामला अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जूही समेत अन्य ने आवेदन दाखिल करके मांग की है कि एकल पीठ की तरफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज की गई याचिका में खारिज की जगह निरस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाए।

फायरिंग का मन किया तो चौकी से चुरा ली इंसास रायफल, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

कक्षा 10वीं के छात्र ने पुलिस चौकी से इंसास रायफल चुरा ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से रायफल बरामद की है। पूछताछ में उसने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर वीडियो देखकर उसका भी फायरिंग करने का मन हुआ तो पुलिस की रायफल चुरा ली। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। उधर, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है।

मामला उप्र के गाजियाबाद साहिबाबाद का है। चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मोहित कुमार के अनुसार, चौकी के लिए आवंटित इंसास रायफल कमरे में रखी जाती है। पीसी-32 (पुलिस का वाहन) पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी सुविधानुसार थाने से रायफल लाने-ले जाने के बजाय इसका प्रयोग करते हैं। ड्यूटी खत्म होने पर वापस कमरे में रख देते हैं। वह रायफल कमरे में नहीं दिखी तो उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर उन्होंने थाने में रायफल चोरी होने की तहरीर दी। जिसके आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

> 10वीं के छात्र ने पुलिस चौकी से रायफल चुराई थी। उसे गिरफ्तार कर रायफल बरामद कर ली गई है। जांच रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है।
>
> –ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय, गाजियाबाद।

ताला खोलकर चुराई रायफल : रायफल चोरी होने से अफरातफरी मच गई। पुलिस ने जांच शुरू की और चौकी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उसमें एक युवक स्कूटी पर तौलिया में बंदूकनुमा सामान लपेटकर जाता दिखा। उस पर शक हुआ। पुलिस स्कूटी नंबर के आधार पर उसके घर पसौंडा पहुंची। युवक से पूछताछ की तो उसने खुद का नाम आरिश बताते हुए रायफल चुराने की बात कबूल की। उसके घर से रायफल बरामद हो गई। उसके पिता जाहिद कैब चालक हैं।

पहले चुराई थी चाबी : पुलिस की पूछताछ में अरिश ने बताया कि वह 10वीं का छात्र है। उसने इंटरनेट मीडिया पर तमाम लोगों का बंदूक के साथ वीडियो और फोटो देखा। इस पर उसे भी फायरिंग करने का मन हुआ। इस बीच उसका स्थानीय लोगों के साथ चौकी पर आन-जाना हुआ। उसने चौकी में स्थित कमरे में रायफल देखी। मौका पाकर उसने उस कमरे की चाबी चुरा ली। चौकी के पुलिसकर्मी जब क्षेत्र में निकले तो उसने ताला खोलकर रायफल चुरा ली।

यह है नियम : पुलिस चौकी के नाम आवंटित रायफल जब तक किसी पुलिसकर्मी के सिपुर्द नहीं की जाती, तब तक उसकी जिम्मेदारी संबंधित चौकी प्रभारी पर रहती है। जब कोई पुलिसकर्मी उसे लेकर ड्यूटी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। रायफल ले जाते और जमा करते वक्त का विवरण दर्ज होता है। इस मामले में पुलिस यह नहीं बता रही है कि कागजों में उस समय रायफल किसकी जिम्मेदारी पर थी। उल्लेखनीय है कि पुलिस चौकी में मालखाना नहीं होता है।

बड़ा कदम

दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से बंगबंधु चेयर स्थापित

डीयू में होगा बांग्लादेश की कला–संस्कृति पर शोध

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर गए थे। जहां दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना की घोषणा की गई थी। संयुक्त वक्तव्य के चंद महीने के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना हो गई। सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) ने चेयर की स्थापना के बाबत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह चेयर भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का हिस्सा है। चेयर के जरिए भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत को और आगे बढ़ाया जाएगा।

आइसीसीआर के महानिदेशक दिनेश पटनायक ने कहा कि इस साल हम बांग्लादेश की स्वतंत्रता और राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मना रहे हों। ऐसे में बंगबंधु चेयर का महत्व बढ़ जाता है। यह हमारे लिए काफी खास है।



दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते डीयू के कार्यवाहक कुलपति प्रो पीसी जोशी (दाएं), बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद इमरान (दाएं से दूसरे),भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक दिनेश पटनायक (बाएं) व अध्यक्ष डा विनय सहस्त्रबुद्धे (बाएं से दूसरे)। सौ. आइसीसीआर

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का पत्र पढ़कर सुनाया गया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से नई जमीन तैयार होगी जो भारतीय शिक्षाविदों के बीच बांग्लादेश से संबंधित ज्ञान और सद्भावना बढ़ाने में मदद करेगी।

डीयू कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी ने कहा कि बंगबंधु चेयर की स्थापना के लिए डीयू का चयन गर्व की बात है। वह हम सभी के लिए एक आदर्श नायक थे और स्वतंत्रता, लोकतंत्र व स्वतंत्रता के प्रतीक थे।

शोध को बढ़ावा : कला संस्कृति, इतिहास, आधुनिक भारतीय भाषाएं, संगीत, फाइन आर्ट, राजनीति, विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति, शोध आदि के क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश से जुड़े सेमिनार, कांफ्रेंस आयोजित किए जाएंगे।

निजी स्कूलों की फीस पर कोर्ट ने सभी पक्षकारों से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त करने के एकल पीठ के फैसले को दी गई है चुनौती

निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक व विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत सभी पक्षकारों को लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसके साथ ही सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

एकल पीठ के इस फैसले को दिल्ली सरकार, एक गैर-सरकारी संगठन जस्टिस फार आल व कुछ छात्रों ने चुनौती दी है। सात जून को अवकाशकालीन पीठ ने 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि एकल पीठ के फैसले से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आकलन के अनुसार स्कूलों की तरफ से ली जा रही 60 फीसद ट्यूशन फीस शिक्षकों के वेतन और खर्च के लिए पर्याप्त है। 31 मई को न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए कहा था कि सरकार के इस आदेश से स्कूलों का कामकाज प्रभावित होगा। पीठ ने अनुमति दी थी कि 15 फीसद की छूट देते हुए निजी स्कूल छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 का वार्षिक व विकास शुल्क वसूल सकते हैं। अदालत ने शिक्षा निदेशालय के 18 अप्रैल, 2020 और 28 अगस्त, 2020 को जारी दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया था।

अफगानिस्तान में भारत की 500 परियोजनाएं खतरे में

बढ़ रहा संकट ▸ अरबों डालर के खर्च से चल रहीं ये छोटी-बड़ी परियोजनाएं अफगानिस्तान के विकास की धुरी बनीं

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

▸ लंबे हितों को ध्यान में रखकर तैयार हो रही परियोजनाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता

पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान की बढ़ती ताकत के संकेत के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल उन परियोजनाओं को सुरक्षित रखने की है, जिसे लगाने में उसने न सिर्फ अरबों डालर खर्च किए हैं, बल्कि जिनके साथ उसके रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से तकरीबन 500 छोटी-बड़ी परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उन पर काम जारी है। तीन अरब डालर के निवेश वाली इन परियोजनाओं में अफगानिस्तान के ग्रामीण व दूरदराज के हिस्सों में न सिर्फ बिजली पहुंचाई जा रही है, बल्कि भारत की तरफ से निर्मित सड़कों और पुलों की वजह से वहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। भारत को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से उसकी परियोजनाओं को उसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है जैसे वर्ष 1996-2001 में पहुंचाया गया था। तब तालिबान ने भारत की तरफ से बनाए गए बच्चों के अस्पताल तक को भी नहीं बख्शा था।

तालिबान के आने से वहां चलाई जा रही कुछ अहम परियोजनाओं का भविष्य भी अधर में लटक सकता है। इनमें सबसे अहम परियोजना ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के देलारम तक की सड़क परियोजना है। 218 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पूरी तरह से भारत की मदद से हो रहा है जो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को सीधे चाबहार बंदरगाह से जोड़ेगी। इसके अलावा पूरे काबुल को पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली शहतूत डैम परियोजना का काम भी लटक सकता है। भारत पहले ही सलमा डैम का निर्माण कर चुका है जिससे 42 मेगावाट बिजली बनती है और 75 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। पूर्व में तालिबान ने भारत की मदद से निर्मित बच्चों के जिस अस्पताल को धवस्त किया था, भारत ने उसे फिर से एक बड़े चिकित्सा केंद्र के तौर पर बनवा दिया है। इसके अलावा भारत की मदद से कई पावर ट्रांसमिशन स्टेशन, स्माल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इन सारी परियोजनाओं को भारत ने अफगानिस्तान की जनता की दशा सुधारने के लिए शुरू किया था। इनमें से कुछ का काम अभी अधूरा है। कुछ परियोजनाओं को भारत के लंबे रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनका भविष्य इस बात से तय होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान कितना शक्तिशाली साबित होता है।



अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से कई परियोजनाओं पर चल रहा है काम। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अब एससीओ बैठक पर सभी की नजरें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच अब सभी की नजरें मंगलवार और बुधवार को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक पर टिकी हुई हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, चीन के विदेश मंत्री वांग ई, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत अफगानिस्तान के कुछ दूसरे पड़ोसी देशों के विदेश मंत्री भी होंगे। इस मंच पर 14 जुलाई, 2021 को अफगानिस्तान को लेकर एक विशेष बैठक होने वाली है। उस बैठक में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। एससीओ के सारे सदस्य देश सीधे या परोक्ष तौर पर अफगानिस्तान के बदल रहे हालात से जुड़े हुए हैं और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद माना जा रहा है कि अब एससीओ के देशों की भूमिका बढ़ गई है। एससीओ अफगानिस्तान को लेकर कितना प्रभावशाली साबित होता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन और रूस क्या रवैया अख्तियार करते हैं।

उधर, अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि कंधार स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से भारतीय कर्मचारियों को वापस भेजने का काम चल रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास की रक्षा अफगानिस्तान के कमांडो कर रहे हैं। इसके बावजूद कंधार से जो सूचना पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने सोमवार को भेजी है उसके मुताबिक वहां तालिबान और अफगानिस्तानी सेना के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। कंधार के अलावा हेरात, हिलमंद, बदक्शान, गजनी, फरयाब समेत 11 प्रांतों में तालिबान की तरफ से प्रांतीय सरकारों के ढांचे को खत्म करने की कोशिश जारी है। कंधार के बाद मजार-ए-शरीफ के पास भी तालिबान की पकड़ बढ़ रही है और संभवतः जल्द ही वहां के भारतीय मिशन को लेकर भी फैसला करना पड़ सकता है। बहरहाल, काबुल स्थित भारतीय दूतावास पूरे हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। नई दिल्ली को लगातार पूरे देश में बदल रहे हालात की पल-पल की जानकारी दी जा रही है।

सनद रहे कि तालिबान का दावा है कि उसने 421 जिलों में से 85 फीसद जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि तालिबान अभी देश के एक तिहाई हिस्से पर ही काबिज हुआ है।

लोकपाल को अप्रैल-जून के बीच भ्रष्टाचार की 12 शिकायतें मिलीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकपाल के पास इस वर्ष अप्रैल-जून के बीच भ्रष्टाचार की 12 शिकायतें आईं, जिनमें से आठ शिकायतें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ थीं। हालिया आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल को कम से कम 110 शिकायतें मिलीं, जिनमें से चार सांसदों के खिलाफ थीं। हालांकि, यह संख्या 2019-20 में प्राप्त 1,427 शिकायतों के मुकाबले करीब 92 फीसद कम थी।

लोकपाल के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में प्राप्त 12 शिकायतों में से आठ समूह ए अथवा बी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ थीं। इसके मुताबिक, दो शिकायतों को शुरुआती जांच के बाद बंद कर दिया गया, जबकि तीन शिकायतों में अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास जांच लंबित है। वहीं, एक शिकायत में सीबीआइ से स्थिति रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। भ्रष्टाचार-रोधी कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा, 'दो साल से अधिक समय से लोकपाल कार्य कर रहा है। लोकपाल को उसके द्वारा प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों से संबंधित अभियोजन का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।'

जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता पर लाए जाएंगे निजी बिल

मानसून सत्र ▸ रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण व किरोड़ी लाल समान नागरिक संहिता पर 24 को पेश करेंगे बिल

राकेश सिन्हा ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल के लिए रास में दे रखा है नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के आगामी मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर भाजपा के सांसद निजी सदस्यों के विधेयक पेश करेंगे। गोरखपुर से भाजपा के लोकसभा सदस्य रवि किशन और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के पहले सप्ताह में क्रमशः जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर निजी सदस्यों के विधेयक पेश करने वाले हैं।

एक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी सदस्य के बिल के रूप में जाना जाता है। सरकार के समर्थन के बिना इसके कानून बनने की संभावना बहुत कम होती है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार, रवि किशन और मीणा को 24 जुलाई को अपने-अपने निजी सदस्य बिल पेश करने का अवसर मिलेगा, जो लाटरी प्रणाली के माध्यम से तय किया गया था। राज्यसभा में भाजपा के सदस्य राकेश सिन्हा ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर इसी तरह के बिल के लिए नोटिस दे रखा है। जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित कानून दो से अधिक बच्चों वाले जोड़ों को सरकारी नौकरियों के लिए अपात्र बनाकर और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और सामानों पर सब्सिडी देने पर जोर देते हैं। विधेयक के बारे में सिन्हा ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि देश के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है यह कदम उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक डालने के बाद आया है, जिसमें जनता से 19 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने या किसी भी तरह की सब्सिडी प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।



संसद के मानसून सत्र के पहले सोमवार को तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रेट्र

मसौदे से हटाया जाए एक बच्चे का नियम : विहिप

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उप्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे से एक बच्चे की नीति हटाने का सुझाव दिया है। विहिप का मानना है कि इससे विभिन्न समुदायों के बीच जनसंख्या असंतुलन और बढ़ने की संभावना है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (यूपीएससीएल) को पत्र लिखकर कहा कि विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह विधेयक अन्य बातों के साथ जनसंख्या को स्थिर करने के साथ दो बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए है। विहिप दोनों उद्देश्यों से सहमत है। उन्होंने कहा कि बिल की धारा 5, 6 (2) और 7 जो लोक सेवकों और अन्य लोगों को परिवार में केवल एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है यह उक्त उद्देश्यों से बहुत आगे की बात है। इसलिए, हम जनसंख्या के संकुचन के साथ-साथ एक बच्चे की नीति के अवांछनीय सामाजिक और आर्थिक परिणामों से बचने के लिए धारा 5, और परिणामी धारा 6 (2) और 7 को हटाने का सुझाव देते हैं।

दोनों सदनों के 600 से अधिक सदस्यों को लग चुका है टीका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अधिकांश सांसदों को कोरोना रोधी टीका लगने के बावजूद संसद के मानसून सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन अपरिहार्य होगा। हालांकि, टीके की एक डोज लेने वाले सांसदों को सदन की बैठक में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। लोकसभा के 411 से अधिक सदस्यों ने टीका लगवा लिया है। इनमें 323 सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं, जबकि राज्यसभा के 205 सदस्यों ने दोनों डोज ले ली हैं। वहीं, लोस के बाकी बचे सदस्यों के अलावा रास के छह सदस्य स्वास्थ्य वजहों से अभी तक टीका नहीं लगवा पाए हैं।

▸ कोरोना प्रोटोकाल के साथ संसद के मानसून सत्र की तैयारी हुई पूरी

▸ लोकसभा के 323 व राज्यसभा के 205 सदस्य लगवा चुके हैं दोनों डोज

मानसून सत्र में कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन होगा मगर संसद के दोनों सदनों की बैठकें एक ही समय अपने-अपने सदनों में चलेंगी। सदस्यों के बैठने में शारीरिक दूरी के नियम का पालन होगा। लोकसभा कक्ष में 280 सदस्य, जबकि उसकी अलग-अलग गैलरियों में 259 सदस्य बैठेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी होने की जानकारी देते हुए कहा कि जिन्होंने कोरोना टीके की एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें संसद भवन में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलेगा।

विपक्ष को लामबंद रखने के लिए जुटी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▸ पेट्रोल-डीजल की महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर के कहर, राफेल सौदे की जेपीसी जांच को लेकर होगी जंग

संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, राज्यों के अधिकार पर प्रहार से लेकर राफेल सौदे की जांच जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इन मुद्दों की फेहरिस्त के साथ सत्र के दौरान सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों से मशविरा शुरू कर दिया है।

नवगठित सहकारिता मंत्रालय के पीछे छिपी सियासत, बेकाबू महंगाई से लेकर राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच जैसे विषयों पर विपक्ष की आवाज मजबूती से रखने के लिए कांग्रेस संसद में विपक्ष की संयुक्त रणनीति को जरूरी मान रही है। इसीलिए वामदलों और तृणमूल कांग्रेस के अलावा शिवसेना ही नहीं समाजवादी पार्टी से भी साझी रणनीति को लेकर बातचीत चल रही है, ताकि संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को गोलबंद किया जा सके। मानसून सत्र के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ साझी रणनीति बनाने के प्रयासों में जुटे कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि भले ही विपक्षी दलों की आधिकारिक बैठक सप्ताहांत में होगी मगर अनौपचारिक संवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। मालूम हो कि बीते कई सत्रों के दौरान विपक्षी गोलबंदी के कांग्रेस ने काफी प्रयास किए, मगर एक दो मुद्दों के अलावा एकजुटता का प्रयास लंबा नहीं चल पाया।

महंगाई और सहकारिता मंत्रालय के गठन में छिपी सियासत के मुद्दे पर इस बार विपक्षी खेमे के अधिकांश दल एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला द्वारा जाहिर की गई आशंका के बाद इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में सियासी गहमागहमी काफी बढ़ गई है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को सहकारिता मंत्रालय के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृहमंत्री का इस महकमे के मंत्री के रूप में कामकाज संभालना संविधान के संघीय स्वरूप पर हमला है।

सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित कर इसके जरिये भाजपा द्वारा चुनावी लाभ लेने से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं, राफेल सौदे पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इसकी जांच कराने की कांग्रेस की मांग का अभी तक वामदलों ने ही समर्थन किया है। दूसरे दलों ने इस पर अभी अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की है। नए कृषि कानून निरस्त करने की मांग का अधिकतर विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राकांपा प्रमुख शरद पवार के हालिया बयान कि कृषि कानूनों को पूरी तरह निरस्त करना उचित नहीं होगा, कांग्रेस की चिंता का कारण है। पवार का रुख सदन में सरकार के लिए मददगार साबित हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एमडीएस की काउंसिलिंग में देरी का लिया संज्ञान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एमडीएस दाखिले के लिए काउंसिलिंग आयोजित करने में देरी पर संज्ञान लिया, जिसके लिए परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और अन्य पक्ष एक साल से 'टाल-मटोल' कर रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में कहा, 'ये योग्य बीडीएस छात्र हैं। आपने पिछले साल से काउंसिलिंग क्यों नहीं आयोजित की? क्या भारत को होने वाले नुकसान की कल्पना कर सकते हैं? आप काउंसिलिंग न कराकर उन्हें डिग्री लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। एक साल से टाल-मटोल कर रहे हैं। हमें एक हफ्ते के भीतर बताएं कि आप इसे रोके हुए क्यों हुए हैं।'

'आइटी नियम पढ़कर पूरी तैयारी से आएं, तब सुनेंगे'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सुप्रीम कोर्ट ने वकील की याचिका पर एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाली

▸ इंटरनेट मीडिया पर इस्लामोफोबिया को लेकर दायर की गई है याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर नफरत फैलाने वाले और इस्लामोफोबिया के संदेशों पर रोक और कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह टालते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह नए आइटी नियमों को पढ़कर पूरी तैयारी से आएं, तब मामले पर सुनवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई टालते हुए ये टिप्पणी प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

कोर्ट ने याचिका पर स्वयं बहस कर रहे याचिकाकर्ता वकील ख्वाजा अइजाजुद्दीन से कहा कि क्या आपने नए आइटी नियम पढ़े हैं। आप जो मांग कर रहे हैं उसमें ये चीज है। वकील ने कहा कि नए आइटी नियमों में इस चीज को कवर नहीं किया गया है जिसकी वह मांग कर रहा है। नए आइटी रूल में धर्म (रिलीजन) के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जस्टिस रमना ने कहा आइटी रूल दिखाइए कहां है। वकील ने कहा कि नए आइटी रूल को फाइल में नहीं लगाया है। कोर्ट का अगला सवाल था कि क्या आप अपनी मांग के बारे में सरकार के पास गए थे। वकील ने कहा नहीं। इस पर पीठ ने कहा कि तो फिर आपकी इस याचिका पर कोर्ट क्यों सुनवाई करे। वैसे भी तब्लीगी जमात के मामले में पहले से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट मे लंबित है तो फिर इस नई याचिका पर क्यों सुनवाई की जाए। वकील ने कहा कि उस लंबित मामले में तबलीगी जमात के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग का मुद्दा है, जबकि उनकी याचिका उससे भिन्न है। वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनकी याचिका पर नोटिस जारी कर दिया जाए और इसे भी तब्लीगी जमात के मामले में दाखिल याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न कर दिया जाए, लेकिन पीठ इसके लिए राजी नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि आप पूरी तैयारी के साथ होमवर्क करके और आइटी नियम पढ़ कर आइएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। याचिका में पिछले वर्ष दिल्ली में फैले कोरोना के पीछे तब्लीगी जमात को जिम्मेदार ठहराए जाने का मुद्दा उठाया गया है। इंटरनेट मीडिया पर नफरत फैलाने वाले और इस्लामोफोबिया के संदेश पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग की गई है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कोर्ट ने किसी याचिकाकर्ता से पूरी तैयारी से आने की बात कही हो। इससे पहले भी कई बार कई मामलों में आधी अधूरी जानकारी और तैयारी से याचिका दाखिल करने वालों को कोर्ट इस तरह की नसीहत दे चुका है।

यूजरनेम बदलने पर कुछ समय के लिए हटा ट्विटर पर नए आइटी राज्यमंत्री का 'ब्लू बैज'

नई दिल्ली, प्रेट्र : इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा ट्विटर पर अपना यूजरनेम बदलने से सोमवार को उनके ट्विटर हैंडल को सत्यापित करने वाला ब्लू बैज कुछ समय के लिए हट गया। हालांकि, यह कुछ समय बाद बहाल हो गया।

राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को ट्विटर पर अपना यूजरनेम 'राजीव एमपी' से बदलकर 'राजीव जीओआइ' कर लिया था। ट्विटर की सत्यापन नीति के मुताबिक, अगर कोई अकाउंट होल्डर अपना यूजरनेम बदलता है तो ट्विटर उसके अकाउंट से ब्लू बैज स्वतः हटा सकता है। ट्विटर ने कहा कि वह मंत्री के कार्यालय के साथ संपर्क में था और ब्लू बैज बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रहा था। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब नए इंटरनेट मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर का सरकार के साथ टकराव जारी है। राज्यमंत्री के अकाउंट से थोड़े समय के लिए ब्लू बैज हटाने के लिए कुछ यूजर्स ने ट्विटर की तीखी आलोचना की।

याद दिला दें कि ट्विटर ने पिछले महीने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के निजी अकाउंट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी कुछ समय के लिए ब्लू बैज हटा दिया था। तब उसका कहना था कि नियमों के मुताबिक अकाउंट के अपूर्ण होने या छह महीने निष्क्रिय रहने पर ब्लू बैज स्वतः हट सकता है।

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआइ) का दौरा किया और कहा कि देश के इतिहास को संरक्षित करना एक 'प्रतिबद्धता' है, न कि केवल एक नौकरी।

संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ रेड्डी ने एनएआइ में रिकार्ड प्रबंधन, संरक्षण और डिजिटलीकरण गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अनुसंधान कक्ष, पुराने भंडार, संरक्षण कक्ष और एनएआइ की पुरानी इमारत का दौरा किया और कहा कि उन्हें भारत के गैर-वर्तमान अभिलेखों के सबसे समृद्ध और उत्तम संग्रहों में से एक को संभालने का अवसर मिला है जो देश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का प्रमाण है।

बदलाव

गृह मंत्री ने नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोजिक सब्सटेंसेज डिटेक्शन सेंटर का किया उद्घाटन

फारेंसिक साइंस से पुलिस तत्काल कर सकेगी जांच : शाह

जागरण संवाददाता, गांधीनगर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपराधों की जांच में पुलिस की थर्ड डिग्री के दिन गए, पुलिसकर्मी अब फारेंसिक साइंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर त्वरित जांच कर सकेंगे। छह साल से अधिक सजा के मामलों में फारेंसिक जांच अनिवार्य होनी चाहिए। शाह ने कहा कि देश के हर जिले में नारकोटिक्स लैब सेंटर खोला जाएगा। केंद्र सरकार देश को नशा एवं मादक पदार्थ से मुक्त बनाना चाहती है।

गृह मंत्री शाह ने सोमवार को गांधीनगर में नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोजिक सब्सटेंसेज डिटेक्शन सेंटर के उद्घाटन के बाद कहा कि भारतीय दंड संहिता आइपीसी एवं कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में बड़े बदलाव की जरूरत है। हर जिले में फोरेंसिक मोबाइल वैन होनी चाहिए। जज, वकील, पुलिस अधिकारी तथा विशेषज्ञों से चर्चा कर देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। पुलिस की थर्ड डिग्री जांच के दिन अब चले गये हैं। अपराधी को फोरेंसिक साइंस व आधुनिक तकनीक से जांच करके भी तोड़ा जा सकता है।

शाह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे यहां गृह मंत्री थे। अब वे प्रधानमंत्री हैं और मैं देश का गृह मंत्री हूं। फारेंसिक साइंस लैब की स्थापना के वक्त जो सपना देखा था आज वह पूरा हुआ। नेशलन फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने कम समय में विश्व स्तरीय फारेंसिक जांच एवं प्रशिक्षण का स्तर प्राप्त कर लिया है। दुनिया भर के छात्र अब यहां नारको एनालिसिस, साइबर क्राइम व क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन सीखने आएंगे। देश के सात राज्य अपने यहां फारेंसिक साइंस कालेज खोलने की इच्छा जता चुके हैं।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए साइबर क्राइम पर लगाम कसना जरूरी है। फारेंसिक साइंस एवं नारको एनालिसिस सेंटर के जरिये पुलिस जांच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलेगा। इससे जांच में तेजी आएगी और पुलिस का काम आसान होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अपराध के वैज्ञानिक परीक्षण के साथ उस पर नियंत्रण भी आसान होगा। ड्रग्स माफिया की पहचान आसान होगी। कार्यक्रम में गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी मौजूद रहे।

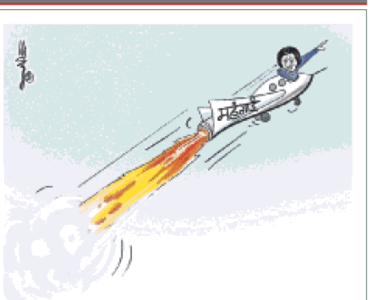
गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा के मौके पर मंदिर पहुंचे और मंत्रोच्चार के साथ आरती की। इसके साथ उन्होंने ट्वीट किया, जगन्नाथ रथयात्रा के शुभ अवसर पर मैं अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में कई वर्षों से मंगला आरती में भाग लेता आ रहा हूं और हर बार यहां एक अलग ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज भी महाप्रभु की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर सदैव अपनी कृपा व आशीष बनाए रखें। प्रेट्र



अहमदाबाद में रिकार्ड टीकाकरण

इससे पहले शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 250 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्मार्ट क्लास रूम, वाचनालय, सिविक सेंटर के उद्घाटन और नारदीपुर गांव में 12 एकड़ में फैली झील के सुंदरीकरण कार्य की उन्होंने शुरुआत की। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते जो विकास कार्य किए, विकास की वही गति अविरल जारी है। वहीं, वह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर गए और मंगला आरती में भाग लिया।

कह के रहेंगे माधव जोशी



60 से अधिक सीटें आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में हासिल करने का लक्ष्य तय किया है प्रदेश भाजपा ने। इसके लिए सभी पदाधिकारी महीने में 10 दिन प्रवास करेंगे। यह कार्यक्रम दो महीने तक सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 13 जुलाई, 2021

संघ ने बंगाल में संगठन को लेकर किया बड़ा बदलाव

बंगाल को दक्षिण, मध्य और उत्तर प्रांत में बांटा, अब तक था एक प्रांत

कोलकाता व बर्द्धमान संग सिलीगुड़ी होंगे प्रांतों के मुख्यालय

राजीव द्विवेदी, चित्रकूट

बंगाल को बांटने की थ्योरी को मिला बल

विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से बंगाल में हो रही हिंसा के बाद वहां के राज्यपाल के रुख और केंद्रीय जांच टीमों की रिपोर्ट आने के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि केंद्र बंगाल को तीन भागों में बांट सकता है। सियासी हलकों में एक थ्योरी उत्तर, दक्षिण और मध्य में बांटने की थी तो दूसरी थ्योरी फिर तीन टुकड़े करके उनको ओडिशा, असम और बिहार से जोड़ने की। सियासी अटकलों के बीच संघ ने संगठनात्मक तौर पर बंगाल को तीन भागों में बांटकर इस विचार को बल दे दिया है।

चित्रकूट में प्रांत प्रचारक बैठक के तीसरे दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दो सह सरकार्यवाह के दायित्वों में परिवर्तन के साथ ही लगाए जा रहे कयास सच साबित हुए। बैठक के अंतिम दिन संघ ने बंगाल को लेकर बड़ा फैसला किया। संगठनात्मक दृष्टि से जिस बंगाल में संघ का एक प्रांत था, उसको तीन भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व क्षेत्र जिसमें बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान प्रांत शामिल हैं, वहां के क्षेत्र प्रचारक रहे प्रदीप जोशी को अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख का दायित्व देने का फैसला किया जा चुका है। बैठक के अंतिम दिन पूर्व क्षेत्र के सह क्षेत्र प्रचारक रमापदो पाल को क्षेत्र प्रचारक बना दिया गया। दक्षिण बंगाल के प्रांत प्रचारक रहे जलधर महतो को अब सह क्षेत्र प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है तो सह प्रांत प्रचारक प्रशांत भट्ट को दक्षिण बंगाल का प्रांत प्रचारक बनाया गया है।

संघ में परंपरा रही है कि शिक्षा वर्ग होने के बाद प्रतिनिधि सभा में प्रचारकों की प्रोन्नति और जिम्मेदारियों को तय किया जाता है, लेकिन इस बार बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के कारण वहां कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। संगठनात्मक तौर पर एक प्रांत रहे बंगाल को अब संघ ने कार्य की दृष्टि से दक्षिण, मध्य और उत्तर प्रांतों में विभाजित कर दिया है। दक्षिण बंगाल का मुख्यालय कोलकाता तो मध्य बंगाल का बर्द्धमान में होगा। वहीं, उत्तर बंगाल का मुख्यालय सिलीगुड़ी को बनाया गया है।

बंगाल पर अब संघ का खास फोकस : हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम से संतुष्ट संघ अब बंगाल में अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएगा। बंगाल को तीन प्रांत में बांट कर साफ संदेश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य पर खास फोकस है। प्रांत बढ़ाने के साथ ही बंगाल में संगठन को गांव-गांव पहुंचाने के पीछे की वजह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ व खास वर्ग की आबादी का असंतुलन भी है।

भय्या जी जोशी विहिप व कृष्ण गोपाल होंगे विद्या भारती के संपर्क अधिकारी : पूर्व सरकार्यवाह और कार्यकारिणी के सदस्य भय्या जी जोशी अब संघ की ओर से विश्व हिंदू परिषद के संपर्क अधिकारी होंगे। वहीं, डा. कृष्ण गोपाल विद्या भारती के संपर्क अधिकारी बनाए गए हैं। भय्या जी जोशी पहले भी सरकार्यवाह रहते हुए विहिप का काम देखते रहे थे।

अनुषंगिक संगठनों के कामों पर निगरानी रखने के लिए संघ की ओर से कार्यकारिणी अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाया जाता है। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार को बैठक के तीसरे दिन ही भाजपा और संघ के बीच समन्वय रखने का दायित्व सौंपा जा चुका है। वहीं, पूर्व क्षेत्र प्रचारक से सह संपर्क प्रमुख बनाए गए प्रदीप जोशी का केंद्र चंडीगढ़ होगा।

संघ भी बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरहद के बीच फंसी प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट की मुक्ति के लिए संघ भी मुखर हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के अंतिम दिन चित्रकूट विकास को लेकर चर्चा हुई। संघ ने बुंदेलखंड राज्य बनाने का समर्थन किया और चित्रकूट को उसकी राजधानी बनाने पर जोर दिया।

यहां शुरू हुई बैठक से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात की थी। इसमें जगद्गुरु ने चित्रकूट के विकास को लेकर चर्चा की थी। संघ प्रमुख से कहा था कि उप्र और मप्र की सीमा में चित्रकूट के बसे होने से विकास नहीं हो रहा है। इसको किसी एक प्रदेश में शामिल कर दिया जाए या बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो। नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। जगद्गुरु की इन बातों पर सोमवार को संघ की बैठक में गहनता से चर्चा हुई। क्षेत्र व प्रांत प्रचारकों ने सीमा बंधन में छटपटा रहे चित्रकूट को मुक्त करने की बात उठाई। सबसे पहले बुंदेलखंड राज्य का निर्माण कर चित्रकूट को राजधानी बनाने का प्रस्ताव आया। दूसरी ओर केंद्र शासित राज्य बनाने की बात उठी।

सख्त जनसंख्या कानून बनाए सरकार



चित्रकूट में सोमवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (बाएं) ने आरोग्यधाम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस दौरान तुलसीपीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामदास (बीच में) भी मौजूद रहे। सौ. तुलसी पीठ

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

उप्र सरकार जनसंख्या कानून को सख्त बनाए। हर नागरिक के लिए इसे मानने की बाध्यता भी हो। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने उनसे नई जनसंख्या नीति पर चर्चा की। इसके बाद वह संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले। चर्चा में कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून का प्रभाव अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ेगा। संतों की ओर से सरकार की नई जनसंख्या नीति का स्वागत और समर्थन है। जनसंख्या विस्फोट को लेकर दोनों संतों ने गहरी चिंता भी जाहिर की। नई जनसंख्या नीति का मुस्लिम धर्मगुरुओं के विरोध को लेकर महंत नरेंद्र गिरि ने ऐतराज जताया है।

अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में आए संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्रदास ने चर्चा की।

अनुषंगिक संगठनों को शाखाओं के विस्तार की नसीहत

जासं, चित्रकूट : प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में चार दिनों से चल रही अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक के अंतिम दिन विविध संगठनों के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उनको शाखाओं के विस्तार और कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर बचाव के कार्य में जुटने को कहा। कुछ अनुषंगिक संगठनों के संगठन मंत्रियों के कामकाज पर नाराजगी भी जताई गई।

संघ प्रमुख व सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अनुषंगिक संगठनों द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में किए गए सेवा कार्यों की समीक्षा की। फिर से शुरू हुई संघ की 27,166 शाखाएं नियमित रखने के लिए प्रयास करने को कहा। कोरोना से बचाव के लिए बनने वाली गांव टोलियों के ढाई लाख स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और सितंबर में चलने वाले जन जागरण कार्यक्रम में संगठनों को अपनी भूमिका तय करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी, विद्या भारती, सेवा भारती, वनवासी सेवा आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारत विकास परिषद, लघु उद्योग भारती व हिंदू जागरण मंच जैसे राष्ट्रीय संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों ने भाग लिया। कई संगठन मंत्रियों को लेकर आ रही शिकायतों पर बैठक में राष्ट्रीय टोली के अधिकारियों ने नाराजगी जताई।

रजनीकांत ने रजनी मक्कल मंद्रम किया भंग

चेन्नई (तमिलनाडु), एएनआइ : फिल्म स्टार रजनीकांत ने सोमवार को 'रजनी मक्कल मंद्रम' (आरएमएम) को भंग कर दिया। इसका गठन उन्होंने राजनीति में अपने प्रवेश के लिए किया था। उन्होंने कहा कि अब उनकी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है।

चेन्नई कोडम्बक्कम रागावेंद्र हाल में 'रजनी मक्कल मंद्रम' के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद रजनीकांत ने उक्त घोषणा की। उन्होंने बयान में कहा, 'मैं सभी रजनी मक्कल मंद्रम पदाधिकारियों व प्रशंसकों का धन्यवाद करता हूं। राजनीति में प्रवेश नहीं करने के मेरे फैसले के बाद रजनी मक्कल मंद्रम के बारे में सवाल उठ रहे थे और इस बारे में स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है।' उन्होंने आगे कहा कि रजनी मक्कल मंद्रम के पदाधिकारी रजनीकांत फैन क्लब एसोसिएशन का हिस्सा बने रहेंगे जो जनसेवा का काम करेगी। उन्होंने कहा, 'परिस्थितियों के कारण हमने जो सोचा था, उसे हासिल नहीं कर पाए। भविष्य में मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए मैंने रजनी मक्कल मंद्रम को भंग करने का फैसला किया।'

जनता चुनेगी जिपं अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पहल के लिए तैयार भाजपा सरकार, पंचायत चुनाव से खत्म होगा बाहुबल
- उपमुख्यमंत्री मौर्य की बात का स्पष्ट संदेश, केंद्र सरकार बदलेगी चुनाव व्यवस्था

धनबल-बाहुबल और अराजकता से घिरे नजर आने वाले पंचायत चुनावों से अब शायद यह दाग-धब्बे साफ हो जाएं। भाजपा सरकार संविधान संशोधन कराते हुए यह व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रही है कि महापौर और पार्षदों की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख सीधे जनता के वोट से चुने जाएं। स्पष्ट संकेत हैं कि योगी सरकार के इन प्रयासों पर केंद्र सरकार अन्य राज्यों की सहमति लेकर अगले चुनाव तक प्रक्रिया बदल दे।

हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं। तमाम जिले और ब्लाक में हिंसा की घटनाएं सामने आईं। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख का जनता के वोट के बजाए जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वोट से होता है, इसलिए यह चुनाव धनबल-बाहुबल के आरोप में हमेशा घिरे रहते हैं। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर जीरो टालरेंस का संदेश देने वाली भाजपा सरकार चाहती है कि नगर निकाय में महापौर और पार्षदों की तरह ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख भी जनता के वोट से चुने जाएं। अंदरखाने शुरू हुए इन प्रयासों का संदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान से मिला है। सोमवार को प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में यह इशारा कर चुके केशव ने 'जागरण' से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वह पंचायत चुनाव की व्यवस्था में यह बदलाव कराने का पुरजोर प्रयास करेंगे, ताकि अगला चुनाव पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हो। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों से इस पर सहमति भी लेनी होगी। चूंकि इस समय केंद्र के साथ कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसलिए प्रस्ताव की स्वीकृति में कोई बाधा आने की आशंका नहीं है। आयोग के अफसरों का कहना है कि महापौर-पार्षद की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।

वक्त रहता तो इसी बार हो जाता बदलाव

ऐसी नहीं कि यह सिर्फ उपमुख्यमंत्री मौर्य की सोच या संकल्प है, बल्कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही प्रयास शुरू कर चुकी है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख का चुनाव जनता के वोट द्वारा पारदर्शी ढंग से हो। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार को पहले ही व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। चूंकि, पंचायत चुनाव का निर्धारित वक्त करीब था। प्रक्रिया बदलने से व्यवधान होता, इसलिए इस बार पुरानी प्रक्रिया से चुनाव कराए हैं, लेकिन प्रयास यही है कि अगली बार पंचायत चुनाव होने तक व्यवस्था बदल जाए।

'जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं, महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी'

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाकर काम करना संभव नहीं। जो राज्य इसे करना चाहें करें, लेकिन कानून से यह ठीक तरीके से संभव नहीं हो सकेगा। आंकड़ों के हवाले से मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का काम महिलाओं की शिक्षा से ही संभव है। वैसे भी सन् 2040 के बाद सभी समुदायों की आबादी में गिरावट दर्ज होगी। मालूम हो कि जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबादी पर अंकुश के लिए कानून लाने की बात कही थी। समान नागरिक संहिता के बारे में एक सवाल पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देने से इन्कार कर दिया।

नीतीश कुमार ने कहा कि इस संदर्भ में आप चीन का आकलन कर सकते हैं। वहां पहले एक बच्चे की बात थी, फिर दो बच्चे पर आए और अब क्या स्थिति हो रही है। बकौल नीतीश, हमने यह अध्ययन किया है कि महिलाएं जब पढ़ी-लिखी होती हैं तो उनमें जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता होती है।

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पूछा– मंत्रियों के कितने बच्चे?

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद वायरल वीडियो में बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें वह उप्र सरकार से पूछ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले सरकार बताए कि उसके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं? उनमें कितने वैध हैं और कितने अवैध, फिर हम भी घोषणा करेंगे। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। वह फर्रुखाबाद में दो दिवसीय दौरे पर आए थे। हालांकि दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि खुर्शीद बताएं कि जबरन नसबंदी करने वाली उनकी पार्टी (कांग्रेस) के मंत्रियों ने बच्चों की घोषणा की थी क्या? बढ़ती जनसंख्या पूरे देश व विश्व की समस्या है। 35 वर्ष पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए कांग्रेस ने जबरन नसबंदी कराई थी। लोगों की सेलरी बंद कर दी थी। खुर्शीद को वोट प्रभावित होने का भय है, इसीलिए तिलमिलाए हैं।

'पत्नी चाहे तीन हों, लेकिन बच्चे दो ही हों'

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विश्व जनसंख्या दिवस पर योगी सरकार की ओर से लाई गई नई जनसंख्या नीति का स्वागत और समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि महाराज ने सोमवार को एक बयान में देश और प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल किया बच्चे पैदा करने में अल्लाह की देन क्या है। कहा कि मुस्लिम समाज में भले ही तीन और शादी करने की इजाजत हो, लेकिन बच्चे दो ही हों। उन्होंने मांग की है कि सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसे देश में रहने वाले हर नागरिक को मानना बाध्यकारी हो।

फिर जागा महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद प्रेम

राज्य ब्यूरो, जम्मू

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के दिल में एक फिर आतंकवाद के प्रति प्रेम जागा है। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त क्यों कर दिया? सलाहुद्दीन का एक बेटा कृषि विभाग और दूसरा शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान श्रीनगर में कार्यरत था। तिहाड़ जेल में बंद दोनों भाइयों को 2011 में दर्ज टेरर फंडिंग और हवाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। महबूबा को तकलीफ है कि पिता के कृत्य की सजा बेटों को क्यों दी गई। इसके अलावा महबूबा ने अनुच्छेद-370 की पुनर्बहाली का राग भी फिर से अलापा। उन्होंने दोहराया कि वह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगी, जब तक अनुच्छेद-370 की पुनर्बहाली नहीं होती।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गत सप्ताह ही जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले 11 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया था। इनमें सलाहुद्दीन के दो बेटे भी शामिल हैं। बीते अप्रैल से अब तक राष्ट्रविरोधी व आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर सरकारी सेवा से 17 कर्मियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। महबूबा को सबसे अधिक परेशानी सलाहुद्दीन के बेटों को नौकरी से निकाले जाने से है। बड़े ही भावुक तरीके से उन्होंने कहा कि वह किसी का समर्थन नहीं कर रही हैं, लेकिन पिता के कृत्य के लिए बेटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक आपके पास सुबूत न हो। दरअसल, महबूबा नहीं चाहती कि सरकारी तंत्र में छिपे ऐसे भेड़ियों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व ही उनकी पाकिस्तान परस्ती के एजेंडे में हाथ-पैर बनते हैं।



महबूबा मुफ्ती। फाइल/इंटरनेट मीडिया

जम्मू संभाग को भावनात्मक सियासी जाल में उलझाने का पासा फेंका

जम्मू संभाग के लोगों को अपने भावनात्मक सियासी जाल में उलझाने के मकसद से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने अनुच्छेद-370 को जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान को संरक्षित रखने के लिए लागू किया था। वह चुनावी प्रक्रिया में तब तक भाग नहीं लेंगी, जब तक पांच अगस्त, 2019 को लिए गए फैसलों को वापस नहीं कर दिया जाता।

पीडीपी की नेता ने केंद्र सरकार पर निकाली भड़ास

केंद्र सरकार पर बरसते हुए महबूबा ने आरोप लगाया कि कश्मीरियों को सजा देने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा कि मैं बार-बार कहती हूं कि आप एक व्यक्ति को पकड़ सकते हो, लेकिन उसके विचार को नहीं। आपको विचारों के मुद्दों का समाधान करना है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। द्वेष भावना और राजनीतिक अपराधीकरण से राष्ट्र पीछे जा रहा है। महबूबा ने केंद्र के राष्ट्रप्रेम को नकली तक बोला।

उप्र की चुनावी रणनीति तय करेगी भाजपा प्रदेश कार्यसमिति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बार-बार परखे गए संगठन की मजबूती पर पंचायत चुनाव के परिणामों ने भी मुहर लगा दी है। अब बेहतर रणनीति के साथ भाजपा उप्र विस चुनाव के बड़े इम्तिहान की ओर कदम बढ़ाने जा रही है। रणनीति को अंतिम रूप 16 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दिया जाएगा। इस वर्चुअल बैठक का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। समापन सत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। उससे पहले 15 जुलाई को प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें कार्यसमिति के एजेंडे पर चर्चा होगी।

उप्र में अगले वर्ष होने जा रहे विस चुनाव की तैयारी भाजपा ने तेज कर दी है। पिछले दिनों राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कोर टीम के साथ मैराथन बैठकें कीं। उसमें सरकार की जनहितकारी योजना और संगठन के सेवा कार्यों की समीक्षा के साथ आगे का रोडमैप तैयार किया।

'सीएम व डिप्टी सीएम मुझ पर रख रहे हैं नजर'

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
- बाद में कहा, उन्होंने केंद्र सरकार को लक्ष्य करके दिया था बयान

महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। इसका प्रमाण है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार उन पर नजर रख रही है।

महाराष्ट्र की शिवसेनानीत महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस व राकांपा सहयोगी हैं। शनिवार को लोनावाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटोले ने कहा कि रोज सुबह नौ बजे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को खुफिया रिपोर्ट सौंपी जाती है कि राज्य में क्या हो रहा है। चूंकि कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है, इसलिए उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। हम यहां लोनावाला में हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट उनके पास पहुंच रही है। व्यवस्था हमें शांति से नहीं रहने दे रही है। हमारा फोन टैप हो रहा है। हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाती है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हम पर नजर रख रहे हैं। हालांकि, बाद में पटोले ने एक मराठी चैनल से बात करते हुए कहा, 'मैंने कभी यह नहीं कहा कि राज्य सरकार मुझपर नजर रख रही है। मेरा आरोप केंद्र को लेकर था।' पटोले ने कुछ दिनों पहले पूर्व की भाजपा सरकार पर भी अपना फोन टैप कराने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए राज्य के गृहमंत्री ने एक समिति का गठन भी कर दिया है।

अब पटोले भले ही यह कहें कि उन्होंने केंद्र सरकार को ध्यान में रखकर बयान दिया है, लेकिन उनके बयान में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री का ही उल्लेख है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार पर ही निशाना साधा गया है। वह पहले भी कह चुके हैं कि शिवसेना-राकांपा उनकी पीठ में छुरा भोंक रही हैं। पटोले के इस बयान पर कुछ बोलने से इन्कार करते हुए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार कह चुके हैं कि वे (नाना पटोले) बहुत छोटे लोग हैं। हमें उनपर कोई प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए। यदि सोनिया गांधी कुछ कहेंगी तो हम उसपर प्रतिक्रिया देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में डेढ़ साल से चल रही महाविकास अघाड़ी सरकार पर नाना पटोले के उस बयान के बाद से ही अस्थिरता के बादल मंडराते दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा अगला चुनाव अलग लड़ने की बात कही थी।



नाना पटोले। फाइल/इंटरनेट मीडिया

अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात कर लें पटोले : राकांपा

राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि खुफिया विभाग मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं, श्रमिक नेताओं एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उनके बारे में जानकारी रखता है। यदि किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए तो वह सरकार को लिखकर दे दे। मलिक ने यह भी कहा कि यदि पटोले को ज्यादा जानकारी चाहिए तो उन्हें अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण एवं सुशील कुमार शिंदे से बात कर लेनी चाहिए।

नया विवाद

कैप्टन-सिद्धू विवाद जारी, अब वड़िंग ने मनप्रीत के खिलाफ खोला मोर्चा, वित्त मंत्री की ओर से अकालियों को दी गई ग्रांट पर उठाए सवाल

मनप्रीत से तुरंत इस्तीफा लें राहुल गांधी : वड़िंग

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और गिद्दड़बाहा के कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वड़िंग ने ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मांग की है कि मनप्रीत बादल से तुरंत इस्तीफा ले लिया जाए। वड़िंग ने इंटरनेट मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करके अकालियों को ग्रांट देने के मामले में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। वहीं इसकी शिकायत पार्टी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ से भी की है।

राजा वड़िंग ने इंटरनेट मीडिया पर मनप्रीत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि अकाली दल की मिलीभगत से कांग्रेस में आए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल सरेआम अकाली दल के लोगों को 15-15 लाख के चेक देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

मनप्रीत पर टिप्पणी करते हुए राजा वड़िंग ने लिखा कि यह वही आपके ताया जी के अकाली दल वाले हैं, जिन्हें छोड़कर मंत्री जी आप कांग्रेस में शामिल हुए थे। सब कुछ तो आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया था, फिर क्यों पार्टी की पीठ में छुरा मार रहे हो। याद रखें कांग्रेस में रहकर अकाली दल की स्पोर्ट करना आपके राजनीतिक जीवन को तबाह कर देगा और पंजाबी इसे भूलेंगे नहीं। पिछले चार साल के आपके वित्त मंत्री के तौर पर किए कामों ने पंजाब के हर वर्ग को कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया है। कल ही आपके हलके में हजारों की संख्या में पंजाब के कर्मचारी आपका विरोध करके गए हैं। कांग्रेस को अब आपकी 75-25 वाला खेल समझ आने लगा है।

काबिले गौर है कि इन दोनों नेताओं के बीच यह कोई पहला विवाद नहीं है इससे पहले भी विभिन्न मुद्दों पर दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि मनप्रीत बादल ने अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके रिश्तेदार जयजीत जौहल (जोजो) ने भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया।

जोजो ने कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष अरुण वधावन, सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान, डिप्टी मेयर मास्टर हरमंदर सिंह, पवन मानी के हवाले से कहा कि वह राजा वड़िंग के बयान की निंदा करते हैं। यह पैसा निजी नहीं है बल्कि माडल टाउन फेस चार व पांच के विकास के लिए दिया गया है।

मनप्रीत बादल के कांग्रेस में शामिल होने से पहले दोनों नेताओं में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी थी। क्योंकि मनप्रीत भी गिदड़बाहा से चुनाव लड़ते रहे हैं और 2012 के चुनाव में जब राहुल गांधी ने जिन छह युवा नेताओं को आगे किया था उनमें राजा वड़िंग भी एक थे और उन्होंने तब मनप्रीत बादल को चुनाव में हराया था। मनप्रीत ने यह चुनाव अकाली दल से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी आफ पंजाब बनाकर लड़ा था। जबकि इससे पूर्व मनप्रीत बादल गिद्दड़बाहा से अकाली दल टिकट पर चार बार चुनाव जीते थे। 2017 के चुनाव से पहले मनप्रीत ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। पार्टी ने उन्हें गिद्दड़बाहा सीट के बजाये बठिंडा से टिकट दी थी।

बंगाल भाजपा संगठन में व्यापक फेरबदल के संकेत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ दिलीप घोष की हुई अहम बैठक

बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश भाजपा ईकाई में उपजे असंतोष और चुनाव बाद की परिस्थिति को लेकर चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली गए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दिलीप घोष ने प्रदेश इकाई में व्यापक संगठनात्मक फेरबदल के साथ पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले बागी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। बागी नेताओं में ज्यादातर वह हैं, जो चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

खबर है कि बैठक के दौरान पार्टी के कुशल कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुरस्कृत करके संगठन को नया रूप देने और स्थानीय व जिला स्तर के कई दलबदलुओं को हटाने का निर्णय लिया गया। चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने, बढ़ती अंदरूनी कलह पर लगाम लगाने और नेताओं कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने के मद्देनजर ये कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में नड्डा ने घोष को महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश दिए।

घोष ने बताया कि चुनाव बाद हिंसा समेत विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया। बताया गया कि यह बैठक नड्डा के आवास पर शाम पांच बजे शुरू हुई जो डेढ़ घंटे तक चली। दरअसल इस बैठक पर खासकर बंगाल भाजपा के नेताओं की निगाहें टिकी हुई थीं। नड्डा के बुलावे पर शनिवार रात में ही घोष दिल्ली गए थे। पहले यह बैठक रविवार को ही होनी थी लेकिन इसे सोमवार के लिए टाल दिया गया था।

बंगाल विस की नौ समितियों से इस्तीफा देंगे भाजपा विधायक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : तृणमूल में वापसी करने वाले मुकुल रॉय को विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से भाजपा काफी क्षुब्ध है और आसानी से हार मानने के पक्ष में नहीं है। खबर है कि भाजपा विधायक मंगलवार को विधानसभा की नौ समितियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।

मंगलवार दोपहर एक बजे विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के आवास पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पीएसी अध्यक्ष को लेकर विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। भाजपा के किसी भी विधायक ने मुकुल रॉय के नाम का प्रस्ताव नहीं दिया था। ऐसे में पीएसी अध्यक्ष के तौर पर मुकुल को चुना जाना अनैतिक है।

144 फीट कम हो गया भाखड़ा बांध में पानी। डैम में 1680 फीट पर होना चाहिए जल स्तर, फिलहाल 1536 फीट पर चल रहा पानी। हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को दी जाने वाली जल की मात्रा में कटौती।

देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है आकाशीय बिजली

मानसून के आते ही देश के अलग-अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। रविवार को विभिन्न राज्यों में इस प्राकृतिक आपदा से जहां लगभग 80 लोगों की मौत हो गई वहीं 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रदेश सरकारों की तरफ से मुआवजे के एलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आकाशीय बिजली इतनी बड़ी आपदा साबित हो रही है।



उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा गिरती है बिजली

पनामा के स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के मुताबिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले 10 करोड़ गुना ज्यादा बिजली गिरती है। चूंकि इन क्षेत्रों में रिहायश बहुत कम है, इसलिए जनहानि का पता नहीं चलता है। क्षेत्रवार बिजली गिरने की घटनाओं की बात करें तो आफ्रीका अव्वल है। उसके बाद एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। जलवायु परिवर्तन के चलते आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 25 से 50 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

इस तरह पैदा होती है आकाशीय बिजली

जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनती है, तब बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने से बादलों में धनावेश (पॉजिटिव चार्ज) ऊपर की ओर एवं ऋणावेश (निगेटिव चार्ज) नीचे की ओर होता है। बादलों में इन विपरीत आवेशों की अपनी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इस तरह आकाशीय बिजली पैदा होती है। धरती पर पहुंचने पर आकाशीय बिजली बेहतर कंडक्टर (संचालक) तलाशती है, जिससे वह गुजर सके। इसके लिए धातु और पेड़ उपयुक्त होते हैं। बिजली अक्सर इन्हीं माध्यमों से पृथ्वी में जाने का रास्ता चुनती है।



इससे बचने के उपाय

- धातुओं से दूर रहें, बिजली के उपकरणों का प्रयोग नहीं करें।
- जितना हो सके वज्रपात की स्थिति में मोबाइल का प्रयोग नहीं करें।
- बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें।

बड़ी संख्या में होती हैं मौतें

बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अकेले 2001 से 2018 के बीच प्राकृतिक आपदा से होने वाली कुल मौतों में से 40 फीसद जानें बिजली गिरने से गई हैं। 2005 के बाद से प्रत्येक साल बिजली गिरने से दो हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2018 में प्राकृतिक आपदा से कुल 6,891 लोगों की मौत हुई। इनमें से 2,357 (34 फीसद) लोगों की जान आकाशीय बिजली के कारण गई। एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आकाशीय बिजली गिरने से 1,619 लोगों की मौत हुई है।

बिजली गिरने में हुई 34 फीसद की वृद्धि

मौसम विभाग के साथ मिलकर काम करने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (सीआरओपीसी) के मुताबिक 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आकाशीय बिजली गिरने में 34 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2019-20 में 138,00,000 के मुकाबले 2020-21 में 185,44,367 बार बिजली गिरी। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहे।

अध्ययन ने बताई भविष्य की तस्वीर

बर्कले विश्वविद्यालय के 2014 के एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक तापमान में हर एक डिग्री के इजाफे के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 12 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि इस सदी के आखिरी तक बिजली गिरने की घटनाओं में करीब 50 फीसद का इजाफा हो जाएगा।

खास बातें

- आकाशीय बिजली की एक बार की चमक 30 करोड़ वोल्ट और लगभग 30 हजार एंपीयर के बराबर होती है। आकाशीय बिजली की एक चमक 100 वाट के बल्ब को तीन महीने तक जला सकती है।
- पिछले एक साल के दौरान बिजली गिरने से भारत में 70 फीसद मौतें पेड़ के नीचे खड़े होने से हुई हैं। करीब 25 फीसद मौतें खुले मैदान में रहने से हुई हैं।

आपदा नीति में मान्यता नहीं

हर साल हजारों मौत के लिए जिम्मेदार इस आपदा को आपदा राहत नीति में मान्यता नहीं मिली है। इसका अर्थ यह है कि पीड़ित परिवारों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मुआवजा संभव नहीं है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने इसे आपदा घोषित कर रखा है। यह केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अपने आपदा राहत कोष का 10 फीसद विशिष्ट आपदाओं के लिए आवंटित करने के निर्देश के बाद किया गया है।

जागरण इन्फो

तय समय के बाद भी आमेर किले में रुके, गिरी बिजली, 12 की मौत

आफत ▸ राजस्थान में बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से कुल 23 की मौत, 28 घायल



कुदरत का कहर : कई राज्यों में हुई भारी बारिश से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल भागसूनाग में पानी के तेज बहाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यहां घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई हैं। जम्मू में हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पानी का तेज बहाव रिहायसी इलाकों तक जा पहुंचा है, जिससे कई मकान ध्वस्त हो गए। उत्तराखंड में भारी बारिश से मलबा सड़कों पर आ गया है। इसके चलते लगभग 150 से अधिक संपर्क मार्गों से आवागमन बंद हो गया है। बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। वहीं, राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से लगभग दो दर्जन लोगों की मौत हो गई। प्रेट्र, जागरण, एएनआइ

जागरण टीम, नई दिल्ली

आकाशीय बिजली गिरने से राजस्थान के छह जिलों में 23 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 28 घायल हो गए । सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत जयपुर में हुई है। ये सभी आमेर किले के वाच टावर पर खड़े होकर मौसम का आनंद ले रहे थे। आमेर किले के वाच टावर पर जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें नौ स्थानीय और तीन पर्यटक थे। उधर, मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो दिन (रविवार व सोमवार) में 14 की जान गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी रविवार को आकाशीय बिजली की वजह से 41 लोगों की जान चली गई थी।

जानकारी के अनुसार आमेर किले और वाच टावर पर जाने की अनुमति शाम सात बजे तक ही है, लेकिन करीब 25 लोग रविवार रात आठ बजे तक वहां मौजूद थे । इसी बीच बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई । वाच टावर पर ज्यादातर लोग सेल्फी लेने गए थे। आपदा प्रबंधन टीम के उप नियंत्रक जगदीश रावत ने बताया कि जहां बिजली गिरी, वहां लाइट का प्रबंध नहीं है । हादसे में घायल एक व्यक्ति ने मोबाइल से कंट्रोल रूम में सूचना दी । इसके बाद रात 8:30 बजे आपदा प्रबंधन दल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे । अंधेरा होने के कारण पहले मोबाइल की फ्लैश लाइट से लोगों को पहाड़ियों से नीचे पहुंचाया गया । रातभर बचाव कार्य चला, जो सुबह खत्म हुआ। इस दौरान ड्रोन से भी लोगों की तलाशी की गई। जयपुर के पुलिस उपायुक्त राहुल प्रकाश ने सोमवार सुबह 11 बजे मृतकों की संख्या के बारे में अधिकारिक पुष्टि की । उन्होंने 12 लोगों की मौत के साथ ही 10 लोगों के घायल होने की बात कही है ।

पहाड़ों में आफत की बारिश, दो की मौत कई लापता

जागरण टीम, नई दिल्ली

- वैष्णो देवी में बैटरी मार्ग पर पत्थर गिरने से रोके गए श्रद्धालु, हेलीकाप्टर सेवा बाधित
- हिमाचल में सड़कें बाधित होने से कुल्लू का संपर्क मंडी से कटा

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून की दस्तक के बाद लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हिमाचल के साथ उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, कई लापता भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सोमवार को बारिश व भूस्खलन ने तबाही मचाई। जिले में भूस्खलन व खड्ड में बहने से दो लोगों की मौत हो गई। बोह घाटी में भूस्खलन से कई मकान ध्वस्त हो गए, जिनमें 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मैक्लोडगंज के साथ लगते भागसूनाग में नाले का बहाव मुड़ने से बाजार में आई बाढ़ से कई वाहन बह गए। प्रदेश के अन्य भागों में भी बारिश व भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है।

शिमला के जुब्बल में कार पर चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। शिमला जिले के कुपवी में लकड़ी से बना तीन मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। प्रदेशभर में 184 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में बारिश से आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से प्रदेश सरकार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। **उत्तराखंड में भी 150 से ज्यादा संपर्क मार्ग बंद :** उत्तराखंड में भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में मलबा आने से करीब 150 से अधिक संपर्क मार्ग भी बंद हैं। इसके अलावा बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर बार-बार मलबा आने से यातायात बाधित होता रहा।

जम्मू में टूटा 32 साल का रिकार्ड

जम्मू में बारिश ने पिछले 32 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। सोमवार को 150 .6 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। इससे पहले सात जुलाई 1989 को 150 .4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। नदियों के किनारे बसे इलाके जलमग्न होने से कई पशु भी तेज बहाव में बह गए। कहीं कच्चा बांध ढह गया तो कहीं वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू शहर के निचले इलाकों के अलावा पाश इलाकों में भी पानी भर जाने से मलबा लोगों के घरों में घुस गया। कटड़ा में माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग पर पहाड़ से पत्थर गिरने से कुछ देर श्रद्धालुओं को रोका गया। उधर, कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आई बाढ़ में कई रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

संसदीय समिति ने भी मौसम विभाग से मांगी रिपोर्ट

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

> संसदीय समिति ने मानसून की मौजूदा और भावी स्थिति पर अपडेट लेने के लिए बैठक रखी थी। दो अन्य एजेंसियां भी बुलाई गई थीं। स्थिति को समझकर समिति आगे के हालात के लिए अपनी रिपोर्ट और रणनीति तैयार करेगी।
>
> – डा. एम महापात्रा, महानिदेशक, आइएमडी

> करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में मानसून के लगातार लेट होने, बार-बार गलत हो रहे पूर्वानुमानों और इस स्थिति का भविष्य में सामने आने वाला परिणाम संसदीय समिति की चिंता का खास कारण रहा।
>
> –महेश पलावत, उपाध्यक्ष, स्काईमेट वेदर

मानसून की दस्तक को लेकर एक के बाद एक गलत साबित हो रहे मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर अब संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। दरअसल, सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की स्थायी समिति ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर दो दिन पहले बैठक की थी। इसमें केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के महानिदेशक डा. एम महापात्रा और स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत सहित कई अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी एजेंसियों से राज्यवार मानसून की मौजूदा और आगे की स्थिति पर अलग-अलग प्रेजेंटेशन देने को कहा गया। आइएमडी की ओर से बताया गया कि मानसून का पूर्वानुमान पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के माडल पर निर्भर रहता है, लेकिन इस बार चार हफ्तों के पूर्वानुमान को लेकर इन दोनों ही माडलों से सही पूर्वानुमान नहीं मिल पाए। केरल में मानसून की दस्तक को लेकर पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। इसके बाद सही अनुमान लगाया ही नहीं जा सका है। इस पर रिपोर्ट मांगी गई है।

जैसलमेर पहुंचा मानसून, दिल्ली को अब भी इंतजार

- मौसम विभाग ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के अनुकूल स्थितियां बनीं
- पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई बारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को अपने आखिरी पड़ाव में पड़ने वाले राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश का अब भी इंतजार है।

दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और हरियाणा के करनाल में बारिश हुई, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में बादल मंडराते ही रहे, बरसे नहीं और इस वजह से यहां गर्मी से राहत नहीं मिली है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में राहत की बूंदे जरूर बरस गई हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा (एनएलएम) इस समय जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, अलीगढ़, करनाल और गंगानगर से गुजर रही है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों तक मानसून पहुंच गया है। आमतौर पर पूरे देश के बाद मानसून जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंचता है।

मौसम विभाग ने कहा, 'पिछले तीन दिन से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली पुरवाई हवाओं के चलने से बादलों का दायरा बढ़ गया और पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है और 12 जुलाई को राजस्थान, पंजाब के अधिकतर स्थानों के साथ ही हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और स्थानों पर दस्तक दे चुका है।' आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार से दक्षिण पश्चिम मानसून के बादल छाये हुए हैं, हवा का रुख बदल गया है और नमी वाली पुरवाई हवाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा, 'लेकिन अभी तक वर्षा नहीं हुई। यह बहुत असाधारण स्थिति है।'

गलत साबित हुआ पूर्वानुमान : मौसम विभाग ने पहले कहा था कि दिल्ली में समय से 12 दिन पहले 15 जून को मानसून आ जाएगा, लेकिन बाद में उसने अपने पूर्वानुमान में बदलाव कर दिया। इसके बाद मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचने के लिहाज से सात जुलाई तक स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। फिर 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की बात कही, लेकिन दिल्ली वाले इंतजार ही करते रह गए और बारिश नहीं हुई।

अनंतनाग में दूसरे दिन भी की छापेमारी, तीन आतंकी हिरासत में

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

भारत, खासकर कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने भारत पर केंद्रित आनलाइन प्रोपेगंडा मैगजीन द वायस आफ हिंद को कश्मीर में शुरू कर रखा था। इसके जरिये वह भारत में मुस्लिम युवाओं को हिंसा और जिहाद फैलाने के लिए उकसा रहा है। इससे वह अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए वित्तीय मदद भी पहुंचा रहा था। इस मैगजीन का संचालन उमर निसार कर रहा था। सूत्रों की मानें तो वह कासिम खुरासानी के कोड नाम से इस मैगजीन को चला रहा था। उमर निसार उन छह लोगों में शामिल है, जिन्हें एनआइए ने गत रविवार को ही श्रीनगर और अनंतनाग में छापे मारकर हिरासत में लिया था। अब इनमें से उमर निसार, तनवीर अहमद बट और रमीज अहमद लोन को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह तीनों ही अच्छाबल, अनंतनाग के रहने वाले हैं। वहीं, आइएस के कश्मीर माड्यूल के खिलाफ एनआइए ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी अनंतनाग में दो जगह छापे मारे। इस दौरान दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि देश-विदेश में सक्रिय आइएस का कैडर फर्जी नामों से भारत के खिलाफ आनलाइन दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। वायस आफ हिंद मैगजीन से जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में बैठे राष्ट्रविरोधी और जिहादी तत्व जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि एनआइए बीते दो दिनों के दौरान कथित तौर पर एक महिला समेत नौ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले चुकी है। अलबत्ता, एनआइए के प्रवक्ता ने इस मामले में अभी तक सिर्फ तीन लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

अफगानिस्तान से शुरू की थी मैगजीन : इस मैगजीन अफगानिस्तान में हुजैफा अल बाकिस्तानी नामक आइएस आतंकी कमांडर ने कथित तौर पर शुरू की थी। हुजैफा का संबंध श्रीनगर से है।

एक साल पहले 12 आतंकियों ने की थी घुसपैठ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

साजिश

- जेएमबी के आतंकियों से पूछताछ में एसटीएफ को मिली जानकारी
- तीन कोलकाता में रह रहे थे और बाकी छोटे समूहों में दूसरे राज्यों में चले गए थे

कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा रविवार को गिरफ्तार किए गए जमात- उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, जांच में पता चला है कि करीब एक साल पहले 12 आतंकियों का एक समूह बांग्लादेश से सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। उनमें से तीन कोलकाता में रह रहे थे और बाकी छोटे समूहों में दूसरे राज्यों में चले गए थे। कुछ कश्मीर और ओडिशा गए।

नजीउर अपने दोनों साथी शेख शब्बीर और रबीउल के साथ पहचान बदलकर दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर में किराए के एक मकान में रह रहा था। तीनों खुद को भारतीय बताते थे। अधिकारियों की मानें तो स्थानीय लोगों को ये तीनों छाता मरम्मत करने वाले और फल व कपड़ा विक्रेता के रूप में अपना परिचय देते थे। डायरी से **साजिश का खुलासा:** इनके पास से डायरी मिली है जिसमें आतंकियों ने लिखा है कि बंगाल के प्रत्येक घर की रसोई में बम बनाने का कारखाना बनाना होगा। इस बीच, तीनों को 14 दिनों के लिए 26 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

बार्डर गार्ड बांग्लादेश का जवान रह चुका है नजीउर : जांच में पता चला है कि पकड़े गए तीनों आतंकियों में से एक नजीउर रहमान (30) बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) का जवान रह चुका है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, बीजीबी में काम करते वक्त उसे विस्फोटक रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और आतंकी क्रियाकलाप से जुड़े होने के आरोप उसपर लगे थे। इसके बाद उसे बीजीबी ने बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद आंतकी बन गया।

कई शहरों में डेरा जमाए है टीमें

प्रथम पृष्ठ से आगे

मिनहाज जम्मू-कश्मीर निवासी तौहीद व मूसा के भी संपर्क में भी था। कानपुर, संभल व कई अन्य शहरों में एटीएस की टीमें डेरा जमाए हैं और मिनहाज के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। एटीएस के सामने अब उसके संपर्क में रहे युवकों को तलाशने के साथ यह पता लगाने की भी चुनौती है कि मिनहाज अलकायदा के किन हैंडलर से सीधे जुड़ा था। उनके बीच किस तरह के संदेशों व सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा था। मिनहाज ने जम्मू-कश्मीर निवासी तौहीद के खातों में रकम भेजी थी। यह रकम किस काम के लिए दी गई थी और दोनों के बीच क्या संबंध हैं। इनके जवाब भी बेहद अहम हैं।

सूत्रों का कहना है कि संभल के निवासी कई युवक अलकायदा से जुड़े हैं और वे पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हैं। उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है।

भारत ने किया सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण



ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का एक दृश्य। सौ. डीआरडीओ

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

सामरिक क्षमता के विस्तार का क्रम आगे बढ़ाते हुए भारत ने सोमवार को दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण किया। 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 2.8 गुना ज्यादा तेज बताई जा रही है। ओडिशा के चांदीपुर तट पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आइटीआर) के वरिष्ठ अधिकारियों और विज्ञानियों के दल ने सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर इसका परीक्षण किया। डीआरडीओ इस परीक्षण के परिणामों की विवेचना कर रहा है। उधर, समाचार एजेंसी एएनआइ परीक्षण के पूरी तरह सफल नहीं होने की बात कह रही है, लेकिन डीआरडीओ सूत्रों के अनुसार इसका परीक्षण सफल रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खास बात यह है कि इसे जल, थल और वायु कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। पानी के जहाज, हवाई जहाज, जमीन व मोबाइल लांचर से छोड़े जाने की खास खूबी से युक्त यह मिसाइल किसी भी दिशा में घूम कर लक्ष्य को भेद सकती है। यह अपने साथ 300 किलो वजन तक का विस्फोट ले जाने की क्षमता रखती है। मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है और इसका व्यास 0.6 मीटर है। इसका वजन तीन हजार किलोग्राम है।

भारत और रूस के विज्ञानियों के संयुक्त प्रयास से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन का परीक्षण भारत पहले ही कर चुका है। इसका एक बेड़ा पहले से ही भारतीय सेना में शामिल है। डीआरडीओ लगातार इसके एडवांस वर्जन बनाकर इसका क्षमता में वृद्धि कर रहा है। यह मिसाइल घनी शहरी आबादी में भी छोटे लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम है।

ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को आइटीआर चांदीपुर से ही किया गया था। ब्रह्मोस नाम भारत की पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र और रूस में बहने वाली मोस्कवा नदी के संयुक्त नाम का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि है।

खुशी में खलल

दलाई लामा के जन्मतिथि कार्यक्रम में खलल डालने के लिए डेढ़ किमी अंदर तक आए थे चीनी सैनिक ,भारतीय सेना की मजबूती, तिब्बत की आजादी के संघर्ष से सुलग रहा है चीन

चीनी सैनिकों ने देमचोक में लहराए झंडे

राज्य ब्यूरो, जम्मू

लद्दाख पर बुरी नीयत रखने वाले चीन ने देमचोक (लेह) में घुसपैठ कर धर्मगुरु दलाई लामा के तिब्बत की आजादी संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने की गीदड़ भभकी दी। पूर्वी लद्दाख में गलवन में मुंह की खाने वाला चीन क्षेत्र में सेना के मजबूत होने व तिब्बत के लोगों के संघर्ष से सुलग रहा है। छह जुलाई को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लोगों के दलाई लामा का जन्मदिन मनाने, तिब्बत के झंडे फहराना चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को नागवार गुजरा।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, डोला तामगो क्षेत्र के कोयूल गांव में तिब्बती शरणार्थियों ने दलाई लामा का 86वां जन्मतिथि मनाकर तिब्बत को चीन से आजाद करवाने के नारे बुलंद किए। कार्यक्रम का विरोध करने के लिए चीन के सैनिक पांच वाहनों में कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मौके से करीब 200 मीटर की दूरी पर सिंधु नदी के पार एकत्र हो गए। कार्यक्रम में खलल डालने के लिए चीनी सैनिक कच्ची सड़क से डेढ़ किलोमीटर अंदर तक आए थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार, चीनी सेना के झंडों के साथ बड़ा लाल झंडा उठा रखा था, जिसमें चीनी भाषा में कुछ लिखा था। कयास लगा जा रहे झंडे पर तिब्बत को आजाद करवाने की गतिविधियां रोकने की धमकी थी। छह जुलाई को सुबह 11 बजे आए चीन के सैनिक करीब आधा घंटे सिंधु नदी के पार विरोध जताने बाद लौटे गए। स्थानीय निवासियों के अनुसार, करीब 10 दिन पहले भी इस इलाके के करीब चीनी सैनिकों ने सोलर पंप लगाने पर विरोध का इजहार किया था। कायूल गांव के उरगेन सीवांग का कहना है कि देमचोक इलाके में हमारा आखिरी गांव है। पहले भी चीन के सैनिक खलल डाल चुके हैं।

चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाना जरूरी

तिब्बतियों को इस मांग पर समर्थन देने के लिए बने भारत तिब्बत संवाद मंच के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख के प्रभारी शिशुपाल सिंह का कहना है कि हम लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार तिब्बत का चीन से आजाद करवाएं। लद्दाख में बुरे मंसूबे रखने वाले चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाना जरूरी है।

निलंबित एडीजी की डायरी में ईवीएम हैकरों के नाम

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जीपी सिंह के घर से मिली डायरी में ईवीएम हैकरों के नाम और पते मिले हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जब डायरी के पन्ने पलट रही है तो नित नए तथ्य सामने आ रहे हैं। उधर, पुलिस अब जीपी सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर गत दिनों छापे मारे थे। इस दौरान मिली डायरी के आधार पर उन पर राज्य सरकार को गिराने की साजिश रचने की कोशिश करने का आरोप लगा था।

न्यूज गैलरी

पीकू वार्ड में बच्चों का मन बहलाएंगी रंग-बिरंगी दीवारें

बलिया : कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयारी में लगा है। बलिया के जिला अस्पताल में पीकू वार्ड (पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट) तैयार हो चुका है। इस वार्ड में भर्ती होने वाले बच्चों को घुटन महसूस न हो, इसके लिए मनोरंजन का इंतजाम भी किया गया है। कार्टून और जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। (जासं)

आर्थोडाक्स सीरियन चर्च आफ इंडिया के सर्वोच्च प्रमुख का निधन

कोट्टायम : मलंकारा आर्थोडाक्स सीरियन चर्च आफ इंडिया के सर्वोच्च प्रमुख बेसेलियस मारथोमा पालोस द्वितीय का रविवार की देर रात निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। पालोस ने ताउम्र गरीबों व वंचितों के लिए काम किया और गिरजाघर में कई बदलावों के वाहक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन व कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि ने उनके निधन पर शोक जताया है। (प्रेट्र)

करतारपुर साहिब कारिडोर खोलने की मांग

नई दिल्ली : कोरोना का प्रकोप कम होने का हवाला देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने केंद्र सरकार से करतारपुर साहिब कारिडोर खोलने की मांग की है, जिससे कि श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे के दर्शन कर सकें। इस कारिडोर के जरिये श्रद्धालु बिना बीजा के पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जा सकते हैं। (राब्यू)

पटना एम्स में छोटे बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल सुस्त

पटना : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण जल्द पूरा करने को प्रयासरत है। हालांकि छोटे बच्चों पर उसका ट्रायल सुस्त है। दस दिनों में दो से छह आयुवर्ग के 16 बच्चों ने पंजीयन कराया, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ चार बच्चे ही परीक्षण के मानकों पर खरे उतरे। चारों बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं, इस आयुवर्ग के अन्य बच्चों का पंजीयन कर उनकी स्क्रीनिंग का कार्य जारी है। परीक्षण में शामिल सभी बच्चे एम्स के विशेषज्ञों की निगरानी में रहते हैं। अबतक किसी में दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। उधर, जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश में एंटीबाडी बन जाने से उन्हें ट्रायल में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। (राब्यू)

पर्यटन व धार्मिक यात्राओं से घातक हो सकता है कोरोना, आइएमए ने किया सचेत

नई दिल्ली : देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ राज्यों में मामले बढ़े भी हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने सरकार को सचेत करते हुए कहा है कि पर्यटन व धार्मिक यात्राओं से कोरोना ज्यादा घातक हो सकता है। इससे तीसरी लहर जल्द आ सकती है और धार्मिक यात्राएं कोरोना का संक्रमण बढ़ाने में सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा सकती हैं।

ऐसे में आइएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सभी राज्य सरकारों से मांग की है कि कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के उपायों को अभी कम नहीं करना चाहिए। पर्यटन, तीर्थ स्थलों का भ्रमण और धार्मिक यात्राएं जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा समय में यह उचित नहीं है। ऐसे आयोजनों के लिए अभी कम से कम तीन माह इंतजार करना चाहिए। आइएमए के अध्यक्ष डा. जेए जयलाल ने कहा कि डाक्टर दूसरी लहर से निपटकर तुरंत बाहर निकले हैं। (राब्यू)

पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ पीएम की चर्चा आज

संक्रमण की स्थिति और नियंत्रण पर होगी बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। केरल को छोड़ दें तो महाराष्ट्र में मामले बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन कम भी नहीं हो रहे हैं। परंतु, इससे उलट पूर्वोत्तर के छोटे-छोटे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं जो चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि हालात को काबू में करने के लिए वो कुछ जरूरी निर्देश दे सकते हैं।

देश में कोरोना वायरस की राष्ट्रीय संक्रमण दर पिछले कुछ दिनों से पांच फीसद से नीचे बनी हुई है, लेकिन 66 जिलों में यह 10 फीसद से ज्यादा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इनमें से 39 जिले पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं। मसलन अरुणाचल प्रदेश के 10, मणिपुर के नौ, मेघालय के छह, असम और सिक्किम के चार-चार, त्रिपुरा के तीन, मिजोरम के दो और नागालैंड का एक जिला इसमें शामिल है। अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में इतने अधिक जिलों में संक्रमण दर अधिक होने से पूरे पूर्वोत्तर में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों से आक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों की कमी की कोई शिकायत नहीं आई है।


कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच सोमवार को नई दिल्ली स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लेती महिला। प्रेट्र

लेकिन अधिक संक्रमण दर केंद्र के लिए चिंता का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और नगालैंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही संक्रमित लोगों के इलाज के लिए किए गए बंदोबस्त की भी जानकारी लेंगे। केंद्र ने अभी कुछ दिन पहले ही इन राज्यों में दो सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम भेजी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी कुछ जरूरी निर्देश दे सकते हैं।

टीकाकरण के औसत में 21 जून से लगातार गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का नया चरण आरंभ होने के बाद दैनिक औसत में 21 जून से कमी देखी जा रही है। कोविन प्लेटफार्म पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 21-27 जून वाले हफ्ते में प्रत्येक दिन कोविड रोधी टीके की औसतन 61.14 लाख डोज दी गईं। इसके बाद के हफ्ते में 28 जून से 4 जुलाई के बीच यह आंकड़ा कम होकर प्रतिदिन 41.92 लाख डोज रह गया। इसके बाद 5 से 11 जुलाई वाले हफ्ते में प्रतिदिन दी गई डोज की औसत संख्या और कम होकर 34.32 लाख रह गई।

राज्यों में टीकाकरण की मिलीजुली प्रवृति देखने को मिली है। कुछ राज्यों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण में निरंतरता है जबकि कहीं इसमें गिरावट आई है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 21-27 जून वाले हफ्ते से औसत दैनिक टीकाकरण में गिरावट देखी गई जबकि केरल, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा नागर हवेली और जम्मू-कश्मीर में दैनिक कोरोना रोधी टीकाकरण में निरंतरता देखी गई है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जहां कोरोना वायरस के नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है वहां दैनिक औसत टीकाकरण में गिरावट देखी जा सकती है। इस के बावजूद कोविड रोधी टीकाकरण के इससे पहले के चरण के मुकाबले अब औसत टीकाकरण अधिक है।

देश में कोरोना की स्थिति

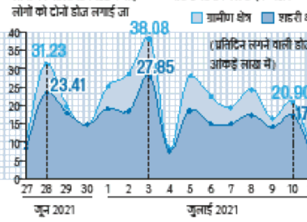
कोरोना/वैक्सीन मीटर	(आंकड़े टैली फारमेट के लिए)
24 घंटे में नए मामले	37,154
कुल सक्रिय मामले	4,50,899
24 घंटे में टीकाकरण	12.35 लाख
कुल टीकाकरण	37.73 करोड़

गुजरात ने पर्याप्त डोज मिलने का किया दावा :

गुजरात सरकार के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि राज्य को केंद्र से अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की पर्याप्त डोज मिली हैं और राज्य के पास अभी टीके की करीब सात लाख डोज हैं। यहां के अधिकारियों ने विश्वास जताया कि राज्य के सभी पात्र लोगों को इस साल के अंत तक टीका लगा दिया जाएगा। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, गुजरात की टीके के लिहाज से पात्र आबादी के पूर्ण टीकाकरण के लिए राज्य को कुल 9.6 करोड़ डोज की आवश्यकता है।

टीकाकरण में हमारे गांवों ने शहरों को पीछे छोड़ा

महामारी विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। इस लहर के असर को हम कुंद कर सकते हैं, अगर कम समय में ज्यादा से ज्यादा आबादी को टीका लगा दिया जाए। देश में अब तक 37.6 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इनमें 30.27 करोड़ लोगों को पहली तो 7.32 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। देश में टीकाकरण का जो ट्रेंड चौंकाने वाला सामने आ रहा है उसमें हमारे गांव सुविधा संपन्न शहरों से काफी आगे दिख रहे हैं। जिन गांवों के लिए माना जाता था कि लोग जागरूक नहीं हैं, संसाधनों की समस्या है, वहां के लोग टीका लगवाने में शहरों को पढ़े-लिखों को मात दे रहे हैं। पेश है एक नजर :



अगले छह महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में नियोजन और क्षमता निर्माण

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हाल में मंजूर हुए पैकेज से बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं
- सभी जिलों में जरूरी चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त कोष की व्यवस्था

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि हाल में मंजूर हुए 23 हजार करोड़ रुपये के कोरोना पैकेज से सरकार ने एक समग्र योजना के तहत अगले छह महीनों में सभी अस्पतालों में बच्चों की देखभाल के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

एक बयान में कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री भावनगर में सरकार द्वारा संचालित सर तख्तसिंहजी अस्पताल में 1000 एलपीएम (लीटर प्रतिमिनट) की क्षमता वाले दो आक्सीजन संयंत्रों के डिजिटल उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। दीनदयाल बंदरगाह न्यास ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत 2.53 करोड़ रुपये की लागत से यह संयंत्र स्थापित करवाया है। कोरोना की चुनौती पर उन्होंने कहा, 'हमने दूसरी लहर से काफी कुछ सीखा है, जैसे आक्सीजन आपूर्ति, अस्पताल में बिस्तर और दवाएं। हमनें अब यह सुनिश्चित किया है कि सभी जिलों में जरूरी चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त कोष रहे।' मंडाविया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में कोरोना की आपात स्थिति से निपटने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है जिसके जरिये अगले छह महीनों में एक समग्र योजना और क्षमता निर्माण पर काम किया जा रहा है। 'हमनें सभी अस्पतालों में बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं जिससे उन्हें सबसे प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल मिल सके।

मामले बढ़ने पर सुनील शेट्टी की बिल्डिंग सील

मुंबई, एएनआइ : कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अभिनेता सुनील शेट्टी की बिल्डिंग सील कर दी है। वह दक्षिण मुंबई के अल्टामाउंट रोड स्थित पृथ्वी अपार्टमेंट में रहते हैं। इस बिल्डिंग में कोरोना संक्रमण के पांच मामले मिल चुके हैं। बीएमसी के सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड़ (डी वार्ड) ने बताया कि पृथ्वी अपार्टमेंट को शनिवार को सील किया गया है। संवाददाताओं ने जब सवाल किया कि बिल्डिंग सील किए जाने के बावजूद उसमें लोगों की आवाजाही दिख रही है तो प्रशांत ने कहा कि यह कोविड नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, 'अब हम पुलिस की तैनाती करेंगे,' सुनील शेट्टी बिल्डिंग के 18वें तल पर रहते हैं। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अभिनेता का पूरा परिवार सुरक्षित है। अभिनेता के प्रवक्ता ने भी बताया कि वह सपरिवार शहर से बाहर हैं और सुरिक्षत हैं।

संक्रमित मां के गर्भस्थ शिशु रहे सुरक्षित

1,000 औसत गर्भवतियों का प्रसव प्रत्येक माह

550 से अधिक संक्रमित गर्भवतियों का हुआ है सुरक्षित प्रसव

आकाश शुक्ला, रायपुर

कोरोना संक्रमित माताओं के नवजात बच्चों पर संक्रमण का असर नहीं होता है। पं. जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कालेज में चिकित्सा विज्ञानियों ने 200 कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं पर शोध किया है। जन्म के बाद शिशुओं का परीक्षण किया गया और लगातार नजर रखी गई। शोध में यह भी सामने आया कि गर्भ में बच्चों के आसपास और प्रसव के बाद दूध के तरल नमूनों में सक्रिय वायरस नहीं थे।

बच्चों में संक्रमण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। इस अस्पताल में हर माह 1,000 महिलाओं का प्रसव होता है। कोरोनाकाल में अब तक 500 से अधिक संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जा चुका है। इनमें नौ महिलाओं की मौत हो गई जिनमें तीन की मौत का कारण कोरोना रहा, जबकि अन्य पांच दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थीं। जबकि सभी बच्चे संक्रमण मुक्त थे।

वरिष्ठ चिकित्सा विज्ञानी डा. नेहा सिंह ने बताया कि स्वस्थ महिलाओं की तुलना में कोरोना संक्रमित महिलाओं को गंभीर बीमारी होने की आशंकाएं अधिक थी, लेकिन अध्ययन में देखा गया कि अस्पताल में भर्ती गर्भवतियों में सामान्य लक्षण जैसे बुखार, खांसी, हाथ-पैर में दर्द, गले में खरास दस्त आदि के अतिरिक्त कोई गंभीर समस्याएं नहीं आईं। वहीं जन्म के दौरान बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहे।

मां का दूध बचाता है संक्रमण से

संक्रमित गर्भवतियों से गर्भस्थ बच्चों को और जन्म के दौरान कोई खतरा नहीं होता है। शोध में देखा गया कि गर्भ के आसपास और जन्म के बाद मां का दूध संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रहा है। संक्रमित मां सावधानी रखकर और मास्क पहनकर बच्चे को स्तनपान भी करा सकती हैं। इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है।

-डा. नेहा सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा विज्ञानी, पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज

पुरी में सीमित भक्तों के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

- भाई-बहन के साथ रत्न वेदी से जन्म वेदी के लिए रवाना हुए महाप्रभु
- जय जगन्नाथ के जयकारे से गुंजायमान रहा श्रीक्षेत्र धाम

जागरण संवाददाता, पुरी

सोमवार को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के मौके पर ओडिशा के श्रीजगन्नाथपुरी धाम में महाप्रभु जगन्नाथजी की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा निकली। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी सीमित भक्तों के साथ ही रथयात्रा निकाली गई। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े पुजारी, सेवकगण, राज परिवार के प्रतिनिधि और अनुष्ठान व्यवस्था से जुड़े लोगों को ही रथयात्रा में शामिल होने की अनुमति थी। पुरी के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी इसमें शामिल हुए।

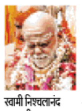
रथयात्रा के दौरान पूरा श्रीक्षेत्र जय जगन्नाथ के जयकारे से गूंजता रहा। भगवान के तीनों रथों को विग्रहों के साथ रस्सियों से खींचकर भगवान की मौसी के घर गुंडिचा मंदिर (जन्म वेदी) ले जाया गया। नौ दिनों बाद भगवान अपने भाई-बहन के साथ मौसीबाड़ी से वापस अपने धाम लौटेंगे। तब रथयात्रा संपन्न होगी।


ओडिशा के पुरी में सोमवार को महाप्रभु जगन्नाथजी की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा कोरोना महामारी के चलते सीमित भक्तों के साथ और कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। प्रेट्र

ब्रह्म मूहूर्त में ही शुरू हो गया अनुष्ठान: सोमवार अलसुबह 3:30 बजे मंगल आरती के बाद सूर्यपूजा और द्वारपाल पूजा की गई। सुबह सात बजे से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा तथा भगवान के सुदर्शन चक्र की विधि-विधानपूर्वक पूजा की गई। 10 बजकर 50 मिनट पर गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव (पुरी राज परिवार के प्रतिनिधि) पहुंचे और तीनों रथों के चारो ओर झाड़ू लगाई।

स्वामी निश्चलानंद ने कहा-कोरोना पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : श्रीजगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि कोरोना को लेकर दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। वह सोमवार को रथयात्रा के मौके पर रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे थे।


स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। जागरण

जगद्गुरु ने कहा कि यह कौन सा नियम है, जिसमें राजनीतिक सभा हो तो कोरोना नहीं फैलता है, और धार्मिक आयोजन की बात हो तो कोरोना फैलता है। क्या धार्मिक सभा में कोरोना को आमंत्रण दिया जाता है। शंकराचार्य ने कहा कि बिना भक्तों के नहीं बल्कि सीमित भक्तों को लेकर महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथयात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में, यह कहना गलत है कि बिना भक्तों की रथयात्रा हो रही है। जहां भगवान हैं, वहीं भक्त हैं और जहां भक्त हैं, वहीं भगवान हैं। आप और हम सब भगवान के भक्त हैं जो लोग रथ खींच रहे हैं, वह भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं। हालांकि शंकराचार्य ने लोगों से कोरोना के दौरान सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यह भी कहा कि यदि सरकार सख्ती कर रही तो लोग कह रहे हैं कि सरकार उन्हें भगवान का दर्शन करने नही दे रही है। यह भी ठीक नहीं। जो जहां हैं, वहीं से भगवान की पूजा करें।

कोलकाता में खुले पंडाल में होगी दुर्गा पूजा

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता : कोरोना महामारी को देखते हुए कोलकाता के दुर्गापूजा आयोजक इस बार खुले पंडाल का निर्माण कर रहे हैं ताकि लोग दूर से ही देवी दुर्गा के दर्शन कर सकें। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूजा पंडालों के अंदर दर्शनार्थियों के प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से दुर्गापूजा का आयोजन होने पर भी लोग देवी दुर्गा के दर्शन नहीं कर पाए थे। दुर्गापूजा आयोजकों का अनुमान है कि इस बार भी प्रशासन अथवा अदालत की तरफ से संभवतः पंडाल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए, इसलिए वे खुले पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। शहर के प्रमुख दुर्गापूजा आयोजकों में शुमार संतोषपुर लेक पल्ली के महासचिव सोमनाथ दास ने बताया, जमावड़ा जोखिम भरा हो सकता है इसलिए हम ऐसे थीम पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत खुले पंडाल का निर्माण किया जाएगा और लोग 10 मीटर की दूरी से देवी दुर्गा के दर्शन कर पाएंगे।

राष्ट्रीय फलक

सैलानियों से फिर गुलजार हुआ जन्नत-ए-कश्मीर

नवीन नवाज, श्रीनगर

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के थमते ही कश्मीर फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है। डल झील हो या पहलगाम या गुलमर्ग, हर जगह सैलानियों की तादाद साफ बता रही है कि जन्नत-ए-कश्मीर आज भी देसी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद हैं। टैक्सी चालक, हाउसबोट मालिक और पर्यटन जगत से जुड़ा हर शख्स सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। घाटी आ रहे पर्यटकों में सुरक्षा और विश्वास की नई भावना नजर आती है जो पहले महसूस नहीं होती थी।

पिछले 10 दिन में कश्मीर में लगभग 15 हजार पर्यटक आ चुके हैं। यह संख्या रोज बढ़ रही है। पर्यटन विभाग के अनुसार, जुलाई के पहले सप्ताह में रोजाना औसतन 1200 पर्यटक पहुंच रहे थे। शुक्रवार-शनिवार को तीन हजार पर्यटक घाटी पहुंचे हैं। इस साल अब तक कश्मीर में करीब 1.55 लाख पर्यटक आ चुके हैं। इनमें 850 विदेशी हैं। इस वर्ष मार्च में लगभग 42 हजार पर्यटक कश्मीर आए थे। उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण सब बंद हो गया। अब सब खुल चुका है और पर्यटन विभाग की मानें तो जुलाई में करीब 50 हजार पर्यटक कश्मीर पहुंचेंगे।


कश्मीर में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ती जा रही है। डल झील में शिकारे में बैठ हाउस बोट में ठहरने के लिए जाते पर्यटक। कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार आने के बाद कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। जागरण

यह बदलाव का ही संकेत है कि लालचौक के आसपास भी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमते नजर आते हैं। चश्माशाही बाग के नीचे बाटनीकल गार्डन में फिरन में तस्वीर खिंचवा रहे पुणे से आए नारायण खेमकर ने कहा कि मैं पहली बार कश्मीर आया हूं। यहां सबकुछ शांत है। मौसम अच्छा है। हम लोग कोरोना प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं। हमारा टैक्सी चालक ही हमारा गाइड है।

कुछ बरस अच्छे नहीं रहे : वर्ष 2019 में जुलाई के अंतिम सप्ताह में घाटी पर्यटकों से खाली हो गई थी। वर्ष 2020 में कोरोना लाकडाउन ने पर्यटन क्षेत्र का बहाल नहीं होने दिया। इस वर्ष पर्यटकों की आमद जब जोर पकड़ने लगी तो फिर लाकडाउन शुरू हो गया था।

साफ दिख रहा आत्मविश्वास : दूसरी बार कश्मीर घूमने आए मनीशा साबडे ने कहा कि पहले तय किया कि हिमाचल जाएंगे फिर हमने कहा कि कश्मीर ही बेहतर है। यहां आपके लिए बाग-बगीचे, झील, पहाड़ और बर्फ सबकुछ है। यहां की दस्तकारी बेजोड़ है। पहले टैक्सी चालक व होटल मालिक से पूछती थी कि बाहर सब ठीक है। इस बार ऐसा पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। टैक्सी चालक नजीर ने कहा कि हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। इस बार मैंने पर्यटकों में एक बात देखी है, वे अब अपनी सुरक्षा या कश्मीर के हालात को लेकर ज्यादा बात नहीं करते।

बिना जांच पर्यटकों को अनुमति नहीं : पर्यटन निदेशक डा. जीएन इट्टू ने कहा कि पर्यटन अब जोर पकड़ रहा है। हमने होटल संचालकों, टैक्सी आपरेटेरों, रेस्तरां मालिकों व कर्मियों, शिकारेवाले सभी को कोरोना वैक्सीन लगाई है।

शिकारे दिनभर बुक रहते : डल झील में पर्यटकों को सैर कराने के बाद प्रफुल्लित अब्दुल रज्जाक ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि सैलानी लौट आए हैं। लगभग सभी शिकारे दिनभर बुक रहते हैं। सैलानियों से भी कहता हूं कि कश्मीर घूमने आएं, लेकिन टेस्ट कराकर आएं।

प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में घेरा भाजपा नेता का घर, 11 घंटे तक बनाए रखा बंधक

- भाजपा नेता हुए मुक्त, 153 लोगों पर केस पर नहीं रुकी मनमानी
- पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में घटना की निंदा की

जागरण टीम, चंडीगढ़

पंजाब के राजपुरा में भाजपा नेताओं को करीब 11 घंटे तक बंधक बनाए रखने के मामले में पुलिस ने 153 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रविवार शाम करीब सवा पांच बजे बंधक बनाए गए इन नेताओं को सोमवार सुबह करीब चार बजे मुक्त करवाया जा सका।

इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने कोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। यह याचिका भाजपा चंडीगढ़ के लीगल सेल के कन्वीनर और याची ब्रजेश्वर जसवाल के वकील अनिल मेहता ने लगाई थी। जसवाल भी बंधक बनाए गए नेताओं में शामिल थे। जहां सरकार ने सभी बंधकों को मुक्त करवाने की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की सरकार निंदा करती है और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं, दूसरी तरफ राज्य के अन्य हिस्सों में किसानों की मनमानी जारी रही। सोमवार को किसानों ने फतेहगढ़ साहिब से भाजपा के जिलाध्यक्ष को उनके घर में बंधक बना लिया। बाद में उन्हें पुलिस की गाड़ी में घर से निकाला गया। भाजपा की ओर से प्रदेशभर में जिला प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने से पहले किए गए प्रदर्शनों में भी किसानों ने कुछ जगह रुकावटें पैदा कीं। जबकि कुछ जगह पुलिस ने किसानों को रोक लिया।

उधर, भाजपा की प्रदेश इकाई के नेताओं ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। करीब आधा घंटा धरना देने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा ने किसान के हमलों और पुलिस के मूक दर्शक बने रहने का मुद्दा उठाया। जिस पर कैप्टन ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इससे पहले सोमवार सुबह कसबा अमलोह में किसानों ने फतेहगढ़ साहिब से भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग के घर का घेराव कर उन्हें घर में बंधक बना लिया। मौके पर पहुंचे डीएसपी सुखविंदर सिंह और एसडीएम आनंद सागर शर्मा के समझाने पर भी किसान पीछे नहीं हटे। बाद में प्रदीप गर्ग को डीएसपी की गाड़ी में बिठाकर बाहर निकाला गया। गर्ग को सरहिंद में आयोजित पार्टी के रोष प्रदर्शन कार्यक्रम में जाना था और किसान उनके घर का घेराव करके उन्हें रोक रहे थे। पुलिस सुरक्षा में उन्हें सरहिंद लाया गया। गर्ग ने कहा कि कांग्रेस व अकाली कार्यकर्ता किसानों के वेष में आए और उन्होंने सरेआम गुंडागर्दी की। अगर वह अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षित होंगे। इसी तरह फाजिल्का में भी भाजपा ने धरना दिया तो किसान भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस की ओर से लगाए गए बेरिकेड हटा दिए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को भाजपा के धरने में जाने से रोका। कपूरथला में एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने ही रास्ते में घेरकर रोष मार्च करने से रोका। मगर प्रदर्शन करने को लेकर अड़े रहे।

एलआइसी के आइपीओ को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआइसी के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) को मंजूरी दे दी है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में एक पैनल इस आइपीओ के आकार, प्राइसिंग और सही समय का निर्धारण करेगा। विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एलआइसी के मूल्यांकन का जिम्मा मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी को सौंपा था। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। (प्रेट्र)

पुरानी एमपीएमसी से किसानों को जिंस के कुल मूल्य का केवल 15 फीसद ही मिलता है और लगभग पूरा लाभ बिचौलिए ले जाते हैं। नए कृषि कानूनों में इस समस्या का निदान है।

– कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, सीईए



सेंसेक्स	52,372.69	▼ 13.50
निफ्टी	15,692.60	▲ 2.80
सोना प्रति दस ग्राम	₹46,796	▼ ₹169
चांदी प्रति किलोग्राम	₹67,611	▼ ₹300
डॉलर	₹74.58	▼ ₹0.06
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 74.44	

एशिया के पांच तेल खरीदारों को अगस्त में पूरी खेप भेजेगा सऊदी

सिंगापुर, रायटर : दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल निर्यातक सऊदी अरब ने कहा है कि वह एशिया के कम से कम पांच खरीदारों को अगस्त के करार की पूरी खेप भेजेगा। घटनाक्रम से सीधे जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हालांकि दो सूत्रों ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब ने अतिरिक्त तेल मुहैया कराने के कम से कम दो खरीदारों का आग्रह ठुकरा दिया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरैमको ने इस मामले पर टिप्पणी से इन्कार किया है।

पिछले सप्ताह कच्चा तेल निर्यातकों के सबसे बड़े समूह ओपेक और सहयोगी देशों यानी ओपेक प्लस में अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाने के मसले पर सहमति नहीं बन पाई। इस मामले पर बातचीत टूट जाने के बाद सऊदी अरब ने एशियाई ग्राहकों को बेचे जाने वाले सभी स्तर के तेल का आधिकारिक बिक्री मूल्य (ओएसपी) अगस्त से बढ़ा दिया।

सहकारी समितियों के खुले भाग्य

किसानों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने में होगी सहूलियत

35,000 प्राथमिक सहकारी समितियां 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में होंगी विकसित

3,000 प्राथमिक समितियों को मल्टी सर्विस सेंटर के लिए 1,700 करोड़ मंजूर



नरेंद्र तोमर • फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अलग मंत्रालय बनते ही सहकारिता क्षेत्र के दिन बहुरने लगे हैं। प्राथमिकता सहकारी समितियों के भी भाग्य खुल गए हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 35,000 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों को 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसी के तहत 3,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) को मल्टी सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे उन्हें गांवों के छोटे व मझोले किसानों को आसानी से उनकी जरूरत का सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

नाबार्ड स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में ये जानकारियां देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि क्षेत्र की विकास दर को रफ्तार मिलेगी। किसानों की माली हालत में पर्याप्त सुधार होगा। इसमें प्राथमिक सहकारी समितियों को शामिल किया गया है, जिन्हें रियायती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। किसानों को इस मद से तीन फीसद ब्याज की रियायत मिलेगी। इसके लिए सरकारी गारंटी के साथ वित्तीय मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.81 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। इसका दो-तिहाई हिस्सा सिंचाई के संसाधनों को विकसित करने में लगाया गया है। सरकार की पीएम कृषि सिंचाई योजना 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के नारे को सफल बनाने के लिए नाबार्ड ने जबर्दस्त सहयोग किया है। इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई निधि का आकार बढ़ा दिया गया है।

कृषि सुधार की दिशा में संसद से पारित कानूनों की पैरवी करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं।

नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. जीआर चिंतला ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास पर जोर देते हुए कहा कि इसमें सिंचाई के साधन, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, बाजार, स्वास्थ्य व अन्य आधारभूत ढांचे पर ज्यादा बल देना चाहिए।

नए कृषि कानूनों से किसानों को ही लाभ : सुब्रमणियन

मुंबई, प्रेट्र : मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए बेहद लाभकारी बताया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को आखिरकार बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी कमाई बढ़ेगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन नियमों के तहत किसानों को अपनी उपज किसी को भी बेचने की आजादी दी गई है। किसान अपनी उपज रिलायंस इंडस्ट्रीज और आइटीसी जैसी बड़ी कंपनियों के हाथों अच्छी कीमत पर बेचने को स्वतंत्र हैं। इससे बड़ी कंपनियों में सीधे किसानों से उपज खरीदने की स्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को बढ़ी कमाई का फायदा मिलेगा। संसद ने तीनों कृषि कानूनों को पिछले वर्ष पारित कर दिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सुब्रमणियन ने कहा कि जब ये बड़ी कंपनियां किसानों की उपज के लिए स्पर्धा करेंगी तो कृषकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा।

मारुति ने सीएनजी वाहनों के दाम 15,000 रुपये तक बढ़ाए

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार से अपने चुनिंदा वाहनों के दाम में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इनमें हैचबैक स्विफ्ट के सभी मॉडल समेत अन्य सभी वाहनों के सीएनजी मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि इन वाहनों की एक्स शोरूम (दिल्ली) कीमतों में इजाफा किया गया है। यह बढ़ोतरी 12 जुलाई (मंगलवार) से प्रभावी हो गई है।

दाम में ताजा बढ़ोतरी से पहले नई दिल्ली में स्विफ्ट के मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमत 5.73-8.27 लाख थी। मारुति अपनी ऑल्टो, सिलेरियो, एस-प्रेसो, वैगनआर, ईको एवं अर्टिगा के सीएनजी वैरिएंट की बिक्री करती है। इनके दाम 4.43 लाख से शुरू होकर 9.36 लाख तक हैं। मारुति ने इस वर्ष अप्रैल में भी वाहनों के दाम में 22,500 तक का इजाफा किया था। उस वक्त सिलेरियो एवं स्विफ्ट के सभी मॉडल मूल्य वृद्धि से बाहर रखे गए थे। कंपनी का कहना था कि लागत मूल्य लगातार बढ़ते जाने की वजह से उसे दाम में बढ़ोतरी को मजबूर होना पड़ा है।

दो दशक में 15 ट्रिलियन डॉलर की होगी इकोनॉमी : अदाणी



गौतम अदाणी •

नई दिल्ली, प्रेट्र : अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी ने अगले दो दशक में देश की इकोनॉमी के 15 लाख करोड़ डॉलर का आकार हासिल कर लेने का भरोसा जताया है। अदाणी ग्रुप की सालाना आमसभा (एजीएम) में सोमवार को शेयरधारकों को संबोधित करते हुए चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि अगले चार वर्षों में देश की इकोनॉमी के पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार लेने की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है देश यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा और दो दशकों में उससे भी तीन गुना बड़ी इकोनॉमी होगा। अदाणी का कहना था कि विकास की राह में समय-समय पर दिक्कतें पहले भी आती रही हैं और आती रहेंगी। लेकिन इस पर कोई शक नहीं कि सबसे बड़े मध्यम वर्ग, कामकाजी आयुवर्ग की बढ़ती संख्या और उपभोक्ता वर्ग का देश के विकास पर सीधा सकारात्मक असर दिखेगा।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने देश और दुनिया को बड़े सबक दिए हैं, जो इसे भविष्य के लिए अधिक बुद्धिमान बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गलतफहमियों की वजह से पिछले महीने कंपनी के छोटे व खुदरा शेयरधारकों को परेशानी हुई। लेकिन ग्रुप ऐसी दिक्कतों से मजबूती के साथ उबरता रहेगा।

शेयर बाजारों ने शुरुआती बढ़त गंवाई

मुंबई, प्रेट्र: आइटी और मेटल शेयरों में मुनाफावसूली से सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में सोमवार को घरेलू शेयर बाजार अपनी शुरुआती बढ़त गंवा बैठे। दिन के कारोबार में 52,700.51 के उच्च स्तर तक जाने वाला बीएसई-सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 13.50 अंक यानी 0.03% फिसलकर 52,372.69 पर बंद हुआ। वहीं, कारोबार के आखिर में निफ्टी 2.80 अंकों यानी 0.02% के सुधार के साथ 15,692.60 पर स्थिर हुआ।

प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी जब्त करने की तैयारी में जुटे बैंक

1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज की गारंटी शीर्ष 10 पर्सनल गारंटरों ने ले रखी है

नई दिल्ली, प्रेट्र : पर्सनल गारंटी के आधार पर बैंकों से कर्ज लेने वाले प्रमोटर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाने के बाद बैंकों ने वेणुगोपाल धूत और कपिल वधावन जैसे प्रमोटर्स की निजी गारंटी भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन दिग्गजों ने कंपनियों को दिए गए कर्ज के एवज में व्यक्तिगत गारंटी दी थी। बाद में वे कंपनियां कर्ज नहीं लौटा सकीं। एक अनुमान के अनुसार 10 शीर्ष व्यक्तिगत गारंटर ने 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक की गारंटी दे रखी है। इसमें कुछ प्रमुख नामों में भूषण स्टील एंड पावर के प्रमोटर संजय सिंघल और उनकी पत्नी आरती सिंघल भी शामिल हैं। इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से लिए गए कर्ज पर 24,550 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत गारंटी दे रखी है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी और डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन ने अपनी कंपनियों को कर्ज दिलाने के लिए पर्सनल गारंटी दी हुई है। डीएचएफएल पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। वहीं धूत ने वीडियोकॉन को दिए गए 22,000 करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर गारंटी दे रखी है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 15 नवंबर, 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कर्जदाताओं, सामान्य तौर पर वित्तीय संस्थान और बैंकों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत कर्ज को लेकर व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अधिसूचना को इस वर्ष मई में वैध ठहराया था।

कोर्ट के फैसले के बाद एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक उन निदेशकों की सहभागिता का आकलन कर रहे हैं, जिन्होंने कर्ज को लेकर व्यक्तिगत गारंटी दी थी। एक अन्य बैंक के अधिकारी ने कहा कि बैंक वसूली प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत गारंटी को भुनाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में जाएंगे।

टेक्सटाइल पीएलआइ की नए सिरे से घोषणा संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने टेक्सटाइल से जुड़ी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम की समीक्षा शुरू कर दी है। पिछले वर्ष नवंबर में कैबिनेट कमेटी ने टेक्सटाइल क्षेत्र में पीएलआइ स्कीम के लिए 10,683 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इस स्कीम का अंतिम प्रारूप जारी नहीं किया गया है। टेक्सटाइल की पीएलआइ स्कीम में मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल को शामिल करने की बात है।

सेक्टर के उद्यमियों का कहना है कि इसमें कॉटन उत्पाद और गारमेंट निर्यात को भी शामिल करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही देश गारमेंट के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे स्पर्धियों का आसानी से मुकाबला कर सकेगा।

टेक्सटाइल पीएलआइ के मसौदे में 100-500 करोड़ रुपये राजस्व वाली कंपनियों को योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव में बदलाव किया जा सकता है।

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सिटी) के पूर्व प्रेसिडेंट संजय जैन के अनुसार छोटी कंपनियों तक समुचित लाभ पहुंचाने के लिए टर्नओवर की सीमा घटाए जाने की जरूरत है। यार्न और फैब्रिक को योजना में शामिल किए जाने से इनके निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में बांग्लादेश यार्न व फैब्रिक का भारत के मुकाबले चीन से अधिक आयात करता है।

कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, मगर महंगाई दर पर दबाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के चरम के बावजूद इस वर्ष मई का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष इसी माह के मुकाबले 29.3 फीसद बढ़ा है। यह बढ़ोतरी इसलिए भी दर्ज की गई है, क्योंकि पिछले वर्ष मई में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक उत्पादन खासा गिरा था। पिछले वर्ष मई में औद्योगिक उत्पादन में 33.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। मई में मैन्यूफैक्चरिंग व कैपिटल गुड्स में अच्छी बढ़ोतरी औद्योगिक उत्पादन के लिए शुभ संकेत है। कैपिटल गुड्स में मई में 85% की बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि आने वाले महीनों के लिए मैन्यूफैक्चरिंग की तैयारी जोरों पर है। इस वर्ष मई के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग में पिछले वर्ष मई के मुकाबले 34.5% का इजाफा रहा।

गिरावट के बावजूद 6.26 फीसद के स्तर पर खुदरा महंगाई, भारतीय रिजर्व बैंक के छह फीसद के लक्ष्य से ऊपर

दूसरी तरफ खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने लक्ष्य से बाहर रही। जून की खुदरा महंगाई दर 6.26% रही। हालांकि यह दर मई के 6.30% के मुकाबले कम है। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर भी कम होती नहीं दिख रही है। जून में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 5.15% के स्तर पर पहुंच गई जबकि मई में यह दर 5.01% थी। जून में खाने-पीने की चीजों में सिर्फ सब्जी के दाम में 1.94 फीसद और अनाज के दाम में 0.7 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से खुदरा महंगाई की अधिकतम सीमा छह फीसद निर्धारित की गई है। इस वर्ष अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.23 फीसद थी। जून में वनस्पति व तेल, फल, दाल, ईंधन, यातायात एवं संचार जैसे मद में दहाई अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर के इस स्तर पर पहुंचने से वस्तुओं की खपत कम हो सकती है, जो आर्थिक रिकवरी को प्रभावित करेगी। लगातार दो महीनों के दौरान खुदरा महंगाई दर छह फीसद से अधिक रहने के बावजूद आरबीआइ द्वारा अपनी अगली मौद्रिक समीक्षा में बैंक दरों पर कोई फैसला लेने की उम्मीद कम है। इसकी वजह यह है कि अच्छे मानसून को देखते हुए खरीफ की बेहतर बोआई से खुदरा महंगाई दर घट सकती है।

न्यूज गैलरी

इसरो जासूसी मामले के पीड़ितों की होगी सुनवाई

तिरुअनंतपुरम : केरल की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक सिबी मैथ्यूज की अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय से पहले वर्ष 1994 के इसरो जासूसी मामले के पीड़ितों को सुना जाएगा। अगली सुनवाई 14 जुलाई को है। (प्रेट्र)

मुंबई में 1.8 किलो हशीश के साथ महिला गिरफ्तार

मुंबई : नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई में 45 वर्षीय हुसैन बी को 1.8 किलो प्रतिबंधित नशीले पदार्थ हशीश के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि रविवार को जब्त नशीला पदार्थ जम्मू एवं कश्मीर से लाया गया था। (प्रेट्र)

मुख्यमंत्री कार्यालय स्टाफ की पत्नी की नियुक्ति पर हंगामा

तिरुअनंतपुरम : केरल विश्वविद्यालय के मलयालम लेक्सिकन विभाग में पूर्णिमा मोहन की नियुक्ति में सभी नियमों का उल्लंघन और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से जुड़े छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। पूर्णिमा मोहन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की पत्नी हैं। (आइएएनएस)

42 लाख लूटे, पुलिस देख 34 लाख फेंक दिए लुटेरे ने

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद जिले में सोमवार को दिनदहाड़े बाइक सवार लुटेरे रेडिएंट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों अरुण कुमार एवं रामनिवास सिंह से 42 लाख रुपये लूट लिए। अपने पीछे पुलिस को देख लुटेरों ने रुपयों से भरा बैग फेंक दिया, फिर भी वे आठ लाख रुपये ले भागे। पुलिस के अनुसार कर्मचारी पेट्रोल पंप से रुपये लेकर पंजाब नेशनल बैंक जमा करने जा रहे थे। (जासं)

पिता करता था पिटाई, मुरादाबाद से रोहतक पहुंचा

रोहतक : पिता की पिटाई से परेशान होकर बच्चे ने घर छोड़ दिया और ट्रेन में बैठकर मुरादाबाद से रोहतक पहुंच गया। चाइल्डलाइन की टीम ने बच्चे को जगन्नाथ आश्रम में भेजा। (जासं)

विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित सात पर दुष्कर्म का केस

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- अदालत के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज की एफआइआर
- पीड़िता केस दर्ज कराने को आठ माह से कर रही थी संघर्ष

पंजाब में अदालत के आदेश पर थाना डिविजन नंबर छह की पुलिस ने लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और आत्म नगर हलके के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित सात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धमकाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता करीब आठ माह से केस दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रही थी। विधायक बैंस के अलावा पुलिस ने केस में कोट मंगल सिंह की गली नंबर पांच के कर्मजीत सिंह, परमजीत सिंह, जसबीर कौर, ईशर नगर की बलजिंदर कौर, सुखचैन सिंह और पीए गोगी शर्मा को भी नामजद किया है।

44 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रापर्टी डीलर सुखचैन सिंह से जनवरी 2018 में उसकी मुलाकात हुई थी। उसने ईशर नगर में उसे 75 गज का मकान दिलवाया था। मकान का सौदा 18 लाख रुपये में हुआ था और 11 लाख रुपये पहले दिए थे। प्रापर्टी डीलर ने बैंक से 10 लाख का लोन लेकर दिया और उसकी एवज में 1.25 लाख रुपये लिए। मार्च 2018 में वह नए मकान में शिफ्ट हो गई। 26 अप्रैल 2019 को प्रापर्टी डीलर के घर में विधायक बैंस की बैठक थी। इसमें उसे भी बुलाया था। विधायक के साथ उसकी वह पहली मुलाकात थी। उसने बैंस को बताया कि वह एक इंटरनेट कंपनी में नौकरी करती है और उसके पति का देहांत हो चुका है। विधायक ने उनकी कंपनी की इंटरनेट सर्विस लेने के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। पति की मौत के कारण वह बैंक से लिए कर्ज की किस्तें जमा नहीं करवा पा रही थी। विधायक बैंस ने उसे और प्रापर्टी डीलर को एक दिन अपने दफ्तर बुलाया और समझौता करवा दिया। प्रापर्टी डीलर साढ़े चार लाख नकद और जस्सोवाल में 60 गज का प्लाट देने को मान गया, लेकिन बाद में मकान कब्जे में ले लिया।

बहराइच में सामूहिक दुष्कर्म, बोरे में बंद कर फेंका

जासं, बहराइच : उप्र के बहराइच में दबंगों ने अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। हालत गंभीर होने पर उसे बोरी में भरकर दूसरे गांव निवासी एक व्यक्ति के घर के बाहर फेंक गए। पुलिस ने किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा है। पीड़िता की मां ने तीन युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। बहराइच की पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी के पिता दिल्ली में श्रमिक हैं। बहराइच में मां के साथ रहने वाली किशोरी का रविवार देर शाम घर के बाहर से तीन युवकों ने अपहरण कर लिया। युवकों ने सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के बेहोश होने पर युवक उसे बोरी में भरकर दूसरे गांव निवासी युवक के बरामदे में फेंककर भाग निकले।

पांच नाबालिग छात्राओं का अपहरण, दो के साथ दुष्कर्म

जासं, गुमला : गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र स्थित एक सुदूरवर्ती गांव से पांच नाबालिग स्कूली छात्राओं का ट्रैक्टर चालक अमित केरकेट्टा ने अपने दोस्त जोनसन एक्का की मदद से नौ जुलाई की रात आठ बजे अपहरण कर लिया था। इसके बाद दो नाबालिगों के साथ पहले जंगल में दुष्कर्म किया, फिर उसे डुमरटोली निवासी जोनसन एक्का के घर ले गया। वहां भी दोनों नाबालिगों से दुष्कर्म किया। दो दिनों तक पांच नाबालिगों को उसी घर में बंधक बना कर रखा। मौका पाकर पांचों नाबालिग वहां से निकल भागी और अपने गांव पहुंचकर मामले की जानकारी स्वजनों को दी। इधर, पीड़िता के बयान पर मंडराटोली निवासी अमित केरकेट्टा व डुमरटोली निवासी जोनसन एक्का के खिलाफ केस दर्ज की गई है।

आवारा कुत्तों ने युवक को नोचा, साढ़े तीन घंटे सड़क पर तड़पता रहा, मौत

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर

- पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, युवक के कपड़े तक फाड़ दिए

आवारा कुत्तों ने रविवार रात ढाई बजे एक युवक को नोच-नोच कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक साढ़े तीन घंटे वह सड़क पर तड़पता रहा। सुबह छह बजे जब लोगों ने उसे देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस कर्मचारियों ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवक को एंबुलेंस से सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि गीता भवन रोड पर स्थित पेट्रोल पंप की तरफ से एक युवक मंदिर की तरफ जा रहा है। जैसे ही वह बीच रास्ते पहुंचा तो दोनों तरफ से आवारा कुत्ते उस पर टूट पड़े और नोचना शुरू कर दिया। उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। सुबह जब पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो युवक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। थाना सिटी के प्रभारी समीर एस मान ने बताया कि मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है।

गश्त कर रहे पीसीआर कर्मचारियों का निकलना भी दूभर : घटनास्थल पर पहुंचे पीसीआर के कुछ कर्मचारियों ने भी बताया कि रात को पेट्रोलिंग के लिए जब उनकी ड्यूटी गीता भवन रोड पर होती है तो वे आवारा कुत्तों के कारण इस सड़क से निकल नहीं पाते।

एक दुकानदार खिलाता था कुत्तों को कच्चा मांस : सीतामऊ रोड के कुछ लोगों ने बताया कि इसी रोड पर एक दुकानदार आवारा कुत्तों को रोजाना कच्चा मांस डालता था। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करने के साथ-साथ आवारा कुत्तों को कच्चा मांस डालने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करे।

भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी

जासं, बहराइच : रविवार रात 24 मिनट में सात बार इंटरनेट फोन करके बहराइच (उप्र) के महसी से भाजपा विधायक व उत्तर प्रदेश प्राक्कलन समिति के सदस्य सुरेश्वर सिंह को सुपारी किलर ने जान से मारने की धमकी दी। विधायक ने एसपी एवं डीएम को फोन कर व अपर मुख्य सचिव, गृह को पत्र भेज जांच कर कार्रवाई की मांग की है। महसी विधायक ने बताया कि रविवार की देर रात 10:21 बजे उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने अपने को सुपारी किलर बताते हुए कहा कि उसे सुपारी मिल चुकी है। फोन करने वाले व्यक्ति ने 10:45 बजे तक 24 मिनट के भीतर सात बार उन्हें फोन किया। विधायक ने बताया कि उन्होंने 10:47 बजे पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह और जिलाधिकारी दिनेश चंद्र को मामले से अवगत कराया। विधायक ने अपर मुख्य सचिव को भी पत्र भेजकर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने घटना का त्वरित संज्ञान लिया।

लोढ़ा के खिलाफ अवमानना याचिका मामले में दखल से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को खारिज करने के कलकत्ता हाई कोर्ट आदेश में दखल देने से सोमवार को इन्कार कर दिया। लोढ़ा के एमपी बिड़ला समूह की कंपनियों में निदेशक व चेयरमैन बने रहने को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के आदेश में हस्तक्षेप को इच्छुक नहीं है, क्योंकि याचिका अभी वहां लंबित है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लंबित याचिकाओं को किसी भी सूरत में 31 मार्च 2022 या उससे पहले निस्तारित करे।

लोढ़ा जिन कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें बिड़ला कारपोरेशन, यूनिवर्सल केबल्स, विंध्य टेलीलिंक्स व बिड़ला केबल शामिल हैं। बिड़ला के स्वजन व याचिकाकर्ता अरविंद कुमार नेवाड़ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, केके विश्वनाथन व जनक द्वारकादास ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट पूरी तरह गलत है। दूसरे पक्ष के वकील ने भी दलील पेश की।

अभियुक्त से सहानुभूति न्यायतंत्र को बना सकती है कमजोर

जासं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का काम अभियुक्त और अभियोजन के अधिकारों में संतुलन बनाए रखना है। निःसंदेह अभियुक्त के अधिकार महत्वपूर्ण हैं किंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपराधी जेल में हों, ताकि समाज में सही संदेश जाए। अभियुक्त के प्रति सहानुभूति न्याय तंत्र को कमजोर बना सकती है।

जुर्माने के खिलाफ याचिका पर एनबीई से मांगा जवाब

जासं, नई दिल्ली : विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) स्क्रीनिंग टेस्ट को टालने से इन्कार करते हुए जुर्माना लगाने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राधिकारियों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी किया है।

झूठी शान के लिए हत्या के आरोपित की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने झूठी शान (आनर किलिंग) की खातिर हत्या के एक आरोपित को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत रद कर दी है। मामला 2017 का है जिसमें केरल के एक युवक की कथित तौर पर अन्य जाति की राजस्थानी युवती से विवाह करने पर उसके ससुराल वालों के इशारे पर हत्या कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने मृतक अमित नायर के साले और आरोपित मुकेश चौधरी को मिली जमानत को 'बरकरार नही रखने योग्य' करार देते हुए मुकेश को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा, जिसे एक साल के अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी। पीठ ने कहा, 'अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए यह उचित होगा कि मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए।

जोड़े में से कोई एक भी नाबालिग, तो सहमति संबंध स्वीकार्य नहीं : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जोड़े में यदि दोनों में से केवल एक भी नाबालिग हो तो सहमति संबंध स्वीकार्य नहीं होते हैं। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने कहा कि वह दोनों बालिग हैं और सहमति संबंध में रह रहे हैं। लड़की ने बताया कि उसकी आयु 21 वर्ष है लेकिन उम्र से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि दोनों में से कोई एक भी बालिग नहीं है तो उस स्थिति में सहमति संबंध अस्वीकार्य हैं। लड़की और लड़के दोनों की आयु को सत्यापित करना जरूरी है।

सरकार के खिलाफ आदेश देने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं : हाई कोर्ट

कोच्चि, प्रेट्र : केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी सरकारी अधिकारी या वैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ सिर्फ इस आधार पर भ्रष्टाचार का केस या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा पारित कोई आदेश गलत है या सरकार के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने यह फैसला देते हुए सहायक बिक्री कर आयुक्त के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और उसके संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को रद कर दिया। अधिकारी के खिलाफ यह कार्यवाई इस आधार पर शुरू की गई थी कि उसने एक कंपनी को उसके द्वारा किए गए 50,18,606 रुपये के अतिरिक्त कर के भुगतान को वापस करने का आदेश दिया था, जिससे सरकार को नुकसान हुआ। जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने अधिकारी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। वाणिज्य कर आयुक्त ने शिकायत दर्ज करवाई कि अधिकारी ने आकलन संबंधित फाइलों को छोड़ दिया, संशोधित रिटर्न व खातों जैसे तथ्यों पर गौर नहीं किया।

दैनिक जागरण

मार्गदर्शन के अभाव में व्यक्ति कटी पतंग जैसा लक्ष्यहीन हो जाता है

गैर जिम्मेदाराना राजनीति

आतंकवाद निरोधक दस्ते की ओर से लखनऊ में अलकायदा के दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर सपा नेता अखिलेश यादव ने यह कह कर आतंकियों की ही तरफदारी की कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि उन्हें भरोसा उन पर है, जिन्हें आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया अथवा जो उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं? क्या यह अजीब नहीं कि अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं करना चाहते। क्या मुख्यमंत्री बनने की सूरत में वह पुलिस को भंग कर देंगे? क्या पुलिस उसी समय तक भरोसेमंद थी, जब वह मुख्यमंत्री थे? क्या वह यह चाहते हैं कि पुलिस को आतंकियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए या फिर उनसे पूछकर ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी? पता नहीं वह क्या चाहते हैं, लेकिन उनका बयान गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। इस पर हैरत नहीं कि अखिलेश यादव की तरह से मायावती ने भी अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी पर यह कहा कि चुनाव करीब आने पर पुलिस की इस तरह की कार्रवाई संदेह पैदा करती है। क्या चुनाव करीब हों तो पुलिस को आतंकियों की पकड़-धकड़ करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए और चुनाव खत्म होने का इंतजार करना चाहिए?

माना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कल्पना करना कठिन है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत नेता आतंकियों की पैरवी और पुलिस को हतोत्साहित करते दिखेंगे। क्या आतंकवाद से इस तरह लड़ा जाएगा? अखिलेश और मायावती के जैसे बयान सामने आए, उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की ताक में रहने वाले नेताओं की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया आए तो हैरानी नहीं कि उनकी ओर से गिरफ्तार आतंकियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हमारे देश में नेताओं का एक वर्ग ऐसा है, जो हर मसले पर सबसे पहले यह देखता है कि समुदाय विशेष के तुष्टीकरण में मदद मिलेगी या नहीं? इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनसंख्या नीति जारी होते ही इस तरह के बेतुके बयान सामने आ गए कि इसका मकसद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। आखिर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया? क्या यह जनसंख्या नीति केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू होगी या फिर इस नीति के विरोधियों की ओर से यह मान लिया गया कि यही वह समुदाय है, जिसे परिवार नियोजन की कोई फिक्र नहीं? वास्तव में यही वह गैर जिम्मेदाराना और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति है, जो तमाम गंभीर समस्याओं के समाधान में बाधा बनकर खड़ी होती है।

मिथ्या आरोप

दिल्ली सरकार कम पानी की आपूर्ति करने का मिथ्या आरोप हरियाणा पर लगा रही है। हरियाणा सरकार ने भी आरोपों पर अपना तथ्यपरक और तर्कसंगत उत्तर दिया है। वास्तव में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्डा जो हरियाणा पर पानी की कम आपूर्ति का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं, वह एक तरह से भयादोहन है और हरियाणा सरकार की छवि खराब करने का प्रयास है। यदि दिल्ली को वास्तव में हरियाणा से उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है तो उसे इसके साक्ष्य देने चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो स्पष्ट बता दिया है कि दिल्ली को नहर के माध्यम से मूनक में 1049 क्यूसेक पानी दिया जाता है। इसकी मात्रा बवाना प्वाइंट पर 950 क्यूसेक बनती है। इतना पानी हरियाणा अपनी तरफ से दिल्ली को निरंतर उपलब्ध कराता रहा है। हरियाणा ने तो यमुना में इस वर्ष लगभग 40 फीसद पानी की कमी होने पर भी दिल्ली को पूरा पानी दिया है। यह भी रेखांकित करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार की ही 2017 की इकोनामिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में पेयजल के कुप्रबंधन के कारण 20 फीसद पानी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार को इससे क्या? उसे तो हरियाणा पर आरोप लगाना है, बस। विचारणीय है कि हरियाणा को पंजाब उसके हिस्से का पानी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं दे रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी यह नहीं कहते कि पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। इसके विपरीत इस मुद्दे पर वह कहते रहे हैं कि जब पंजाब के पास पानी कम है तो वह हरियाणा को उसके हिस्से का पानी कैसे दे? अब इस तर्क के आधार पर हरियाणा भी कह सकता है कि जब हमारे पास पानी कम है तो हम दिल्ली को कहां से पानी दें? लेकिन नहीं। हरियाणा यह नहीं कहता। वह स्वयं पानी की कमी झेल कर दिल्ली को पानी देता है, इसलिए कि हरियाणा आरोपों-प्रत्यारोपों के बजाय पानी के प्रबंधन पर ध्यान देता है।

दिल्ली सरकार के कुप्रबंधन के कारण वहां पानी का संकट है और वह कम पानी की आपूर्ति का आरोप हरियाणा पर लगा रही है

आर्थिक असंतुलन दूर करे सरकार



भरत झुनझुनवाला

हमारे उद्यमियों के पास विश्व की अद्यतन तकनीक है और श्रम भी सस्ता है। ऐसे में हमारा निर्यात तेजी से बढ़ना चाहिए, लेकिन हो इसका उलटा रहा है

भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन का कहना है कि भारत का घरेलू बाजार छोटा है, इसलिए आर्थिक विकास के लिए निर्यात को बढ़ाना होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड के अनुसार चीन के निर्यात में 2019 की पहली तिमाही के मुकाबले 2021 की पहली तिमाही में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में दक्षिण एशिया, जिसमें भारत प्रमुख है, से होने वाले निर्यात में दो प्रतिशत की गिरावट आई है। यह तब है जब 2020 में हमें आशा थी कि कोविड के कारण चीन के विरुद्ध भड़क रही भावना से विश्व भर में चीन से कम माल खरीदा जाएगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से निकलकर दूसरे देशों में कारोबार बढ़ाएंगी। यह अनुमान सही साबित नहीं हुआ। कोविड के बावजूद जहां चीन का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, वहीं हम अपने पुराने बाजारों से भी फिसल रहे हैं। हमारी इस फिसलन का एक बड़ा कारण देश की नौकरशाही है। यह सही है कि सरकार ने तकनीकी सुधारों से निर्यातकों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और ईमानदार अधिकारियों की पदोन्नति दी है तथा भ्रष्ट अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर नौकरशाही का अवरोध बरकरार है। किसी उद्यमी को निर्यात का ऑर्डर सप्लाई करना था। सप्लाई की आखिरी तिथि आ चुकी थी। उनका कंटेनर बंदरगाह पर जहाज में लादे जाने के लिए रखा हुआ था। उस समय बंदरगाह के अधिकारी ने कहा कि वह कंटेनर में रखे 25-25 किलो के 1600 बक्सों में प्रत्येक का वजन चेक करेंगे। इसमें कम से कम दो दिन का समय लगता। तब तक निर्यात की तारीख निकल जाती। सरकार को नौकरशाही के मूल चरित्र को समझकर जमीनी नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए जन सहयोग की व्यवस्था करनी होगी। नौकरशाही सहयोग करे तो हम निर्यात में इजाफा कर सकते हैं।

विख्यात जर्मन दार्शनिक हेगेल ने कहा था कि मध्यम वर्ग पर नियंत्रण के लिए ऊपर से शासन और नीचे से जनता के दबाव, दोनों की जरूरत होती है। सरकार केवल ऊपर से सफाई कर रही है और नीचे से जनता का सहयोग नहीं ले रही है। इसी कारण नौकरशाही बेलगाम है। हमारे उद्यमियों के पास विश्व की अद्यतन तकनीक है। देश में श्रम भी सस्ता है। ऐसे में हमारा निर्यात तेजी से बढ़ना चाहिए, लेकिन हो इसका उलटा रहा है, क्योंकि नौकरशाही के अवरोध हमारे निर्यात पर ग्रहण लगा रहे हैं। नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक सरकारी दफ्तर से संबंधित उपभोक्ताओं की एक सक्षम निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए। नीति परिवर्तन के अभाव में निर्यात आधारित आर्थिक विकास कठिन दिखता है।



अवधेश राजपूत

सेवा क्षेत्र के निर्यात की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रपट के अनुसार सेवा क्षेत्र के मैनेजरों का खरीद सूचकांक (जो बाजार से खरीद करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है) फरवरी 2021 में 55.3 से घटकर मार्च 2021 में 54.6 रह गया। यानी सेवा क्षेत्र का भी संकुचन हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व बाजार में सेवा का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत के पास बड़ी संख्या में इंजीनियर और अंग्रेजी बोलने वाले युवा हैं। इनके द्वारा सॉफ्टवेयर इत्यादि उत्पादों को बनाकर निर्यात किया जा सकता है। इन संभावनाओं को भी हम पर्याप्त रूप से नहीं भुना पा रहे। इसका मूल कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य सिर्फ नौकरियां हासिल करने के लिए छात्रों को प्रमाण पत्र बांटना रह गया है। इस समस्या का भी हल निकालना होगा।

दूसरा विषय घरेलू मांग का है। हमारी आर्थिक विकास दर वर्ष पिछले कुछ समय से लगातार घटने पर है। अतः समस्या कोविड की नहीं, बल्कि कुछ समय से लागू आर्थिक नीतियों की है। विशेष यह है कि 2014 से हमारा सेंसेक्स उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष इसमें लगभग 15 प्रतिशत की और वृद्धि होगी और सेंसेक्स 58000 के स्तर को छू सकता है। कौतूहल का विषय है कि आर्थिक विकास दर गिर रही है और सेंसेक्स उछल रहा है। बताते चलें कि सेंसेक्स में मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों की भागीदारी होती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि समग्र अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है और इस संकुचन के बावजूद बड़े उद्यमी बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह दिखता है कि जीएसटी लागू करने से बड़े उद्यमियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजना आसान हो गया है, लेकिन यह छोटे उद्योगों पर भारी पड़ा। जीएसटी से बड़े उद्यमी बढ़े और छोटे उद्यमी संकुचित हुए।

नोटबंदी का भी ऐसा ही प्रभाव रहा, क्योंकि छोटे उद्यमी ही नकद में ज्यादा काम करते थे। सरकार ने हाईवे इत्यादि बुनियादी संरचना में भारी निवेश किए। ऐसे निवेश से भी बड़े उद्यमियों को लंबी दूरी तक माल ले जाने में सुविधा हुई। छोटे उद्यमियों का बाजार आसपास के क्षेत्रों में ही सीमित रहता है। हाईवे आदि बनाने में जो मशीनें और माल उपयोग किए गए जैसे जेसीबी, सीमेंट, स्टील, तारकोल इत्यादि, ये भी बड़े उद्यमियों के द्वारा ही बनाए और सप्लाई किए जाते हैं। विकास के इस मॉडल का परिणाम यह हुआ है कि छोटे उद्यमी समाप्तप्राय हो गए हैं। छोटे उद्यमियों के समाप्तप्राय होने से देश के आम आदमी की क्रय शक्ति घटी है, क्योंकि छोटे उद्यमों में ही अधिक संख्या में आम आदमी को रोजगार मिलते हैं। अतः घरेलू बाजार का संकुचन एक तरह से सरकारी नीतियों के कारण है।

मेरा तर्क जीएसटी, नोटबंदी और हाईवे के विरोध में नहीं है, परंतु इनसे जुड़ी समस्याओं पर विचार तो करना ही होगा। इसका एक उपाय है कि श्रम सघन उत्पादों और आम जन की खपत के उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाई जाए। बुनियादी संरचना में निवेश की दिशा को झुग्गी-झोपड़ियों और गांव में बिजली और सड़क की तरफ मोड़ा जाए, जिससे हमारे छोटे उद्योग पुनः बढ़ें, रोजगार के अवसर सृजित हों, घरेलू बाजार में मांग बने और अर्थव्यवस्था का विस्तार हो। इन कठिन परिस्थितियों के मेरे आकलन के विपरीत मई के प्रथम सप्ताह में देश के निर्यात में वृद्धि हुई है और बिजली की खपत भी बढ़ी। मेरा मानना है ये अकस्मात घटनाएं हैं, जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2014 से आज तक का रिकॉर्ड इसके विपरीत है। सरकार को चाहिए कि मौजूदा मुश्किल हालात को नीतिगत उपायों से दुरुस्त करे। अन्यथा हम फिसलते ही जाएंगे।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

सतह पर आया जनसंख्या का मसला



डॉ. जयंतीलाल भंडारी

एक ओर जहां जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर आबादी में कमी से भी बचना होगा



जनसंख्या नीति जारी करते योगी आदित्यनाथ। फाइल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की। इस नई जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, मातृ मृत्यु और बीमारियों के फैलाव पर नियंत्रण, नवजात और पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु रोकना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश की तरह देश के अन्य राज्यों में ही नहीं, वरन राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे बढ़ने की भी जरूरत है। ज्ञात हो कि इन दिनों देश की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अर्थिक-सामाजिक चुनौतियां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत में जहां एक ओर जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में कमी से भी बचना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में जहां देश में कुछ राज्य दो बच्चों की जनसंख्या नीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है। सप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, कृषि भूमि, पेयजल और अन्य मूलभूत जरूरतों की उपलब्धता की तुलना में जनसंख्या लगातार चिंताजनक स्थिति निर्मित करते हुए दिखाई दे रही है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि चूंकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में हैं, इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह नागरिकों के गुणवत्तापरक जीवन के लिए कड़े और प्रभावी नियम, कानून और दिशानिर्देश तैयार करे।

चूंकि संसाधनों को विकसित करने की रफ्तार जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है इसलिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की आर्थिक-सामाजिक समस्याओं की जननी बनकर विकास के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और सार्वजनिक सेवाओं की कारगर प्राप्ति जैसे मापदंडों पर बहुत पीछे नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मुद्दों पर प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत 131वें पायदान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। विश्व बैंक द्वारा तैयार 174 देशों के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का 116वां स्थान है। यह सूचकांक मानव पूंजी के प्रमुख घटकों स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्कूल में नामांकन और कुपोषण पर आधारित है।

यद्यपि इस समय करीब 141 करोड़ आबादी वाला चीन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का दर्जा रखता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जून 2019 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2027 तक सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने अपनी जनसंख्या नीति बनाई थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर आशा के अनुरूप निर्यंत्रित नहीं हो पाई। एक आकलन के मुताबिक 2020 में भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ पर पहुंच गई थी। दुनिया की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17.5 फीसद है, जबकि पृथ्वी के धरातल का मात्र 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही भारत के पास है।

एक ऐसे समय में जब चीन जनसंख्या और विकास के मॉडल में अपनी भूल संशोधित कर रहा है, तब जनसंख्या और अर्थ विशेषज्ञ चीन के जनसंख्या परिवेश से भारत को कुछ सीख लेने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मत है कि भारत में जहां एक ओर जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं जनसंख्या में ऐसी कमी से भी बचना होगा कि भविष्य में विकास की प्रक्रिया और संसाधनों का दोहन मुश्किल न होने पाए। मौजूदा परिवेश में यह जरूरी है कि 'हम दो हमारे दो' की नीति को दृढ़तापूर्वक अपनाया जाए। इससे जहां भविष्य में श्रमबल चिंताओं से दूर रहकर विकास की डगर पर लगातार आगे बढ़ा जा सकेगा, वहीं तेजी से बढ़ती जनसंख्या से निर्मित हो रही गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, शहरीकरण, मलिन बस्ती फैलाव जैसी कई चुनौतियों को निर्यंत्रित भी किया जा सकेगा।

इसमें कोई दो मत नहीं कि यदि देश में जनसंख्या नियंत्रित रही तो भारत के युवाओं को उपयुक्त शिक्षण और प्रशिक्षण से मानव संसाधन के रूप में उपयोगी बनाया जा सकता है। भारत की जनसंख्या में करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा उन लोगों का है, जिनकी उम्र 25 साल से कम है। ऐसे में वे कुशल मानव संसाधन बनकर देश के लिए आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। कोविड-19 के बीच देश के साथ-साथ दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को संभालने में भारत की कौशल प्रशिक्षित नई पीढ़ी प्रभावी भूमिका निभा रही है। वर्क फ्रॉम होम की प्रवृत्ति को व्यापक तौर पर स्वीकार्यता से आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला है। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत के आइटी सेक्टर द्वारा समय पर दी गई गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योग-कारोबार इकाइयों का भारत की आइटी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है।

हम उम्मीद करें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नीति और असम द्वारा तैयार की जा रही दो बच्चों की जनसंख्या नीति की तरह देश के अन्य प्रदेश भी आर्थिक और बुनियादी संसाधनों की चुनौतियों के बीच उपयुक्त जनसंख्या वृद्धि दर के लिए दो बच्चों की नीति तैयार करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेंगे। उम्मीद यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयुक्त दिश निर्देश देने के लिए आगे बढ़ेगा। इससे ही समाज और देश विकास की डगर पर अपेक्षित तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ज्ञानी कौन

परमात्मा ने मनुष्य को दस इंद्रियां उपहार में दी हैं। इनके माध्यम से वह सृष्टि से संपर्क स्थापित करने योग्य होता है। इनमें पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां। पांच ज्ञान इंद्रियों में कर्ण, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका हैं। सुनकर, देखकर, स्पर्श द्वारा, स्वाद और सुगंध द्वारा ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इंद्रियां परमात्मा की सत्ता और गुणों का ज्ञान अर्जन करने में सहायक हैं। ये मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती भी हैं।

माया के प्रभाव में मनुष्य इंद्रियों के वास्तविक उद्देश्य को उपेक्षित कर देता है। जिन इंद्रियों से उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर उसकी आराधना करनी थी उन्हें वह संसार के रस-रंग में लगा देता है। इंद्रियां जब वासनाओं के नियंत्रण में चली जाती हैं, तब परमात्मा विस्मृत हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आगे आ जाते हैं। जो नाशवान संसार है, उससे मोह हो जाता है। जो परमात्मा ने दिया है, उसे अपना मान अहंकार हो जाता है। मृत्यु जो जीवन मिलने के पहले ही सुनिश्चित हो गई है, उसे भूल मनुष्य सदियों की योजनाओं में व्यस्त हो जाता है। सुख जो परमात्मा से मिलना है, आनंद जो परमात्मा की भक्ति में है, उसे सांसारिक पदार्थों और सांसारिक संबंधों के घने मेघ ढक लेते हैं। माया के छलावे में वह उसे सुख समझ लेता है, जो अंततः दुख देने वाला है। इस तरह मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के दुरुपयोग का अपराधी बनता है।

परमात्मा के गुणों और सामर्थ्य का ज्ञान ही मनुष्य को जीवन और संसार का सच जानने योग्य बनता है। यह सच जाने बिना जीवन तो व्यतीत हो जाएगा, किंतु एक अंधकारमय सुरंग की भ्रमित यात्रा की तरह। मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को अज्ञान में गंवा देना परमात्मा से द्रोह है। जीवन पथ को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। यह ज्ञान इंद्रियों के सदुपयोग से ही संभव है। तभी जीवन की सार्थकता भी संभव है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

समस्या बढ़ा रही कृत्रिम रोशनी

अली खान

रात के समय में कृत्रिम रोशनी की जरूरत ने विभिन्न जीव-जंतुओं के जीवन को खासा प्रभावित किया है

हाल में ब्रिटेन की नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि प्रकाश के रंगों और तीव्रता में बदलाव के कारण जीव-जंतुओं की दृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन दुनियाभर में प्रकाश प्रदूषण के कारण बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति हमें सचेत करता है।

दरअसल रात के समय में इंसानों के लिए पड़ने वाली कृत्रिम रोशनी की जरूरत ने विभिन्न जीव-जंतुओं के जीवन को खासा प्रभावित किया है। कृत्रिम रोशनी की अत्यधिक तीव्रता ने छोटे-छोटे कीट-पतंगों पर एक तरह से विनाशी प्रभाव डाला है। मालूम हो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में इन छोटे-छोटे कीटों का अहम योगदान रहता है। ऐसे में इनका विनाश पारिस्थितिकीय असंतुलन को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कीटों पर पड़ने वाले कृत्रिम प्रकाश के प्रभाव को लेकर किए गए इस शोध से पता चला है कि पूरी दुनिया में रात के समय में प्रकाश व्यवस्था का स्वरूप पिछले करीब 20 वर्षों के दौरान नाटकीय रूप से बदला है। इन दिनों एलईडी जैसे विविध प्रकार के आधुनिक रोशनी वाले उपकरणों का चलन तेजी से बढ़ा है। यह स्वाभाविक है कि प्रकाश के प्रति कीटों का आकर्षण अधिक रहता है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था कीटों की दृष्टि को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है।

अध्ययन में पाया गया है कि कई कीटों की दृष्टि कुछ विशिष्ट प्रकार की रोशनी में बढ़ जाती है, जबकि प्रकाश के कुछ अन्य रूपों से इनकी दृष्टि बाधित होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि मानव दृष्टि के लिए डिजाइन की गई कृत्रिम रोशनी में नीली और पराबैंगनी श्रेणियों का अभाव होता है, जो इन कीटों की रंगों को देखने की दृष्टि क्षमता के निर्धारण में अहम होती हैं। यह स्थिति कई परिस्थितियों में किसी भी रंग को देखने की कीटों की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। यह कीटों को शिकारियों से बचकर छिपे रहने के लिए अनुकूल नहीं होती है। फूलों को खोजना एवं परागण करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे में प्रकाश की मात्रा एवं तीव्रता को सीमित करने के सामान्य प्रयासों से आगे बढ़कर प्रकाश व्यवस्था के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।

वास्तव में कृत्रिम प्रकाश से होने वाला प्रदूषण समस्त वातावरण को ही प्रभावित कर रहा है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। हमारी कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण के प्रति जागरूकता ही पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान कर सकती है। यदि हम कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि हम स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और कीटों के जीवन को भी बचा सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

दलित राजनीति का भविष्य

'नई करवट लेती दलित राजनीति' शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. एके वर्मा ने दलित राजनीति पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दरअसल दलित समाज सदियों से शोषित और पीड़ित रहा है। देश और उत्तर प्रदेश में बसपा के उदय के बाद दलितों का लगाव उसके साथ हुआ। बसपा के शासनकाल में दलितों का ही नहीं, बल्कि सर्वसमाज का भी सशक्तीकरण हुआ। बात यदि उत्तर प्रदेश की हो तो यहां पर बसपा, सपा, भाजपा क्रमशः पूर्ण बहुमत में सरकार बनाकर चला चुके हैं। इन दिनों दलितों के बीच इस तरह का विमर्श चल रहा है कि इन तीनों में से किसमें दलितों का सबसे कम उत्पीड़न और शोषण हुआ। इस विश्लेषण में बसपा ही भारी पड़ रही है। इतना ही नहीं बसपा को प्रत्येक चुनाव में मिले वोट का प्रतिशत भी बहुत कुछ स्पष्ट संकेत दे रहा है। इसलिए लेखक का यह कहना कि बसपा से दलित मतदाता छिटक रहे हैं उचित नहीं है। हां, सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग जरूरी होता है। अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मायावती को इस पर काम करना होगा। जहां तक दूसरे प्रदेशों में दलित राजनीति का सवाल है तो समावेशी राजनीति ही कारगर होगी, जिसका प्रयोग बसपा कर चुकी है। फिर भी अगले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कहना मुश्किल है?

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

खतरे की घंटी

महामारी के इस कठिन दौर में जहां लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं अधिक संख्या में लोग तनाव का भी सामना कर रहे हैं। छात्रों के अंदर पढ़ाई के साथ-साथ अपने भविष्य को लेकर तनाव बना हुआ है। वयस्क वर्ग घटती आमदनी और प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के कारण तनाव में है। ऐसे में तनाव से निजात पाने के लिए परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की जरूरत है। इसके अलावा मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी परेशानियों को भी साझा करें। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सामान्य बीमारियों में तो डॉक्टर से मिलते हैं, पर मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद 95 फीसद लोग मनोचिकित्सक के पास जाने से बचते हैं। तनाव ग्रस्त लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने उपचार पर ध्यान देने की जरूरत है। बीमारी को टालना खतरे को आमंत्रित करना है।

श्याम मिश्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय

कंपनियों को मिले वित्तिय प्रोत्साहन

संपादकीय पेज पर शिक्षा को चाहिए तकनीक का सहारा नामक आलेख पढ़ा। इसमें अमिताभ कांत ने वर्तमान अथवा भविष्य की शिक्षा में एडु-टेक नीतियों की अपार संभावनाएं तलाशने और उन्हें एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और भी तराशे जाने की जरूरत पर बल दिया है। आज यदि हम शिक्षा की उन्नति में अन्य देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं। अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में जिस डिजिटल सुधार की बात कर रहे हैं वह कुल सकल घरेलू उत्पाद के पिछली बार के आम बजट के अनुसार 4.4 फीसद खर्च को आधार बना कर कर रहे हैं, जबकि सकल घरेलू उत्पाद का यह हिस्सा सात फीसद अथवा इससे ऊपर होना चाहिए। एडु-टेक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एडु-टेक कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर आगे लाना होगा ताकि ये पूरे जोशोखरोश से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रसार को निश्चित बिंदु तक पहुंचा सकें। लेकिन यहां भी एक खामी यह नजर आती है कि एडु-टेक सेवाओं के लिए जीएसटी की दर को 18 फीसद रखा गया है जो उपयुक्त नहीं है। इस दर को पांच फीसद के आसपास कर देना चाहिए। हम सबको मालूम है कि कोरोना के नए नए स्वरूप के साथ आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समय की नजाकत को देखते हुए शिक्षा अथवा शिक्षण के क्षेत्र में हमें उन चुनौतियों पर बारीकी से काम करना होगा जो बाधाओं के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। इसके लिए केवल सरकार को ही नहीं, बल्कि उन तमाम हितधारकों को आगे आना होगा जो इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तभी हम अपनी इस शिक्षण पद्धति को तकनीकि रूप प्रदान कर सकते हैं।

पवन कुमार मुरली गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति यात्री की दर से बुकिंग शुरू की है रिचर्ड ब्रैंसन के मालिकाना हक वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने, जिसने कहा है कि दो टेस्ट फ्लाइट्स के बाद अगले साल वह अंतरिक्ष की व्यावसायिक उड़ानें शुरू करेगी।

आजकल

सामने आ रहे अंतरिक्ष पर्यटन के नए आयाम

लंबे समय से यह सपना शायद हजारों आंखों में पल रहा है कि अगर पैसे चुका सकें, तो क्या उन्हें कभी अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिल सकता है। अभी दो दिन पहले ही जब रिचर्ड ब्रैंसन अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के पांच अन्य कर्मचारियों के साथ रॉकेट में बैठकर न्यू मैक्सिको के ऊपर लगभग 80 किमी ऊंचाई तक अंतरिक्ष की सैर करके आए, तो इस संभावना को नए पंख मिल गए। आज की तारीख में दुनिया की दो कंपनियां इस मामले में आगे आई हैं, जिनसे यह उम्मीद जगी है कि भविष्य में रकम चुकाकर लोग अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं



डॉ. संजय वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा


अंतरिक्ष में उड़ान भरने की तैयारी में रिचर्ड ब्रैंसन (बाएं से दूसरे) के साथ अन्य अंतरिक्ष यात्री। इंटरनेट मीडिया

अंतरिक्ष में सैर करने की इंसान की पुरानी हसरत रही है। हालिया चर्चित अंतरिक्ष यात्रा से हमारा एक जुड़ाव भारतीय मूल की शिरीषा बांदला के जरिये भी होता है जो इस यात्रा पर गई थीं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद वह तीसरी महिला हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। रिचर्ड ब्रैंसन की हालिया यात्रा के एक साक्षी थे स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क, जो इसी तरह की यात्राओं के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही, उनके अभियान पर एक निगाह दुनिया के मशहूर कारोबारी जेफ बेजोस की भी रही, जो चंद दिनों बाद (20 जुलाई को) ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं। अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर इस कोरोना काल में नई सनसनी पैदा हो गई है। खास तौर से अरबपति अमीरों की ऐसी लंबी लिस्ट तैयार बताई जा रही है, जो आने वाले वक्त में अंतरिक्ष कही जाने वाली सरहद को छूकर लौटना चाहते हैं।

पर यहां कई सवाल हैं। जैसे निजी तौर पर पैसे खर्च करके अंतरिक्ष कही जाने वाली सीमा तक पहुंचने का मतलब क्या है। आखिर क्यों कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं। अगर इसमें कमाई की संभावना है, तो यह काम सरकारी स्पेस एजेंसियां क्यों नहीं कर रही हैं। क्या इसमें खतरे वाकई में इतने कम हो गए हैं कि जो व्यक्ति चाहे, विमान यात्रा की तरह अंतरिक्ष की सैर पर निकल सकता है। असल में इस यात्रा में अत्यधिक खतरों, खर्च और यात्रियों के कौशल के अलावा इन्हें संपन्न कराने वाले संगठनों की विशेषज्ञता का इतना ज्यादा महत्व रहा है कि प्राइवेट एजेंसियां प्रायः इसमें हाथ डालने से बचती रही हैं। ऐसे ज्यादातर कारनामे सरकारी स्पेस एजेंसियां ही कर सकीं। जैसे अब से करीब 20 साल पहले 28 अप्रैल, 2001 को स्पेस कंपनी 'स्पेस एडवेंचर' ने रूस की मदद से अमेरिकी पर्यटक डेनिस टीटो को रूसी रॉकेट सोयूज टीएम-32 और आइएसएस ईपी-1 नामक यान से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचाया था। टीटो दुनिया के ऐसे पहले टूरिस्ट बने थे, जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की थी।

सैर की भारी कीमत : अभी भी अंतरिक्ष की सैर इतनी सस्ती नहीं हुई है कि कोई शख्स किसी विमान यात्रा जितने खर्च में अंतरिक्ष का भ्रमण कर ले। लेकिन अब इस यात्रा का आनंद लेने वाले अमीरों की दुनिया में कमी नहीं है। वे इसके लिए अच्छी खासी रकम चुका सकते हैं। यही वजह है कि वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजन, स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में उतरकर भारी कमाई करना चाहती हैं। ब्रैंसन के मालिकाना हक वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने हाल में कहा है कि दो टेस्ट फ्लाइट्स के बाद अगले साल वह अंतरिक्ष की व्यावसायिक उड़ानें शुरू करेगी। इसके लिए उसने भी 600 लोगों से प्रति सीट ढाई लाख अमेरिकी डॉलर लेकर बुकिंग कर रखी है। उम्मीद की जा रही है कि टिकट की लागत जल्द ही घटकर 40 हजार डॉलर हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष की सैर और सुहावनी हो जाएगी। जहां तक स्पेस की सैर से कमाई का सवाल है तो स्विट्जरलैंड के एक बैंक का अनुमान है कि 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार तीन अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा।

निजी बनाम सरकारी : हाल के वर्षों में अंतरिक्ष यात्राओं के आंगन में निजी स्पेस एजेंसियों का दखल तेजी से बढ़ा है। अंतरिक्ष की निजी यात्राओं से ज्यादा इनका उद्देश्य विज्ञान-सम्मत था। पिछले ही साल ऐसे दो मौके आए, जब अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ने अपने रॉकेटों की मदद से अमेरिका और जापान के विज्ञानियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) तक सफलता से पहुंचाया। स्पेसएक्स ने ऐसा पहला अभियान 30 मई, 2020 को संचालित किया था जो सफल रहा था। उस यात्रा में फॉल्कन-9 रॉकेट से ड्रैगन कैप्सूल को कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। आइएसएस के लिए स्पेसएक्स की यह पहली निजी और सफल उड़ान 19 घंटे की रही थी। इस यात्रा में दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले शामिल थे। ये दोनों चार महीने तक आइएसएस पर रहे थे। यह उड़ान भी सफल रही और प्रक्षेपण के बाद 27.5 घंटे की उड़ान के बाद यान अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जा पहुंचा। इन दोनों अभियानों से विज्ञानियों को अंतरिक्ष में ले जाया गया गया था, लेकिन इन्हीं से यह उम्मीद जगी कि अब निजी स्पेस कंपनियां जल्द ही आम लोगों को भी अंतरिक्ष की सैर करने का अवसर दे सकेंगी।

लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर खुद नासा या कोई अन्य सरकारी स्पेस एजेंसी अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए निजी स्पेस एजेंसियों की सेवाएं क्यों लेने लगी है। नासा ने स्पेसएक्स के अलावा एक अन्य विमानन कंपनी बोइंग से वर्ष 2014 में इसका करार किया था कि भविष्य में यही कंपनियां उसके अंतरिक्ष विज्ञानियों को आइएसएस पर भेजने और वहां से वापस लाने का काम करेंगी और इसके बदले उन्हें एक निश्चित रकम दी जाएगी। हुआ यह है कि 21वीं सदी की शुरुआत में ही नासा ने अंतरिक्ष परिवहन के बढ़ते खर्च को देखते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने के काम से खुद को अलग करने की योजना तैयार कर ली थी। इसके बाद वर्ष 2003 में जब आइएसएस से लौटते वक्त उसका यान कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया (इसी हादसे में कल्पना चावला का निधन हो गया था) तो आइएसएस की शटल सेवाओं के लिए उसने खुद को पूरी तरह हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद वर्ष 2011 से वह इसके लिए पूरी तरह से रूस के रॉकेट सोयूज पर निर्भर हो गई। रूसी स्पेस एजेंसी इसके बदले में नासा से काफी मोटी रकम लेती रही है। अनुमान है कि नासा इसके काम के लिए यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) पर क्रू की आवाजाही के लिए उसे प्रति सीट नौ करोड़ डॉलर की भारी-भरकम रकम चुकाती रही है। हालांकि यहां यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि निजी एजेंसियां स्पेस ट्रैवल का काम अपने हाथ में लेंगी तो कहीं इससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। अंतरिक्ष यात्राओं के अतीत को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस तरह की यात्राओं में बड़ा जोखिम रहता है। पहले चैलेंजर और बाद में कोलंबिया, इन दो स्पेस शटलों की दुर्घटनाओं ने साबित किया है कि यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने से ज्यादा बड़ा खतरा पृथ्वी पर वापसी में रहता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्राओं संबंधी तकनीक में हुए सुधार और उसकी उपलब्धता ने इन खतरों को काफी कम कर दिया है। यही वजह है कि नासा जैसा संगठन अब करीबी अंतरिक्ष की यात्राओं के लिए निजी कंपनियों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है।

अधिक ऊंचाई पर आसान नहीं होता उड़ान भरना

पृथ्वी पर रहते हुए भी हम बह्मांड और अंतरिक्ष का हिस्सा हैं। इसलिए खुद को अंतरिक्षवासी भी कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वीवासियों की नजर से यह अंतरिक्ष वहां शुरू होता है, जहां से पृथ्वी के वायुमंडल और उसके गुरुत्वाकर्षण का दायरा खत्म होता है। ऐसी जगह पर जाकर वायु के दबाव और हवा की परतों में ऐसा अंतर आ जाता है कि विमानों की स्वाभाविक उड़ान संभव नहीं हो पाती। इस जगह को एक प्रतीकात्मक सीमा 'कैरमन लाइन' कहकर संबोधित किया जाता है। यह जगह पृथ्वी की सतह से करीब 100 किमी ऊपर है। अभी ज्यादातर स्पेस एजेंसियां पर्यटकों को इसी ऊंचाई तक ले जाने के अभियानों पर काम कर रही हैं। इस ऊंचाई पर जाकर अंतरिक्ष पर्यटक भारहीनता (जीरो ग्रैविटी) का अनुभव कर सकेंगे। साथ ही, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, वह देख सकेंगे। ऐसे कल्पनातीत नजारों के दर्शन कर सकेंगे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे।

आसान नहीं अंतरिक्ष यात्री बनना : बात चाहे विज्ञानियों को अंतरिक्ष में भेजने की हो या किसी पर्यटक को, यह काम बेहद मुश्किल है। ऐसे कई खतरे हैं जिनका सामना पूरी ट्रेनिंग के बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है। उनका सामना गहन अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों से हो सकता है। भारहीनता के दौरान उनके रक्तचाप में भी भारी उलटफेर हो सकता है। शायद यही वजह है कि अंतरिक्ष की यात्रा के लिए या तो विमान पायलटों को चुना जाता है या फिर उन्हें इसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सोवियत संघ (आज के रूस) और अमेरिका ने अपने ज्यादातर अंतरिक्ष अभियानों के लिए एयरफोर्स पायलटों का ही चुनाव किया है।

अंतरिक्ष में हमें पृथ्वी की तरह न तो आक्सीजन मिल पाती है और न ही संतुलित वायुदाब। सिलेंडर से मिलने वाली आक्सीजन के अलावा खतरनाक कॉस्मिक किरणों का मुकाबला अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है। इससे शरीर कमजोर होता है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और यात्रियों को भारहीनता (गुरुत्वहीनता) की स्थिति में रहना पड़ता है, इससे पैरों का काम खत्म हो जाता है। लिहाजा लंबा वक्त स्पेस में गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के पांव कमजोर हो जाते हैं। उन्हें वापस लौटने पर सामान्य होने में महीनों लग जाते हैं।

अंतरिक्ष अभियानों को अनेक दुर्घटनाओं के लिए भी याद रखा जाता है। चैलेंजर स्पेस शटल और कोलंबिया स्पेस शटल के हादसे तो इस मामले में एक बड़ी नजीर हैं। वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेसशिप अक्टूबर, 2014 में अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान ध्वस्त हो गया था। इससे वर्जिन गैलेक्टिक के अभियान को भारी धक्का लगा था। उस दौरान वर्जिन के स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्रा का आनंद लेने के लिए ब्रैड पिट और केटी पैरी जैसी हॉलीवुड की हस्तियों ने अपनी सीटें बुक की थीं, लेकिन टेस्ट फ्लाइट की दुर्घटना ने उनके सपने पर विराम लगा दिया। यही वजह है कि ऐसी कंपनियां अंतरिक्ष के पर्यटकों की सौ फीसद सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रही हैं। हालांकि उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के कुछ उपाय अपनाना अवश्य शुरू कर दिया है। जैसे वर्जिन ग्रुप ने अपने यान में एक ऐसा ग्लाइड-स्लोप सिस्टम अपनाने की बात कही है जो यान के खराब होने की दशा में यात्रियों को सुरक्षित धरती पर वापस ला सकता है। इसी तरह कॉस्मोकर्स नामक स्पेस कंपनी ने अपने यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट और वापसी के कैप्सूल में एक पैराशूट सिस्टम लगाने की बात कही है।

खरी-खरी

नेताजी की शोक प्रकटीकरण यात्रा

मुकेश राठौर

बबन भैया नेताजी को उनके राजगुरु ने मंत्र दिया था कि बेटा किसी के सुख में न सही, दुख में जरूर शामिल होना। बस इसी की गांठ बांधकर भिया अहर्निश लोगों का दुख बांटते रहे। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब कुछ दिन तक इन्हें कोई दुखी नहीं मिला, तो इन्होंने पहले अपनी हरकतों से किसी को दुखी किया और फिर उसका दुख बांटते हुए अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाई। मगर कोरोना काल में गुरुजी की आज्ञा का पालन न हो सका।

गाड़ी पर 'भैया को कार्यकर्ता शोक' का बैनर लगाकर तूफानी शोक यात्रा शुरू हुई। देखते ही देखते भैया ने उपचुनाव क्षेत्र के गांव के गांव निपटा दिए। अगर भैया निपटाने की योजना बना ही लें तो फिर गांव हो, सरकारी योजना का बजट हो या फिर विरोधी हो, सबको निपटा देते हैं। उनकी शोक यात्रा से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।

कार्यकर्ता चाहे ही क्या? भैया नाम से जानते हों, गमी में घर बैठने आते हों, उनके पांव नीचे बीसियों मुंडियों के बीच अपनी भी मुंडी हो, घर में टांगने को उनके साथ सेल्फी वाली एक फोटू हो... और फोन करने पर उठा लेते हों। यही तो असल पूंजी है। बाकी तो भैया की पूंजी देख-देखकर भी खुश रहा जा सकता है।

आज भैया वफादार स्वर्गीय कार्यकर्ता के घर बैठने पहुंचे, जो कोरोना की चपेट में देह परिवर्तन कर गया था। पहुंचते ही भैया शुरू हुए, 'बहुत बुरा हुआ, जल्दी चला गया। ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। जो आया है, उसे जाना ही है।' इतना कहने में ही माहौल बनता देख भैया कुछ-कुछ रोने टाइप हो गए। शोक-संतप्त लोगों के परिवार में 25 वोट देखकर उन्होंने अपना शोक की गति ओर बढ़ा दी, 'मेहरबान जी मेरे खास कार्यकर्ता थे, बल्कि पिता समान थे। मैंने उन्हें हाथखर्च हेतु एक पेटी दारू और लाख रुपये दिए थे। कभी हिसाब न लिया। मुझे उनके जाने की भनक लग जाती, तो जाने न देता।'

यह सुनते ही सभा में घोंट-मोट करवा कर बैठा मेहरबान सकपका गया, क्योंकि वह तो जिंदा था, मरे तो उसके बाऊजी थे। सभा में हंसी का फव्वारा छूट गया। अब सकपकाने की बारी भैया की थी।

ट्वीट-ट्वीट

यूरो फाइनल में हार के बाद इंग्लैंड में उपद्रव देखकर अचरज नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड हमेशा से रेसिस्ट रहा है। श्रेष्ठग्रंथि से नहाया हुआ अभिमानी देश। इनकी हरकतों को देखकर कल्पना करें, हमारे देश पर इन्होंने कैसे-कैसे जुल्म ढाए गए होंगे! ब्रिटिश हुकूमत के नस्लीय अपमान और अत्याचार की कहानियां बुजुर्गों से पूछिए।
मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

रोजर फेडरर का प्रशंसक होने के बावजूद मैं यह कह रहा हूं कि नोवाक जोकोविक टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं। वह सभी कोर्ट पर खुद को साबित कर चुके हैं। मुश्किल दौर में भी जीत दर्ज की। कई बार जबरदस्त वापसी की। मुझे उम्मीद है कि इतिहास उन्हें उनका वह हक जरूर देगा, जो मौजूदा दौर के टेनिस पत्रकार और लेखकों ने नहीं दिया।
हार्दिक राजगोर@Hardism

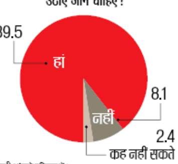


अगर हम इस दुनिया को बचाने के प्रति गंभीर हैं तो फिर हमें बढ़ती हुई आबादी के प्रगतिशील खाके को अवश्य अपनाना होगा।
अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

क्या पूंजीवाद कभी जनसंख्या नियंत्रण अभियान को सफल होने देगा? उसके अनुसार तो जितने अधिक लोग होंगे, उतने ही ज्यादा खरीदार बढ़ेंगे।
विवेक रंजन अग्निहोत्री@vivekagnihotri

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

काकोरी के नाम पर मढ़ने चले कलंक,
एक मियां अशफाक थे ये बिच्छू के डंक।
ये बिच्छू के डंक कुचलिए इनको योगी,
अब इन पर ना बोल रहा है कोई ढोंगी।
याद करो अशफाक और बिस्मिल की जोड़ी,
जिनके कारण तीर्थ बन गया है काकोरी।
- ओमप्रकाश तिवारी



जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

विधान परिषद के नाम पर भी होगा 'खेला'

विधानसभा चुनाव में 'खेला होबे' यानी 'खेल होगा' का नारा बुलंद कर जीत दर्ज करने के बाद अब मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधान परिषद के नाम पर भी 'खेला' करने की तैयारी में हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद गठित करने पर मुहर लगाने के बाद गत छह जुलाई को विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करा लिया। अब अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं। परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 52 साल बाद फिर से बंगाल में विधान परिषद गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? बंगाल में 1969 में विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी, 2021 तक इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मार्च, 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए ममता ने घोषणा कर दी कि जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, उन सभी को विधान परिषद गठित कर उसका सदस्य बनाया जाएगा। उस समय माना गया था कि ऐसा पार्टी में बगावत रोकने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2011 में भी ममता ने विधान परिषद गठित करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्ताव पारित हो चुका है और अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी हो रही है। यहीं से असली खेल शुरू होने के आसार हैं।

केंद्र के साथ ममता के संबंध कैसे हैं, यह जगजाहिर है। हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ वह मुखर रहती हैं। ऐसे में विधान परिषद के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार 'धीरे चलो' की नीति अपना सकती है। कई वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवा कर ममता सरकार ने केंद्र को भेजा था, लेकिन आज तक नाम परिवर्तन नहीं हो सका है। अगर ऐसा ही हाल विधान परिषद के प्रस्ताव का हुआ तो ममता एक ओर इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़कर केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा बना सकती हैं, वहीं दूसरी ओर अपने नेताओं को कहेंगी कि केंद्र की वजह से वह अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही हैं।


बीते विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 'खेला होबे' नारा लगाने के साथ कुछ इस तरह फुटबॉल को भीड़ में उछाला करतीं थीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इंटरनेट मीडिया

यही नहीं, जब प्रस्ताव पारित हुआ था, तब ममता ने कहा था कि वाममोर्चा का विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। अगर विधान परिषद गठित होता है तो उसमें उन्हें जरूर सदस्य के रूप में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान में भी सियासी स्वार्थ निहित है। उन्हें पता है कि इस बार वामपंथी वोट भी उन्हें मिले हैं इसलिए उन्हें आगे भी जोड़े रखने व इस मुद्दे पर वाम नेताओं का समर्थन प्राप्त करने का भी यह सहानुभूति संदेश हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि मंजूरी मिल भी जाती है तो विधान परिषद आर्थिक बदहाली झेल रहे बंगाल के लिए एक और बोझ होगा। पहले से ही राज्य पर चार लाख करोड़ से अधिक के ऋण का बोझ है। हालत यह है कि सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशन भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। लिहाजा भाजपा ने विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। माकपा व कांग्रेस के भी कई नेता हैं, जिनका कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है।

वैसे बंगाल में विधान परिषद का इतिहास कुछ इस तरह रहा है। वर्ष 1935 के भारत सरकार के एक्ट में बंगाल को दो सदनों में बांटा गया, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा शामिल थे। विधानसभा का कार्यकाल पांच साल और सदस्यों की संख्या 250 की गई थी जबकि काउंसिल के सदस्यों की संख्या 63 से कम नहीं और 65 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। हर तीन साल बाद एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता था, परंतु आजादी के बाद 1952 में बंगाल में विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था रखी गई। इसमें 51 सदस्यों वाले बंगाल विधान परिषद का गठन पांच जून, 1952 को किया गया और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 240 थी, जिनमें एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो मनोनीत सदस्य शामिल थे। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 21 मार्च, 1969 में बंगाल से विधान परिषद को खत्म कर दिया। बंगाल में यदि विधान परिषद गठित होगा तो नियमों के मुताबिक 294 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में अधिकतम विधान परिषद के 98 सदस्य होंगे। यह विधानसभा में पहुंचने का पिछला दरवाजा है।

इस समय जिन छह राज्यों में विधान परिषद हैं, उनमें से तीन राज्यों के मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बिहार में नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ममता भी अभी विधानसभा सदस्य नहीं हैं। अगर विधान परिषद होता तो उन्हें भी चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती।

मंथन



प्रो. उमेश चंद सिंह यादव
स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

इंसुलिन आविष्कार के सौ साल

इंसुलिन के आविष्कार के बाद से मधुमेह पीड़ितों के जीवन में न केवल एक नई आशा का संचार हुआ, बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है

यद्यपि कोरोना जनित महामारी ने वर्तमान में हमारे जीवन में उथल-पुथल मचा रखा है, परंतु इससे अलग बीमारियों के संदर्भ हमारे देश को डायबिटीज (मधुमेह) की राजधानी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो मधुमेह प्राचीनतम बीमारियों में से एक है और इसके बहुत तरह के उपचार अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में सुझाए गए हैं, परंतु आज हम सौ वर्ष पूर्व हुए एक ऐसे आविष्कार के बारे में चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक समय में मधुमेह के उपचार को नया स्वरूप दिया।

हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं जिसकी शतकीय वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जा रही है। आज से सौ वर्ष पहले 1921 में इंसुलिन को कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने जॉन मैक्लिओड के निर्देशन में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इस आविष्कार को सर्वप्रथम एक 14 वर्ष के मधुमेह रोगी लियोनार्ड थॉम्पसन पर 1922 में आजमाया गया। थॉम्पसन टाइप वन मधुमेह रोग से पीड़ित थे जो अक्सर बच्चों में होती है और इसमें रोगी के अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता। इंसुलिन न बनाने के कारण थॉम्पसन का ब्लड शुगर हमेश बढ़ा रहता था, परंतु बेंटिंग और बेस्ट द्वारा तैयार किए गए इंसुलिन के इंजेक्शन से उनका शुगर नियंत्रित हो गया। इस प्रकार दुनिया को मधुमेह के उपचार के लिए नई दवा मिली।

इंसुलिन के आविष्कार से पहले विज्ञानियों को यह पता था कि अग्नाशय किसी न किसी तरह मधुमेह के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 1889 में ऑस्कर मिन्कोवस्की और जोसफ वॉन मेरिंग ने पता लगा लिया था कि अग्नाशय को नष्ट करने पर कुत्तों में मधुमेह हो जाता है। अपने प्रयोगों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अग्नाशय में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिसे यदि निकाल कर ऐसे जानवर को दिया जाए जिसे मधुमेह है तो उसे मधुमेह के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। अब तक यह तो साफ हो चुका था कि अग्नाशय में स्थित कोई कोशिका समूह ही शरीर में बढ़े शुगर को नियंत्रित करती है, परंतु इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं था। वर्ष 1893 में लगुस्से ने सुझाया कि लैंगरहैंस की कोशिकाएं कुछ ऐसी चीजें स्रावित करती हैं जो शरीर में शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है।

अब मिन्कोवस्की और मेरिंग के कार्य को आगे बढ़ाया बेंटिंग ने। बेंटिंग टोरंटो विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान की डिग्री प्राप्त कर एक सर्जन के पद पर कार्यरत थे। एक मेडिकल स्कूल में अपने एक व्याख्यान की तैयारी के संदर्भ में अक्टूबर 1920 में बेंटिंग के हाथ मोसेस बरों का एक लेख लगा। इस लेख में कहा गया था कि यदि अग्नाशय की एसिनर ग्रंथियों से पाचक रस लाने वाली नलिकाओं को बांध कर बंद कर दिया जाय तो कुछ दिनों में एसिनर कोशिकाएं मर जाती हैं और पाचक रस जैसे कि ट्रिप्सिन आदि का स्राव बंद हो जाता है। बेंटिंग के मन में एक विचार कौंधा जो इंसुलिन के परिष्करण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। उनका विश्वास था कि अग्नाशय में बनने वाले एंजाइम या पाचक रस इंसुलिन को परिष्करण प्रक्रिया के दौरान नष्ट कर देते हैं। इस विचार से उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय के जॉन मैक्लिओड को अवगत कराया जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर अनुसंधान करते थे। इस प्रकार जॉन मैक्लिओड के निर्देशन में बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इस प्रयोग का कार्य शुरू किया।

उन्होंने कुत्तों में अग्नाशय की नलिकाओं को बांध दिया और सात सप्ताह के बाद पाया कि अग्नाशय का आकार घट कर एक तिहाई रह गया। उन्होंने उन अग्नाशयों से निकाले गए रस को उन कुत्तों को इंजेक्शन से दिया जिन्हें अग्नाशय निकाल लिए जाने से मधुमेह हो गया था। इससे मधुमेह पीड़ित प्रयोग में शामिल कुत्तों में शुगर का स्तर घट कर सामान्य हो गया। इतना ही नहीं, कुत्तों में मधुमेह के लक्षणों में बहुत सुधार हुआ, उनकी जिजीविषा लौट आई, उनके घाव शीघ्र भर गए और वे अन्य मधुमेह पीड़ित कुत्तों से ज्यादा दिनों तक जीवित रहे।



इंसुलिन के आविष्कार से लेकर अब तक मधुमेह के इलाज में काफी प्रगति हुई है। प्रतीकात्मक

इस प्रकार अनगिनत विज्ञानियों के इतने वर्षों के सतत प्रयास को अंततः सफलता मिली और डायबिटीज को मात देने के लिए किए गए इस आविष्कार ने मधुमेह से पीड़ितों को सामान्य जीवन जीने की आशा से भर दिया। इस आविष्कार के लिए बेंटिंग और मैक्लिओड को 1923 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

इंसुलिन के आविष्कार के बाद से अब तक इस दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। पिछली शताब्दी के आठवें दशक तक आते आते इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से रेकॉम्बीनैंट डीएनए तकनीक से बनाया जाने लगा जिसे 'ह्यूमन इंसुलिन' कहा गया। यह इंसुलिन वैसा ही होता है जैसा हमारा शरीर बनाता है और यह अत्यंत शुद्ध होता है। इस पद्धति से बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन का निर्माण होने से करोड़ों रोगियों को इंसुलिन आसानी से प्राप्त हो पाता है। इंसुलिन के आविष्कार के सौ वर्षों के बाद भी मधुमेह रोगियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे बढ़ाने में मोटापा, खानपान की पाश्चात्य पद्धति, आरामतलब जीवनशैली, मशीनीकरण और कई अन्य कारण जिम्मेदार हैं। इंसुलिन मधुमेह को नियंत्रित तो कर सकता है, परंतु मधुमेह हो ही नहीं, इसके लिए हमें सतत अध्ययन और प्रयास करते रहने व इंसुलिन जैसे ही नए आविष्कारों की आवश्यकता है।

2.46 रुपये मिलती है ओडिशा को प्रति यूनिट बिजली। झारखंड को 4.04 रुपये, बिहार को 4.26 रुपये, उत्तर प्रदेश को 4.45 रुपये और आंध्र प्रदेश को 4.71 प्रति यूनिट बिजली मिलती है। यह जानकारी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट में दी गई है।

उत्तराखंड

बिजली से लुभाने की कोशिश

उत्तराखंड में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल मुफ्त बिजली के मुद्दे के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के मंसूबे बांधने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी का इस्तेमाल कर पूर्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। उत्तराखंड में भी वह इसी मुफ्त के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब राज्य की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी से यह मुद्दा लपकने की पहल कर दी है। ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देगी और जो उपभोक्ता 200 यूनिट तक खर्च करेगा, उसे बिल में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। हालांकि अभी यह केवल घोषणा ही है, क्योंकि अमलीजामा पहनाने के लिए इसे कैबिनेट से पारित कराना होगा।

> सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने की बात कहने से पहले राजनीतिक दलों ने संसाधन बढ़ाने की रणनीति बनाई होती तो बेहतर रहता

वैसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले उत्तराखंड के लिए मुफ्त बिजली देने से आने वाले भारी भरकम व्यय को वहन करना आसान नहीं होगा। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है, जिसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। इस घोषणा के अमल में आने की स्थिति में लगभग साढ़े सात लाख परिवारों को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। ऊर्जा मंत्री की मानें तो सरकार जल्द कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराकर इस व्यवस्था को लागू कर देगी। इस पर आने वाले खर्च को जलविद्युत निगम और विद्युत पारेषण निगम के लाभ से वहन किया जाएगा। साफ है कि भाजपा की रणनीति मुफ्त बिजली के मुद्दे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में न करने देने की है।

उधर अब कांग्रेस ने भी मुफ्त बिजली के वादे पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वैसे यह सवाल भी अपने आप में खासा अहम है कि क्या यह मुद्दा उत्तराखंड में जनमत पर असर डालेगा। सवाल यह भी कि क्या आय के सीमित संसाधन वाले उत्तराखंड में इस तरह की परिपाटी को बढ़ावा दिया जाना उचित रहेगा। बेहतर होता कि इस तरह की रियायत की बात करने से पहले राजनीतिक दल संसाधन बढ़ाने की रणनीति तय करते। यह तय है कि अगर भाजपा की प्रदेश सरकार मुफ्त या रियायती बिजली विधानसभा चुनाव से पहले ही उपभोक्ताओं को देना शुरू कर दे तो आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा।

इसके अलावा हमें मुफ्त की राजनीति से बाहर निकलने की भी दरकार है। जनता को मुफ्तखोरी की आदत लगाना सही नहीं है। अंततः इसका खामियाजा उसे ही किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ती है। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है।

पंजाब

विरोध के नाम पर अराजकता

देश के संविधान ने हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस अधिकार की आड़ में अराजकता का प्रदर्शन किया जाए। दुर्भाग्य से पंजाब में कुछ माह से ऐसा ही हो रहा है और पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कानूनों से उनकी असहमति हो सकती है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में बार-बार घुस जाने, वहां तोड़फोड़ करने, नेताओं की पिटाई करने को तो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है।


राजनीतिक विरोध के नाम पर तोड़-फोड़ जैसी गतिविधियां उचित नहीं हैं। फाइल

> राजपुरा में भाजपा की बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा नेताओं की पिटाई करने का मामला अत्यंत गंभीर है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह कठघरे में है

रविवार को पटियाला के राजपुरा में भाजपा की बैठक में जिस तरह से नेताओं की पिटाई की गई उससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह मामला इसलिए गंभीर है, क्योंकि प्रदेश में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले होशियारपुर, जालंधर, बठिंडा, फिरोजपुर सहित कुछ और जिलों में ऐसी अराजकता का प्रदर्शन किया जा चुका है। भाजपा के नेता यदि आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के हमलों में पुलिस की मिलीभगत है और उत्पात करने वालों में भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं तो इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। भाजपा को यदि कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है तो सरकार खुद सोचे कि क्या प्रदेश में वाकई लोकतंत्र है? लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी की आवाज को दबाने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रदेश सरकार को यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन ऐसी अराजकता को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है? यदि सियासी फायदे के लिए इस तरह की घटनाओं से मुंह मोड़ा जाएगा तो भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज भाजपा के साथ जो कुछ हो रहा है वैसा दूसरी पार्टियों के साथ नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेहतर यही होगा कि प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता को समझे और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। किसी को भी प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश

आतंक की विषबेल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को अलकायदा समर्थित संगठन अंसार गजवातुल हिंद के दो आतंकियों का पकड़ा जाना बड़े खतरे की निशानी है। यह इसलिए भी, क्योंकि आतंकी संगठन स्थानीय युवकों को बरगलाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ दशक पहले तक आजमगढ़ जिला ही आतंक की नर्सरी के रूप में कुख्यात था। मगर हाल के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई जिलों में आतंकवाद की जड़ें गहरी हुई हैं। खासकर संभल, मुजफ्फरनगर, कानपुर, लखनऊ जैसे कई जिलों तक आतंक की विषबेल पांव पसार चुकी है। ऐसी ही स्थितियां मिलने पर वर्ष 2016 में दिल्ली पुलिस ने एक कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में संभल जिले को अलकायदा का गढ़ तक करार दिया था। कारण यह कि जिन 17 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दी गई थी, उनमें से छह संभल के ही निवासी थे।


एटीएस द्वारा गिरफ्तार आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन। फाइल

> गिरफ्तार आतंकियों के घर पर कई संदिग्ध लोगों का अक्सर आना जाना रहता था, लेकिन इसकी जरा-भी भनक नहीं लगना यह बताता है कि खुफिया तंत्र को अभी और चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है

दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और उसकी छांव में फल-फूल रहे लश्कर ए तैयबा और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों ने एजेंटों के जरिये स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी सोच में ढालने, ट्रेनिंग देने और फंड मुहैया कराने का जिम्मा उठा रखा है। ये एजेंट स्थानीय लोगों को लालच देकर फंसाते हैं और फिर देश विरोधी मानसिकता विकसित करने में जुट जाते हैं। लखनऊ में पकड़े गए लोग भी ऐसी ही एक कड़ी का हिस्सा हैं। इनके इरादे इतने खतरनाक थे कि राजधानी व आसपास के कई बड़े जिलों में सीरियल बम ब्लास्ट करके देश को दहला देना चाहते थे। अच्छा हुआ कि समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को लखनऊ में रह रहे आतंकियों के मंसूबों का पता चल गया। यद्यपि यह सवाल अनुत्तरित है कि स्थानीय खुफिया इकाई को स्थानीय युवकों की गतिविधियों की जरा-भी भनक क्यों नहीं लगी। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकियों के घर कई संदिग्ध लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। बावजूद इसके किसी के कान खड़े नहीं होना यह बताता है कि अभी खुफिया तंत्र को और चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है।

बंगाल

फर्जी काल सेंटर और धोखाधड़ी

पिछले एक सप्ताह में कोलकाता महानगर के अलग-अलग इलाकों में तीन फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में दो दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस तरह के फर्जी काल सेंटर और साइबर अपराधों से हमारे देश के डिजिटल इंडिया मुहिम को पलीता ही लग रहा है। कोरोना महामारी के काल में लोगों का डिजिटल लेनदेन से लेकर इंटरनेट पर निर्भरता काफी बढ़ी है। परंतु जिस तरह से कभी जामताड़ा गैंग तो कभी फर्जी काल सेंटर तो कभी विदेशी साइबर अपराधी बार-बार लोगों को जाल में फंसाकर जालसाजी कर रहे हैं उससे लोगों का डिजिटल लेनदेन से भयभीत होना लाजिमी है। इस तरह के अपराध कहीं न कहीं हमारे देश के डिजिटल अभियान के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं।

> बंगाल सीआइडी ने कोलकाता के निकटवर्ती राजारहाट इलाके से फर्जी काल सेंटर चलाने और आसानी से ऋण देने की बातें कहकर लोगों से ठगी के आरोप में 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है

अभी एक दिन पहले ही बंगाल सीआइडी ने कोलकाता शहर के निकटवर्ती राजारहाट इलाके से फर्जी काल सेंटर चलाने और आसानी से ऋण देने की बातें कहकर लोगों से ठगी के आरोप में 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपराधिक जांच विभाग (सीआइडी) के साइबर अपराध सेल में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने राजारहाट न्यूटाउन में एक ऊंची इमारत से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपित देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को काल करते थे और प्रतिष्ठित कंपनियों से आसान ऋण मुहैया कराने के बहाने उनसे ठगी करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों से 40 मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। इससे पहले कोलकाता पुलिस की साइबर सेल ने विदेशी नागरिकों को ठगने के मामले में तपसिया और साल्टलेक में दो काल सेंटर में अभियान चलाकर 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी कोलकाता में बैठकर विदेश में लोगों से ठगी कर रहे थे। ऐसे काल सेंटर से लेकर जामताड़ा और अन्य जगहों से संचालित होने वाले साइबर अपराध पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ साइबर थाना खोलने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। ऐसी ठोस पहल करनी होगी कि साइबर अपराधियों समय रहते दबोचा जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग डिजिटल लेनदेन के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, जो कहीं न कहीं हमारे देश के डिजिटल इंडिया अभियान को पीछे ले जाएगा। यदि साइबर अपराध का धंधा फलफूल रहा है तो इसकी मुख्य वजह सुरक्षा एजेंसियों की सुस्ती ही है। पुलिस के पास साइबर विशेषज्ञों की कमी से भी ऐसे अपराधियों को हौसला मिल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका विचारार्थ स्वीकार की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

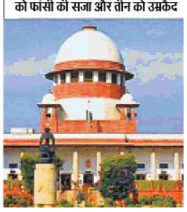
सेनारी नरसंहार मामला

- सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 14 अभियुक्तों को पटना हाई कोर्ट ने 21 मई को कर दिया था बरी
- सत्र अदालत ने सुनाई थी 11 अभियुक्तों को फांसी की सजा और तीन को उम्रकैद

सुप्रीम कोर्ट ने सेनारी नरसंहार में सभी 14 अभियुक्तों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका सोमवार को विचारार्थ स्वीकार कर ली है। हाई कोर्ट ने गत 21 मई को साक्ष्यों के अभाव में सभी 14 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। जबकि सत्र अदालत ने इन 14 अभियुक्तों में से 11 को फांसी और तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

बिहार का जहानाबाद जिला जो अब अरवल हो गया है, के सेनारी गांव में 18 मार्च 1999 को 34 लोगों की सामूहिक हत्या की गई थी। इस मामले में सत्र अदालत ने 2016 में 14 लोगों को दोषी ठहराया था जिसमें से 11 को फांसी और 3 को उम्रकैद की सजा दी थी। पटना हाई कोर्ट ने गत 21 मई को साक्ष्यों के अभाव में सभी 14 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सोमवार को जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने बिहार सरकार की ओर से पेश वकील अभिनव मुखर्जी की दलीलें सुनने के बाद प्रदेश सरकार की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली। वकील मुखर्जी ने याचिका विचारार्थ स्वीकार होने के बाद कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो वे अरवल के एसपी के जरिये अभियुक्तों को नोटिस सर्व करा सकते हैं लेकिन पीठ ने कहा कि सामान्य अनुक्रम में ही नोटिस जाने दें। बिहार सरकार ने इस मामले में दो विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। एक में 13 अभियुक्तों को बरी किये जाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इन 13 में से 10 अभियुक्तों को सत्र अदालत से फांसी की सजा हुई थी जबकि तीन को उम्रकैद। दूसरी याचिका में एक अभियुक्त को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी गई है इस अभियुक्त को सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।


सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

बिहार सरकार ने याचिका में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला देने में कानून के तय सिद्धांतों की अनदेखी की। कहा गया है कि एक केस में 13 और दूसरे में नौ चश्मदीद गवाह हैं लेकिन हाई कोर्ट ने गवाही में मामूली अंतर पर चश्मदीदों की गवाही अस्वीकार कर दी। केस डायरी में नाम न होने के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा गवाहियों को नकारना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुका है कि कोर्ट में दिया गया बयान ही मान्य होता है। बिहार सरकार का कहना है कि छोटी मोटे अंतर के आधार पर गवाहियां नकारना ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानदंडों के मुताबिक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी अभियुक्त ने घटना पर सवाल नहीं उठाया है और न ही अभियुक्तों ने ये कहा है कि घटना की एफआइआर तत्परता से दर्ज नहीं हुई।

34 लोगों का हुआ था नरसंहार : सरकार ने कहा कि यह एक बड़ा सामूहिक नरसंहार था जिसमें 34 लोगों की जान गई थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 गवाह पेश किये जिसमें से 13 वे लोग थे जिन्होंने इस घटना मे अपनों को खोया था। केस का जांच अधिकारी खुद घायलों को अस्पताल भेजने और मृतकों के पोस्टमार्टम की तैयारी और मौके की रिपोर्ट तैयार करने में शामिल था। हाईकोर्ट ने घटना के प्रभाव पर विचार किए बगैर सत्र अदालत के फैसले को तकनीकी अधार पर परीक्षित करके अभियुक्तों को बरी कर दिया।

कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार के यू-टर्न पर कोर्ट में अर्जी दाखिल

जागरण संवाददाता, नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट में हलफनामे के बाद अब कांवड़ यात्रा पर विचार करने का उत्तराखंड सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब याचिकाकर्ता अनु पंत के अधिवक्ता अभिजय नेगी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। इसमें मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उप्र सरकार के दबाव में कांवड़ यात्रा के मामले में पुनर्विचार का जिक्र किया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार की एसएलपी को खारिज करने की मांग की है। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के तीन जिलों में सीमित दायरे में चारधाम यात्रा शुरू करने के 25 जून के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। राज्य सरकार की एसएलपी से पहले हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून की अनु पंत, सच्चिदानंद डबराल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी गई। इसी बीच राज्य के नए मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के मामले में उप्र के अफसरों से विचार विमर्श के निर्देश दिए थे। अनु पंत के अधिवक्ता अभिजय नेगी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से दाखिल एसएलपी की कापी मिली है। इसमें हाई कोर्ट में दाखिल उस हलफनामे का जिक्र है, जिसमें कांवड़ यात्रा पर सरकार की ओर से रोक लगाने की बात शपथ पत्र में की गई है। यह भी जिक्र है कि कोविड संक्रमण के बड़ी संख्या में मामले आए तो हरिद्वार के एक अस्पताल में कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए म्यूजिक सिस्टम तक का सहारा लिया गया।

छग में बालगृह की आड़ में 19 बच्चों के मतांतरण का खेल बेनकाब

नईदुनिया, रायपुर

साजिश

- छत्तीसगढ़ सचिवालय से पांच किलोमीटर दूर अवैध बालगृह की आड़ में बच्चों को दी जा रही थी बाइबल की शिक्षा
- रायपुर आई मंडला पुलिस, पूछताछ के बाद बच्चों को ले गई
- अब मतांतरण की तह तक जाने को लेकर की जाएगी जांच

> मतांतरण की बात अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन बाल कल्याण समिति और मंडला पुलिस भी इस दिशा में जांच कर रही है। जेजे एक्ट के तहत बालगृह बिना अनुमति के चल रहा था, यह गलती संचालक ने की है। अभी इस मामले में पूछताछ जारी है।
> – सर्जत हुसैन नकवी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, रायपुर

> मंडला पुलिस से विभागीय चर्चा हुई है और बच्चों को मंडला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है।
> – अशोक पांडेय, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ सचिवालय से करीब पांच किलोमीटर दूर नवा रायपुर के सेक्टर-29 में चल रहे अवैध बालगृह की आड़ में बच्चों का मतांतरण करने की कोशिश नाकाम हो गई है। पड़ोसियों की शिकायत पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई करते हुए बच्चों को वहां से मुक्त करा लिया। हालांकि, मतांतरण के पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद इस संबंध में बाल कल्याण समिति एवं पुलिस मतांतरण के बिंदु पर जांच कर रही है।

सभी 19 बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला जिले के हैं। मंडला पुलिस सोमवार को रायपुर पहुंची और बच्चों के परिचय संबंधी कागजात, अभिभावकों द्वारा दिए गए अनुमति पत्र को हासिल कर बच्चों को मंडला लेकर चली गई। अब मतांतरण की तह तक जाने की भी जांच की जाएगी। इस बीच देर शाम आरोपित अवैध बालगृह के संचालक नरेश महानंद को राखी थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपित के खिलाफ धारा 420 और किशोर अधिनियम 2015 की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया की टीम सोमवार को गांव खपरी पहुंची तो पाया कि जिस सीनियर एमआइजी 427 नंबर मकान में बच्चों को रखा गया था, उस पर ताला लगा था। आसपास के लोगों ने बताया कि मालिक ने अपना मकान खाली करवा लिया है। गांव खपरी के सरपंच सुजीत गिदौड़े ने बताया कि कुछ लोगों ने मकान में बच्चों को रखे जाने और वहां बाइबल का पाठ करवाने की शिकायत की थी। बच्चों का मतांतरण किए जाने की आशंका और बाल गृह की गतिविधियों को देखते हुए इसकी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग से की थी। विभाग ने कार्रवाई करके बच्चों को माना स्थित शासकीय बाल गृह भेजा था।

अवैध बालगृह के संचालक नरेश महानंद ने बताया कि वह भिलाई का रहने वाला है और उसने दो साल तक चंडीगढ़ में बाइबल की शिक्षा दी है। वह कोरोना के चलते पिछले दो साल से आनलाइन इसकी शिक्षा दे रहा है। नौकरी के सिलसिले में वह मारीशस एवं अन्य देशों में जा चुका है। अब भिलाई में रहकर अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

बालगृह के संचालक महानंद ने माना कि उससे गलती हुई कि जेजे एक्ट के तहत बालगृह चलाने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया। उसके पास सभी बच्चों का रिकार्ड है और बच्चों के माता-पिता की अनुमति से ही लाया गया है। यहां वह बच्चों का लालन-पालन और अच्छी शिक्षा देना चाहता था। उसने कहा कि मुझ पर मानव तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद है।

जागरण विशेष

बनारसी साड़ियों पर दमक रहा हुनर का 'पंचकार्ड'

आइआइटी धनबाद के पूर्व विद्यार्थियों की बनाई मशीन से साड़ी का कारोबार हुआ वर्चुअल

हिमांशु अस्थाना • वाराणसी

बनारसी साड़ियों के कारोबार पर कोरोना महामारी के करीब डेढ़ साल भारी पड़े हैं। आपदा ने बनारस के छोटे-बड़े हथकरघा कारीगरों और बुनकरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। मुसीबत की घड़ी में उम्मीद की किरण दिखाई है बनारस में रहने वाले आइआइटी, धनबाद के पूर्व छात्र नित्यानंद व शणमुख कृष्णा ने। इनके बनाए डिजिटल पंचकार्ड से कताई-बुनाई व डिजाइन सस्ती व आसान तो हुई ही है, साड़ी के कारोबार को वर्चुअल प्लेटफार्म पर विस्तार देने में भी मदद मिल रही है।


डिजिटल पंचकार्ड मशीन (नारंगी-सफेद रंग में) • सौजन्य-नित्यानंद



> यह तकनीक अब हालात की जरूरत भी है। डिजिटल पंचकार्ड समय व संसाधनों के साथ कोरोना से बचाव करेगा। ऐसी तकनीक हर बुनकर के हाथ में होनी चाहिए। हालांकि मशीन की व्यावहारिकता पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
> **डा. जसमिंदर कौर,** एसोसिएट प्रोफेसर, टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट, बीएचयू

कुछ अलग करने को छोड़ा लाखों का पैकेज


नित्यानंद

नित्यानंद ने बताया कि आइआइटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखों रुपये के पैकेज की नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ अलग करना चाहते थे। कोरोना काल में बुनकरों की बदहाली पर निगाह गई तो उनकी मदद के मकसद से डिजिटल पंचकार्ड मशीन बनाई। अभी पांच बुनकरों ने यह मशीन लगवाई है। एक मशीन की लागत करीब 80,000 रुपये आती है। इसे बुनकरों को एक लाख में मुहैया करा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालय (एमएसएमई) से 12 लाख की मदद स्वीकृत हुई है, जो जल्द मिलेगी।

साड़ी व सूट पर मनपसंद डिजाइन: ग्राहक दुनिया में कहीं से भी मनपसंद डिजाइन के लिए फोटो ईमेल कर सकता है। फोटो पेन ड्राइव में कापी कर डिजिटल पंचकार्ड के डिस्प्ले में लगाते ही वह डिजाइन बनारसी साड़ी या सूट पर छप जाता है। तीन गुना कम लागत, कम जगह घेरने के साथ एक साड़ी तैयार करने में हफ्तों के समय की बचत इस मशीन की खूबियां हैं।

उत्तर प्रदेश के बाहर तैयार हो रहा बाजार: पावरलूम में डिजिटल पंचकार्ड इंस्टाल कराने वाले बुनकर मुहम्मद यासीन बताते हैं कि पहले बनारसी साड़ी की डिजाइन को बदलने के लिए हैंडलूम मशीन में हर बार नया पंचकार्ड लगाना पड़ता था। इसमें 15-20 दिन लगते और पैसा खर्च होता था। सामान्य पंचकार्ड जगह काफी घेरता है और इसे चलाने के लिए तीन-चार कारीगर चाहिए। डिजिटल पंचकार्ड से प्रदेश के बाहर बाजार तैयार हो रहा है। लोग मनपसंद डिजाइन ईमेल पर भेजते हैं और हम तय समय में बनारसी साड़ी और सूट बनाकर दे रहे हैं।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

नौसेना की नई पनडुब्बियों में नहीं होगा स्वदेशी एआइपी

पी-75 इंडिया

- डीआरडीओ विकसित कर रहा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम
- नौसेना ने फिलहाल इस सिस्टम को नहीं दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय नौसेना जल्द ही छह स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना के लिए निविदा लेकर आएगी, लेकिन उनमें स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगाया जाएगा जिसे डीआरडीओ विकसित कर रहा है।

एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआइपी) तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों के पानी के भीतर लंबे समय तक रहने की क्षमता और गोपनीयता बढ़ाती है। इन्हें अपनी बैट्री रिचार्ज करने के लिए आक्सीजन का उपयोग करने के लिए सतह पर आना पड़ता है।

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में देश के भीतर छह नई पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के साथ आगे बढ़ने के लिए भारतीय नौसेना के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये की पी-75 इंडिया नामक परियोजना को मंजूरी दी थी।

सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, पी-75 इंडिया परियोजना में अपना एआइपी शामिल करने पर जोर दे रहा है, लेकिन इसे अभी तक टेंडर में शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ से कहा है कि स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियां जब अपनी निर्धारित रिफिटिंग के लिए आना शुरू करें तो उनमें इसे लगाने की अनुमति देने से पहले उसे एक प्लेटफार्म पर अपने एआइपी की क्षमता साबित करनी होगी।

यह पता चला है कि नौसेना अपनी परियोजना के दावेदारों को वर्तमान में चालू एआइपी सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देगी जो केवल विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के पास उपलब्ध होंगी। इस परियोजना में कम से कम दो साल लगने की उम्मीद है। इस परियोजना का काम हाथ में लेने के लिए लार्सन एंड टुब्रो और मझगांव डाक यार्ड्स लिमिटेड के बीच जबर्दस्त होड़ है। इनके साथ पांच विदेशी फर्में भी साझीदार हैं जो कुछ अहम उपकरणों की सप्लाई करेंगी।

6.82 करोड़ है ब्रिटेन की कुल आबादी। करीब 68 फीसद लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज और लगभग 52 फीसद आबादी को दोनों डोज लग चुकी है।

चीन का अमेरिकी युद्धपोत खदेड़ने का दावा

ड्रैगन ने कहा ▶ दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप के पास युद्धपोत यूएसएस बेनफोल्ड को भगाने पर मजबूर किया

अमेरिका ने कहा– फिलीपींस पर हमला किया तो रक्षा संधि के तहत चीन को देंगे जवाब

बीजिंग, रायटर : चीन की सेना का दावा है कि उसने सोमवार को पार्सल द्वीप के पास चीनी जल क्षेत्र में आए अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है। चीन ने यह अनर्गल दावा अंतरराष्ट्रीय अदालत के उस फैसले के एक साल बाद किया है, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई हक नहीं है।

चीन की सेना पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने अपनी दक्षिणी थिएटर कमांड की स्थिरता को कमतर आंकने को चुनौती देने का दावा करते हुए कहा, उसने चीन की मंजूरी के बिना उसके जल क्षेत्र में दाखिल हुए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बेनफोल्ड को खदेड़ दिया है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह अमेरिका से आग्रह करता है कि वह तत्काल ऐसी उकसावे वाली कोशिशें रोक दे। विगत 12 जुलाई, 2016 को हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला दिया था कि चीन का दक्षिण चीन सागर पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चीन ने इस फैसले को टाल दिया है।

इधर, एपी के अनुसार वाशिंगटन में बाइडन प्रशासन ने चीन के समुद्री क्षेत्र को दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा मानने को खारिज करते हुए अपने पूर्ववर्ती ट्रंप के शासनकाल के विरोधी रुख का ही समर्थन किया है। बाइडन प्रशासन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलीपींस पर अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिका आपसी रक्षा संधि के तहत अपना जवाब देगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह कड़ा संदेश इस हफ्ते मनाए गए अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की पांचवीं वर्षगांठ पर फिलीपींस के पक्ष में दिया गया है। अमेरिका ने खुलकर चीन की वृहद समुद्री सीमा के दावों को खारिज किया है। चीन का दावा है कि स्पार्टली द्वीप और उसके आसपास की मूंगा चट्टानों के द्वीप उसके हैं। उल्लेखनीय है कि इस संधि के चौथे समारोह में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि वह मानते हैं कि चीन दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अवैध रूप से अपना दावा करता है। जबकि वह क्षेत्र चीन के बाहर है और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जल क्षेत्र है।



दक्षिण चीन सागर में बढ़ रहा है तनाव। फाइल फोटो/ इंटरनेट मीडिया

दक्षिण चीन सागर भौगोलिक स्थिति और विवाद

दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समुद्री क्षेत्र हैं जो कि तकरीबन 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताईवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। पहले इस क्षेत्र में खास तनाव नहीं था, लेकिन वर्ष 2010 से चीन ने दक्षिणी चीन सागर में दखल बढ़ानी शुरू की। फिर एक छोटी समुद्री पट्टी के आसपास रेत, बजरी, ईंटों और कंक्रीट की मदद से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया। पहले बंदरगाह और फिर विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया। इसके बाद उसने एक कृत्रिम द्वीप द्वीप तैयार करके सैनिक अड्डा बना लिया।

यहां के द्वीपों पर दावा

- पार्सल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है।
- स्प्रैटली द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है।
- स्कारबोरो सोल द्वीप पर फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है।

ईयू उपभोक्ता शिकायतों में निजता को लेकर वाट्सएप पर निशाना

ब्रुसेल्स, रायटर: फेसबुक की सहायक शाखा वाट्सएप ने सोमवार को अपनी नई निजता नीति को लेकर यूरोपीय उपभोक्ता संगठन और अन्य की शिकायतों के अंबार का सामना किया। सोशल नेटवर्किंग साइट की इस नई नीति का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। बल्कि बहुत यूजर तो वाट्सएप को छोड़कर प्रतिस्पर्द्धी टेलीग्राम और सिग्नल पर चले गए हैं।

वाट्सएप ने इस साल जनवरी में नई निजता नीति को लागू कर दिया था। इससे इसका कुछ डाटा फेसबुक और अन्य कंपनियों से साझा किया जाता। उसका कहना है कि इन बदलावों से यूजर को व्यापारिक संदेश मिलने में सुविधा होती है। और इससे निजी वार्तालाप प्रभावित नहीं होता है।

दूसरी ओर, यूरोपीय उपभोक्ता संगठन और आठ अन्य सदस्यों ने इन बदलावों की आलोचना करते हुए यूरोपीय आयोग और यूरोपियन नेटवर्क आफ कंज्यूमर अथारिटीज से शिकायतें की हैं। यूरोपीय उपभोक्ता संगठन ने कहा कि वाट्सएप गलत तरीके से यूजर्स को नई नीतियों को स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डाल रहा है।

इस समूह ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि इन नोटिफिकेशंस की विषय सामग्री, प्रकृति और वैधता पर चयन का दबाव डाला जाता है। उनका कहना है कि वाट्सएप अपनी नीतियों को सामान्य भाषा में स्पष्ट करने में नाकाम रहा है। जबकि फेसबुक का कहना है कि उपभोक्ता संगठन ने इस मुद्दे को गलत तरीके से उठाया है।

दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है चीन के प्रति नफरत

- मानवाधिकार हनन के कारण नापसंद करने वाले देशों की बढ़ी संख्या
- आर्थिक रूप से विकसित 17 देशों में सर्वे ड्रैगन के लिए सबक

ताइपे, एएनआइ : चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में लंबे समय से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला दबाया जा रहा है। मानवाधिकार हनन के मामलों से चीन के प्रति तमाम देशों और वहां रहने वाले लोगों के बीच तेजी से अलोकप्रियता बढ़ रही है। कई देशों में तो उसके लिए नफरत पैदा हो रही है।

थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने पिछले सप्ताह एक सर्वे जारी किया है। यह सर्वे 17 ऐसे देशों में किया गया है, जो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हैं। इस सर्वे में औसतन 69 फीसद लोगों में चीन के प्रति नकारात्मक नजरिया मिला है। इस तरह का नजरिया होने का सबसे बड़ा कारण चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान न होना है।

ताइपे टाइम्स में प्रकाशित इस सर्वे में अस्सी फीसद लोगों ने यह माना है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अंतरराष्ट्रीय मसलों को ठीक से हल नहीं कर सकते हैं। उनकी भी पिछले अलोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तेजी से हो रहा हनन

ज्ञात हो कि इस साल के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म निर्देशक क्लो झाओ ने 2013 में कहा था कि चीन ऐसा देश है, जहां हर तरफ झूठ फैला हुआ है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति के बावजूद यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तेजी से हनन हो रहा है। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के साथ ही अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन के मामले अब किसी से छिपे नहीं हैं। ताइपे टाइम्स के अनुसार शिनजियांग में चीन जो भी कर रहा है, उसमें विकसित देशों के लोगों का मानना है कि वह पूरी तरह से गलत है।

लाहौर में मृत मिली पाकिस्तानी मॉडल नायब नदीम

- पुलिस को गला दबाकर हत्या का शक
- टूटी हुई थी घर के बाथरूम की खिड़की

लाहौर, एएनआइ : पाकिस्तान में एक मॉडल की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि 29 साल की मॉडल नायब नदीम की गला दबाकर हत्या की गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट की मानें तो नायब के भाई ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है।

लाहौर के डिफेंस बी पुलिस स्टेशन के एसएचओ नैयर निसार ने बताया कि संभवतः मॉडल की गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा।

नायब के भाई मुहम्मद अली ने बताया कि नौ जुलाई को आधी रात के करीब वह बहन के घर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि नायब जमीन पर मृत पड़ी हुई हैं। उनकी गर्दन पर चोट के निशान थे। अली ने कहा कि नायब के बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। उन्होंने आशंका जताई कि हत्यारा बाथरूम के रास्ते से घर के अंदर आया होगा। पुलिस का कहना है कि अली अक्सर बहन का हालचाल जानने उसके घर जाया करते थे।

नायब की शादी नहीं हुई थी और वो घर में अकेले रहती थीं। बता दें कि इससे पहले मई में पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश महिला की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 2016 में पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की हत्या कर दी थी। हत्या उनके भाई ने की व उसे उम्रकैद की सजा हुई है।

देउबा के नेपाल का पीएम बनने से भारत को राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चार बार प्रधानमंत्री रहे नेपाली कांग्रेस नेता को माना जाता है भारत का पुराना हितैषी
- देउबा ओली की जगह लेंगे जो अपने कार्यकाल के दौरान कई बार दे चुके हैं भारत विरोधी बयान

नेपाल में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण से भारत ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली है। खास तौर पर नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा का प्रधानमंत्री के पद पर आना भारत के लिए शुभ संकेत है। बता दें कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में वहां पिछले छह महीने से चल रही राजनीतिक असमंजसता को खत्म करते हुए देउबा के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का निर्देश दिया है।

पूर्व में चार बार नेपाल के पीएम का पदभार संभाल चुके देउबा और उनके राजनीतिक दल को भारत का पुराना हितैषी माना जाता है। देउबा केपी शर्मा ओली की जगह लेंगे जो अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ कई बार भारत विरोधी बयान देकर दोनों देशों के रिश्तों को असहज कर चुके हैं, बल्कि चीन को वहां के राजनीतिक गलियारों में घुसपैठ करने की भी छूट दी।

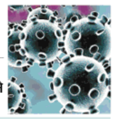
नेपाल में चल रहे राजनीतिक बदलाव को लेकर भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी बयान नहीं दिया है, लेकिन पुराना अनुभव बताता है कि जब भी देउबा ने सत्ता संभाली है तब दोनों देशों के रिश्तों में संदेह को दूर करने में काफी मदद मिली है। वर्ष 2017 में वह पीएम बनने के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों देशों के रिश्तों में घुल रहे तनाव को काफी हद तक खत्म किया। उसके बाद नेपाल में आम चुनाव हुए और फिर केपी शर्मा ओली की सरकार बनी। ओली की दोबारा सरकार बनने के बाद वहां चीन की सक्रियता और बढ़ गई। ओली ने संविधान संशोधन कर भारत के हिस्से वाले कुछ क्षेत्रों को नेपाल में शामिल करने जैसे कदम उठाए।

भारत के साथ नरम रुख अपनाते रहे हैं देउबा

देउबा भारत के साथ आर्थिक रिश्तों से लेकर मधेशियों वाले मामले में भी पारंपरिक तौर पर नरम रुख अपनाते रहे हैं। देउबा उस समय नेपाल के पीएम बन रहे हैं जब चीन की तरफ से भारत के दूसरे पड़ोसी देशों को प्रभाव में लेने की कोशिश चरम पर है।

सिडनी में लाकडाउन के बाद भी नहीं सुधर रहे आस्ट्रेलिया के हालात

- इस्लामाबाद में कई इलाके संक्रमण बढ़ने के बाद सील
- पाक में कोरोना के नियमों का पालन कराने को सेना होगी तैनात



सिडनी, रायटर : सिडनी में लाकडाउन के बाद भी आस्ट्रेलिया में डेल्टा वैरिएंट के कारण स्थिति खराब है। यहां मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के कई इलाके सील कर दिए गए हैं। जनता से कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अब सेना को उतारा जा रहा है।

आस्ट्रेलिया में तेजी से डेल्टा वैरिएंट के मरीज आ रहे हैं। हालात में कोई सुधार नहीं है। कोरोना मरीजों की संख्या तीन अंकों में बढ़ने के साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सिडनी में फिलहाल लाकडाउन हटाना असंभव है। पाकिस्तान में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इस्लामाबाद प्रशासन ने कई इलाकों को सील करने का फैसला किया है। यहां चार दिनों में कोरोना संक्रमण की पाजिटिव दर एक प्रतिशत से पांच प्रतिशत पहुंच गई है। पाक में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है।

म्यांमार : आइएएनएस के अनुसार संक्रमण बढ़ने के कारण 18 शहरों में जनता को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

रूस : आइएएनएस के अनुसार वैक्सीन लगाने में तेजी के बाद भी हर रोज 25 हजार से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं।

चीन : एपी के अनुसार म्यांमार सीमा के निकट युन्नान प्रांत के शहरों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर लाकडाउन लगा दिया गया है।

ब्रिटेन में पाबंदियां हटेंगी, लेकिन सावधानी के साथ

लंदन, एपी : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन 19 जुलाई को लाकडाउन संबंधी पाबंदियों को हटाने की घोषणा कर सकते हैं। ये पाबंदियां सावधानी की चेतावनी के साथ ही हटाई जाएंगी, क्योंकि ब्रिटेन में डेल्टा वैरिएंट के कारण मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।

सिंगापुर में कोविड प्रोटोकाल तोड़ने पर भारतीय को सजा

सिंगापुर, प्रेट्र : कोविड प्रोटोकाल तोड़ने पर 26 वर्षीय भारतीय नागरिक बालचंद्रन परतिबन को सिंगापुर में नौ माह जेल की सजा सुनाई गई है। चूंकि उसने स्वाब टेस्ट के नतीजों के लिए अस्पताल में रहने के बजाय सिंगापुर छोड़कर जाने की कोशिश की थी। बालचंद्रन का कोविड टेस्ट पाजिटिव आने के बाद पुलिस उसे चांगी एयरपोर्ट से ले गई और अस्पताल में फिर से भर्ती करा दिया है। टुडे अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक बालचंद्रन ने सार्वजनिक वाहन से जाकर भारत जाने के लिए टिकट खरीदने की नाकाम कोशिश की।

न्यूज गैलरी

जैकी चैन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में होना चाहते हैं शामिल

बीजिंग : हांगकांग में रहने वाले हालीवुड के मशहूर अभिनेता जैकी चैन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। जैकी की पिछले दिनों दुनियाभर में उस समय कड़ी आलोचना हुई थी, जब उन्होंने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की कार्रवाई का समर्थन किया था। 67 वर्षीय जैकी ने यह इच्छा एक सेमिनार में व्यक्त की। यहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल पूरे होने पर दिए गए भाषण की भी तारीफ की। (प्रेट्र)

इमरान और पाक सेना के खिलाफ कनाडा में प्रदर्शन

टोरंटो : मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) कनाडा ने अपने नेता अल्ताफ हुसैन को धमकी दिए जाने के मामले में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने बजट सत्र में कहा था कि क्या ब्रिटेन की सरकार अल्ताफ हुसैन को मारने की पाक को इजाजत देगी। एमक्यूएम की केंद्रीय समिति के संयोजक तारिक जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अल्ताफ हुसैन की हत्या करने की साजिश रच रही हैं। टोरंटो में हुए इस प्रदर्शन में ब्रिटेन से अल्ताफ हुसैन की सुरक्षा करने और पाक प्रधानमंत्री के बयान पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। (एएनआइ)

जयपुर फुट यूएसए ने दिव्यांगों को मुफ्त कृत्रिम अंग लगाने को चलाई वैन

कोरोना से जंग

- गुजरात की सड़कों पर कृत्रिम हाथ–पैर लगाने वाले विशेषज्ञों के साथ जल्द नजर आएगी गाड़ी

न्यूयार्क, प्रेट्र : वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जयपुर फुट यूएसए ने दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग लगाने के लिए विशेष रूप से मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। जयपुर फुट यूएसए निशुल्क कृत्रिम अंगों को गुजरात के विभिन्न जिलों में वितरित करेगा।

जयपुर फुट यूएसए के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने सोमवार को कहा कि सभी उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल वैन जल्दी ही सड़कों पर दौड़ेगी। इस वैन में तीन तकनीशियन और विशेषज्ञ मौजूद होंगे जो आर्टीफिशियल हाथ और पैर लगाने का काम करेंगे। वैन में हमेशा आठ से दस कृत्रिम मानव अंग मौजूद रहेंगे। गत शनिवार को न्यूयार्क में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने इसकी पहल की है। न्यूयार्क में बसे निखिल मेहता ने मोबाइल वैन को विचार को सबसे पहले सामने रखा था। भंडारी ने बताया कि जयपुर फुट यूएसए मेहसाणा के वडनगर, के जिला प्रशासन के पहले ही संपर्क में है। उन्होंने यहां मुरलीधरन से मुलाकात की और दिव्यांगों को मुफ्त में कृत्रिम अंग लगाने के लिए मोबाइल वैन संचालित करने का आश्वासन दिया।

केबल बस लाइन



मेक्सिको सिटी में सार्वजनिक परिवहन के लिए केबल बस लाइन को शुरू कर दिया गया है। यह लाइन घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गई है। करीब 90 लाख की आबादी वाले शहर के लोग अब आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। रायटर

पाकिस्तानी सांसद भतीजे ने दिलीप कुमार को दी श्रद्धांजलि

पेशावर, प्रेट्र : दिवंगत भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार के भतीजे और पाकिस्तानी सांसद मोहसिन अजीज ने सोमवार को कहा कि वह सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे बल्कि एक संस्था थे। उनके जैसे लोगों का जन्म सदी में एक ही बार होता है।

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के नेता मोहसिन अजीज ने दिलीप कुमार की स्मृति में आयोजित शोक सभा में कहा कि वह एक नेकदिल इंसान थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। उन्होंने मानवता के लिए बहुत काम किया। ज्ञात हो, पाक सरकार ने वर्ष 1998 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान-ए-पाक' दिया था।

ग्रीक भाषा के अक्षरों पर किया जाता है वैरिएंट का नामकरण



हम प्रतिदिन किसी ना किसी नए कोरोना वैरिएंट का नाम सुनते हैं, जिससे ना केवल आम लोग बल्कि स्वास्थ्य अधिकारियों में भी चिंता बढ़ जाती है। वैरिएंट के नामों को लेकर भी लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। खास बात यह है कि वैरिएंट का नामकरण ग्रीक भाषा के अक्षरों पर किया जाता है। आइए जानते हैं कि अब तक कितने वैरिएंट का नामकरण हो चुका है।

24 अक्षर हैं ग्रीक भाषा में (अल्फा से लेकर ओमेगा तक)

11 वैरिएंट की पहचान अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है।

3 वैरिएंट को निगरानी श्रेणी में रखा गया है।

4 अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (चिंता की श्रेणी) में रखा गया है।

4 ईटा, आयोटा, कप्पा और लेम्डा को वैरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट की श्रेणी में रखा गया है।

सबसे ज्यादा खतरनाक वैरिएंट

अल्फा बी.1.1.7 — ये सबसे पहले यूके में सितंबर 2020 में मिला था। ये वैरिएंट अब तक 173 देशों में फैल चुका है। ये महिला मरीजों के लिए ज्यादा घातक है।

बीटा बी.1.351 — ये अगस्त 2020 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिला था। अब तक 122 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं।

गामा पी.1 — दिसंबर 2020 में सबसे पहला मामला ब्राजील में सामने आया था। जिसके बाद बहुत तेजी से लोग बीमार हुए। 74 देशों में मरीज मिल चुके हैं।

डेल्टा बी.1.617.2 — ये वैरिएंट भारत में मिला था। ये अल्फा से 55 फीसद ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका म्यूटेड रूप वैरिएंट डेल्टा प्लस है।

ऐसे वैरिएंट जिनसे बहुत डरने की जरूरत नहीं है

एप्सिलोन : कैलिफोर्निया में सबसे पहले मिला

जीटा : रियो डे जेनेरियो में मिला

थीटा : फिलीपींस में मिला

इन वैरिएंट पर है निगरानी की जरूरत, विभिन्न देशों में मिल चुके हैं मरीज

ईटा : पहला मामला यूके में सामने आया, बाद में नाइजीरिया में भी मरीज मिले।

आयोटा : पहले न्यूयार्क में इसके मामले तेजी से आ रहे थे। हालांकि अब अल्फा के मामले ज्यादा हो गए हैं।

कप्पा : इसको डेल्टा का छोटा भाई भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही बी.1.617 उपवंश के ही हैं। यूपी में इस वैरिएंट के दो मामले हाल ही में सामने आए हैं।

लेम्डा : दिसंबर 2020 में पेरू में सबसे पहले इससे ग्रस्त मरीजों का पता चला था। बाद में अप्रैल–मई में 80 फीसद मामले यहां इसी वैरिएंट के थे। अब तक 29 देशों में ये वैरिएंट फैल चुका है। भारत में अभी तक इसका कोई केस नहीं मिला है।

जागरण इन्फो

अमेरिका में बरस रही आग, डेथ वैली में तापमान 56 डिग्री सेल्सियस

विश्व का सबसे गर्म इलाका

अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी इलाके में भीषण लू से आफत, स्वास्थ्य विभाग ने और गर्मी पड़ने की आशंका पर नागरिकों को चेताया

कैलीफोर्निया, रायटर: अमेरिका और कनाडा के पश्चिम में तापमान इन दिनों हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। भीषण लू के थपेड़े अमेरिका में अब तक कई लोगों की जान ले चुके हैं। पश्चिमी अमेरिका में लगातार तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। कैलीफॉर्निया की मशहूर डेथ वैली में रविवार को तापमान 56 डिग्री सेल्सियस (करीब 133 डिग्री फारेनहाइट) दर्ज किया गया है। इस वजह से यह इलाका एक बार फिर से धरती का सबसे गर्म हिस्सा बन गया है। वहीं पश्चिमी कनाडा में तापमान 92 डिग्री फारेनहाइट (32 डिग्री सेल्सियस) रिकार्ड किया गया है। यहां पर कई जगहों पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। इसकी वजह से लोगों को यहां से बाहर जाने को भी कहा गया है।

अमेरिका के डेथ वैली के केंद्र में मौजूद फर्नेस क्रीक विजिटर्स सेंटर के बाहर लगे थर्मामीटर में तापमान 134 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच चुका है। इसको जब जांचा गया तो यह धरती पर सबसे अधिक तापमान था। रविवार की दोपहर यह बढ़कर 178 डिग्री फारेनहाइट तक जा पहुंचा था। यहां पर पहुंचे एरिजोना के रिचर्ड रेडर ने बताया कि वह यहां पर यह देखने आए थे कि यह कैसे होता है। रविवार को रिचर्ड डेथ वैली में करीब 10 मील की दूरी तक यहां आए थे। यहां पर आने वाले दूसरे पर्यटक भी केवल यहां पर टेंप्रेचर मीटर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए ही अपनी कार से बाहर निकल रहे थे। पूरे पेसेफिक नॉर्थवेस्ट का लगभग यही हाल है।

दक्षिण ओरेगॉन के जंगल में इन दिनों जबरदस्त आग लगी हुई है। इसकी वजह से भी यहां का तापमान इतना अधिक बढ़ा हुआ है। ओरेगॉन में कई लोगों की जान भीषण गर्मी की वजह से अब तक जा चुकी है। इस भीषण गर्मी में यहां के घरों में बिजली जाने का भी डर लगा हुआ है।

अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने और अधिक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। एनडब्ल्यूएस की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिन और गर्म हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि बढ़ता तापमान लोगों की सेहत और उनकी जान का भी दुश्मन बन सकता है। इसलिए बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखा जाए।



अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। दक्षिण-पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान की डेथ वैली में तापमान रिकार्ड 56 डिग्री सेल्सियस (133 फारेनहाइट) तक पहुंच गया है। नेशनल पार्क में फर्नेस क्रीक विजिटर्स सेंटर में लगे तापमान मापक यंत्र के पास तस्वीरें खींचते लोग। एपी

क्यूबा में खाना व दवा की किल्लत के खिलाफ दशकों में सबसे बड़ा प्रदर्शन

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में 1994 के बाद पहली बार सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग, जोरदार नारेबाजी

मियामी : 'आजादी' और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए क्यूबावासी रविवार को देश के विभिन्न शहरों की सड़कों पर उतर आए। खाना व दवा की किल्लत से परेशान लोगों का इतना बड़ा प्रदर्शन पिछले करीब तीन दशकों में नहीं देखा गया।

फेसबुक पर एक लाइव प्रसारण में हवाना के दक्षिण पश्चिम स्थित सैन एंटोनियो डी लास बानोस में सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि, करीब एक घंटे में ही इस वीडियो को हटा दिया गया। जैसे-जैसे दोपहर ढलती गई, वैसे-वैसे क्यूबा के अन्य हिस्सों से प्रदर्शनों के वीडियो सामने आते गए। देश के दक्षिण पूर्व में स्थित पाल्मा सोरियानो में हुए प्रदर्शन में भी लोगों का आक्रोश चरम पर दिखता है। हवाना में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जहां भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

द्वीप के पश्चिम में स्थित आर्टेमिसा प्रांत में फिल्माए गए वीडियो में प्रदर्शन के दौरान एक महिला चिल्लाकर कहती है, 'लोग भूख से मर रहे हैं। बच्चे तड़प रहे हैं।' कार्डेनस में प्रदर्शनकारी पुलिस की कार को पलटते हुए देखे गए। एक अन्य वीडियो में लोग सरकारी दुकान को लूटते देखे गए, जो ऊंची दर पर सामान बेच रही थी।

असंतोष के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई के लिए कुख्यात क्यूबा में इन दिनों रैलियों के आयोजन में आश्चर्यजनक रूप से तेजी आई है। जानकारों का कहना है कि लोग मालेकोनाजो विद्रोह के बाद पहली बार कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। 1994 में हुए इस विद्रोह के बाद बड़ी संख्या में क्यूबावासियों ने समुद्र के रास्ते देश छोड़ दिया था।

34 मैचों से इटली की टीम को शिकस्त नहीं मिली है। इस बीच उसने 28 मुकाबले जीते हैं और छह ड्रा खेले हैं



2 मिनट में गोल करने वाले इंग्लैंड के ल्यूक शा का यह गोल यूरो के फाइनल में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे कम समय में किया गया गोल है



लंदन में जीत का जश्न मनाती इतालवी प्रशंसक • एपी



लंदन में इंग्लिश प्रशंसकों के उत्पात के बाद पुलिस पहुंची • एएफपी



हारने के बाद उत्पात मचाते इंग्लिश प्रशंसक • एएफपी

इटली का रोम-रोम खिला

- इटली 53 साल बाद जीता यूरो कप
- इंग्लैंड पेनाल्टी शूट आउट में हारा

लंदन, एपी : जब यूरो कप का फाइनल शुरू हुआ तब इंग्लैंड के प्रशंसक ट्राफी को लेकर कह रहे थे कि इट्स कमिंग होम (यह घर आ रही है), क्योंकि इंग्लैंड फुटबाल का भी जनक माना जाता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद इटली के प्रशंसक लंदन की सड़कों पर चिल्ला रहे थे कि इट्स कमिंग रोम (यह रोम आ रही है। इटली की टीम जब ट्राफी जीतने के बाद सोमवार को देश की राजधानी रोम लौटी तो प्रशंसक खुशी से झूम उठे। वहीं इंग्लैंड का 55 साल से खिताब का इंतजार लंबा हो गया।

इटली ने रविवार को फाइनल में इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर यूरो कप जीता। दोनों टीमें निर्धारित और अतिरिक्त समय तक 1-1 से बराबरी पर थीं, जिसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में इटली जीत गया। जीत के बाद इटली के खिलाड़ी गोलपोस्ट के नेट को काटकर सुनहरी यादों के तौर पर अपने साथ ले गए। इटली ने 53 साल बाद दूसरी बार यह ट्राफी जीती। इससे पहले उसने 1968 में यूरो कप जीता था।

डोनारूमा ने तोड़ा सपना : इटली के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारूमा ने अपनी बायीं तरफ डाइव लगाकर बुकायो साका का शाट रोका और इस तरह से इंग्लैंड को अपने पसंदीदा वेंबले स्टेडियम में लगातार तीसरी बार पेनाल्टी शूट आउट में नाकामी हाथ लगी। डोनारूमा ने फाइनल में भी दो पेनाल्टी बचाई और सेमीफाइनल में भी स्पेन के खिलाफ दो पेनाल्टी बचाकर टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया था। उनके रहते टीम पांच बार पेनाल्टी शूट आउट खेली और पांचों बार जीत मिली, जिसमें तीन मैच क्लब व दो मैच राष्ट्रीय टीम के थे।

नहीं थी अच्छी स्थिति : चार साल पहले इटली की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह पहली बार विश्व कप में जगह बनाने में असफल रहा था। अब वह यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीम है। वहीं, इंग्लैंड पिछले 55 वर्षों में पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट (यूरो कप/विश्व कप) का फाइनल खेल रहा था। उसने 1966 में विश्व कप में जीत के बाद कोई बड़ा खिताब नहीं जीता।

पेनाल्टी का दर्द : इंग्लैंड के साका, सांचो और रशफोर्ड पेनाल्टी पर चूक गए थे, लेकिन सांचो व रशफोर्ड को अतिरिक्त समय के अंतिम क्षणों में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में लाया गया था। ऐसा लगता है कि पेनाल्टी लेने की उनकी विशेषज्ञता के कारण यह फैसला किया गया था।

ल्यूक का गोल : इंग्लैंड के लिए शुरुआत अच्छी रही और दूसरे मिनट में डिफेंडर ल्यूक शा ने टीम को 1-0 से आगे कर दिया। बाक्स के अंदर से ट्रिपर ने गेंद शा की तरफ भेजी और शा ने गेंद पर अच्छे से नियंत्रण करते हुए अपने बायें पैर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम का मैच में खाता खोल दिया। पहले हाफ में मेजबान टीम 1-0 से आगे रही।

इटली की वापसी : इसके बाद 67वें मिनट में इटली के लिए लियोनार्डो बोनुची ने गोलकीपर बाक्स में रिबाउंड पर गोल करके टीम की मैच में वापसी करा दी।

गोल्डन बूट रोनाल्डो को

लंदन : पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्वाधिक पांच गोल करने और एक गोल में मदद करने के लिए गोल्डन बूट मिला। इटली के गोलकीपर डोनारूमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

मैंने शूट आउट के लिए खिलाड़ियों का चयन किया था। हमने ट्रेनिंग में इस पर काम किया है। इटली पूरे टूर्नामेंट में मजबूत रहा है। इटली ने दिखाया कि वह इतनी बेहतरीन टीम कैसे है। **गेरेथ साउथगेट,** कोच, इंग्लैंड

पेनाल्टी शूट आउट

3 vs **2**

इटली		इंग्लैंड	
बेरार्डी	✓	हैरी केन	✓
बेलोटी	✗	मैगुएर	✓
लियोनार्डो	✓	रशफोर्ड	✗
बेर्नार्डेशी	✓	सांचो	✗
जोर्गिन्हो	✗	साका	✗

ओवरआल पेनाल्टी शूट आउट में रिकार्ड

इंग्लैंड	10 शूट आउट	3 जीते	7 हारे
इटली	13 शूट आउट	6 जीते	7 हारे

इटली ने रचा इतिहास

1968 के बाद दूसरी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया

6 बार कोई बड़ा खिताब जीता। उन्होंने 1934, 1938, 1982 और 2006 में विश्व कप ट्राफी जीती

1 से ज्यादा विश्व कप और यूरो कप जीतने वाली इटली तीसरी टीम बन गई है। फ्रांस और जर्मनी भी ऐसा कर चुके हैं

1996 के बाद यूरो में प्लेयर आफ द टूर्नामेंट बनने वाले जियानलुइगी डोनारूमा पहले गोलकीपर बने

पेनाल्टी पर चूकने वाले शीर्ष खिलाड़ी

खिलाड़ी	देश	बनाम	टूर्नामेंट	वर्ष
प्लाटिनी	फ्रांस	ब्राजील	विश्व कप क्वार्टर फाइल	1986
माराडोना	अर्जेंटीना	यूगोस्लाविया	विश्व कप क्वार्टर फाइनल	1990
राबर्टो बैगियो	इटली	ब्राजील	विश्व कप फाइनल	1994
लियोन मेसी	अर्जेंटीना	आइसलैंड	विश्व कप ग्रुप चरण	2018
नेमार	ब्राजील	कोलंबिया	दोस्ताना मुकाबला	2012

गेंद रखी

इटली 61% – इंग्लैंड 39%

इटली		इंग्लैंड
13	फ्री किक	26
03	कार्नर किक	05
00	गोलकीपर बचाव	05
05	यलो कार्ड	01
836	कुल पास	436

गोल

इटली	इंग्लैंड
1	1
लियोनार्डो बोनुची (67वां मिनट)	ल्यूक शा (02वां मिनट)

आमने-सामने

मैच | जीत | ड्रा

28 कुल मैच	इटली	इंग्लैंड	ड्रा
	12	08	08

इंग्लिश प्रशंसकों का उत्पात

लंदन, एपी : यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड को मिली हार के बाद उसके प्रशंसकों ने रास्तों में उत्पाद मचाया, जिसके बाद लंदन मेट्रोपोलिटियन दंगा पुलिस को उतारा गया। सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को भीड़ को हटाने के लिए रास्ते पर उतारा गया। दंगा पुलिस लंदन के पिसाडिली सर्कल और लिचेस्टर स्क्वायर में भी दिखी, जहां फुटबाल समर्थक लैंप पर चढ़े और कई लोग बसों की छत पर चढ़ गए।

मेट्रोपोलिटियन पुलिस ने ट्वीट किया, 'हमने नियम तोड़ने पर 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे 19 पुलिसकर्मी भीड़ को संभालने के कारण चोटिल हुए हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लंदन के हमारे सभी अधिकारियों को धन्यवाद, जिन्होंने पूरी रात शहर को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया।' मैच के बाद वेंबले स्टेडियम में भी उत्पाद देखने को मिला। इंटरनेट मीडिया में वायरल कई फुटेज में दिखाया गया है कि प्रशंसक बैरिकेड को तोड़कर स्टेडियम में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं कई इंग्लिश प्रशंसक इटली के समर्थकों को मार भी रहे थे।

तैयारियां हुई बेकार : इटली की जीत के साथ जहां उसके प्रशंसक खुशी से झूम रहे थे वहीं वेंबले स्टेडियम की अधिकतर सीटों पर मायूसी छाई हुई थी। इंग्लैंड के प्रशंसक सिर पकड़कर बैठे थे। यही हाल बाहर सड़कों पर था। प्रशंसकों की जमकर जश्न मनाने की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं।

इस तरह के घटिया दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए।



बोरिस जानसन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री

इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ नस्ली टिप्पणी

लंदन, एपी : यूरो कप फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट में चूकने वाले इंग्लैंड के तीनों अश्वेत खिलाड़ियों को इंटरनेट मीडिया पर नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड फुटबाल संघ (एफए) ने खिलाड़ियों के लिए उपयोग की जा रही भाषा की निंदा की। इंग्लैंड की तरफ से बुकायो साका, मार्कस रशफोर्ड और सांचो पेनाल्टी पर गोल नहीं कर पाए थे। टीम ने फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट में चूकने से पहले अपने समर्थकों का दिल भी जीता था, लेकिन खिताब नहीं जीतने के बाद घृणा खुलकर सामने आ गई।

शुरू हुई पदक देने की परंपरा



टोक्यो ओलिंपिक

10 दिन शेष

खिलाड़ियों को पदक देने की परंपरा सेंट लुइस ओलिंपिक से शुरू हुई। लंदन ओलिंपिक से ही खेलों के इस महाकुंभ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। पहली बार यह खेल यूरोप के बाहर आयोजित किए गए।

सेंट लुइस ओलिंपिक (1904)



01 जुलाई से 23 नवंबर, 1904

651 एथलीट | **12** देश | **16** खेल 91 मुकाबले



सेंट लुइस खेलों के दौरान ओलिंपिक खेलों में पहली बार पहले तीन स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक देने की परंपरा शुरू हुई।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	78	239
जर्मनी	04	13
क्यूबा	04	09
कनाडा	04	06
हंगरी	02	04

अस्तित्व की लड़ाई

सेंट लुइस ओलिंपिक खेलों में भी पेरिस की गलतियां दोहराने के कारण यह आयोजन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। पिछले ओलिंपिक की तरह ही इस बार बार भी साढ़े चार महीने तक इन खेलों का आयोजन हुआ। हालांकि, यह दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हो सका।

पहला विवाद

40 किमी की मैराथन अमेरिकी धावक फ्रेड लार्ज ने जीती। दूरी के बीच के हिस्से को कार से तय करने के चलते उन्हें अयोग्य ठहराया गया। दूसरे स्थान पर रहे थामस हिक्स विजेता बने।



फ्रेड लार्ज

चैंपियन

आर्की हान : 60 मी, 100 मी और 200 मी दौड़ जीती। 200 मी में 21.6 सेकेंड का ओलिंपिक रिकार्ड अगले 28 वर्ष तक उनके नाम रहा।



आर्की हान

आइजनर का धमाल
लकड़ी की एक टांग के सहारे अमेरिकी जिम्नास्ट जार्ज आइजनर ने छह पदक जीते।

मुक्केबाजी व फ्रीस्टाइल
मुक्केबाजी और फ्रीस्टाइल कुश्ती जैसे खेल पहली बार ओलिंपिक का हिस्सा बने।

लंदन ओलिंपिक (1908)



27 अप्रैल से 31 अक्टूबर

2008 एथलीट | **22** देश | **22** खेल 110 मुकाबले



लंदन में हुए ओलिंपिक खेल आधुनिक युग का सबसे लंबा आयोजन रहा। यह ओलिंपिक 187 दिन (छह महीने से अधिक) तक चला।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
ग्रेट ब्रिटेन	56	146
अमेरिका	23	47
स्वीडन	08	25
फ्रांस	05	19
जर्मनी	03	13

ओलिंपिक भावना

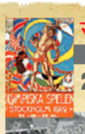
खेल भावना की अद्भुत मिसाल इस ओलिंपिक में देखने को मिली। ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले का फाइनल मार्टेंशन और एंडरसन के बीच होना था, लेकिन मार्टेंशन को हल्की चोट लगने के कारण मुकाबले को एक दिन के लिए टाल दिया गया। अगले दिन मार्टेंशन ने मुकाबला जीत लिया।

अंतरराष्ट्रीय पहचान

यह आयोजन इटली में होना था, पर वहां विसुवियस ज्वालामुखी के फटने के कारण उसने मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया। लंदन में आयोजन जल्दबाजी में किया गया। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज शामिल किए गए।

दौड़ : पहली बार मैराथन के लिए 42 किमी और 195 मी की दौड़ तय की। अंतिम 195 मी की दूरी इसलिए रखी गई ताकि लंदन स्टेडियम में दौड़ रायल बाक्स के ठीक नीचे खत्म हो सके। इटली के धावक डोरांडो पिएट्री अंतिम चक्कर में गलत दिशा में दौड़ते हुए गिर गए। अधिकारियों ने उन्हें सहारा दिया। वह पहले स्थान पर आए। बाहरी मदद मिलने के कारण उन्हें अयोग्य ठहराया, लेकिन वह इतिहास में अमर हो गए।

स्टाकहोम (1912)



06 जुलाई से 22 जुलाई

2406 एथलीट | **28** देश | **14** खेल 102 मुकाबले



तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	25	63
स्वीडन	24	65
ब्रिटेन	10	41
फिनलैंड	09	26
फ्रांस	07	14

पहली बार

जापान ने पहली बार भाग लिया। मार्डन पेंटाथलान, महिला तैराकी और घुड़सवारी को शामिल किया गया। ग्रीको रोमन कुश्ती में एक सेमीफाइनल रिकार्ड 11 घंटे, 45 मिनट तक चला। रूस के मार्टिन कलिन ने यह मैच जीता।

जिम थोर्प

अमेरिकी मूल के जिम थोर्प ने ओक्लाहामा के लिए पेंटाथलान और डेकाथलान का स्वर्ण बड़े अंतर से जीता। बाद में उनके यह रहस्योद्घाटन करने पर कि उन्होंने खेल से पहले पैसे लेकर बेसबाल खेला था, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 1982 में आइओसी ने इस परिणाम को बहाल करते हुए उनके पदक उनकी बेटी को लौटा दिए।

एंटवर्प (1920)



14 अगस्त से 12 सितंबर

2626 एथलीट | **29** देश | **22** खेल 156 मुकाबले



तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	41	95
स्वीडन	19	64
ब्रिटेन	15	43
फिनलैंड	15	34
बेल्जियम	14	36

इन खेलों में पहली बार शपथ ली गई। पहली बार शांति के प्रतीक के तौर पर कबूतर उड़ाए गए और ओलंपिक ध्वज फहराया गया।

उम्रदराज चैंपियन : स्वीडन के 100 मीटर के धावक आस्कर स्वान 72 साल की उम्र में टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन बने।

ब्राजील का पहला स्वर्ण

निशानेबाज गुर्लेमो पाराएंस ने ब्राजील को इन खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया।

विंटर स्पोर्ट्स

इन खेलों में एक हफ्ते विंटर स्पोर्ट्स भी आयोजित किए गए। जिसमें 1908 के बाद पहली बार फिगर स्केटिंग भी शामिल की गई।

टेनिस | 20वां ग्रैंडस्लैम जीतकर विश्व नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक ने की रोजर फेडरर व राफेल नडाल की बराबरी

बिग थ्री की दौड़ में सबसे आगे जोकोविक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : साल 2008 में जब सिर्फ 20 साल की उम्र में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब आस्ट्रेलियन ओपन के रूप में जीता था तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह सिर्फ 14 साल में ही अपने ग्रैंडस्लैम खिताबों को 20 पर पहुंचा देंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हालांकि, जोकोविक के साथ बिग थ्री में शामिल होने वाले रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने भी 20-20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, लेकिन उन दोनों को इसके लिए 16 साल का समय लगा। साथ ही एटीपी रैंकिंग में जोकोविक 329 सप्ताह से शीर्ष पर काबिज हैं। अभी उनके 12,113 अंक हैं।

34 साल की उम्र में 20 खिताब हासिल करके जोकोविक ने यह साबित कर दिया कि बिग थ्री के बीच ग्रैंडस्लैम की इस दौड़ में वह सबसे आगे हैं। 39 साल के हो चुके फेडरर को हाल ही में हुए विंबलडन में उनके पसंदीदा ग्रास कोर्ट पर काफी संघर्ष करते देखा गया था, जिसके चलते वह बमुश्किल क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच पाए थे, जबकि 13 बार फ्रेंच ओपन अपने नाम करने वाले 35 साल के नडाल का रैकेट उनके पसंदीदा लाल बजरी कोर्ट में भी नहीं चला और वह सेमीफाइनल में जोकोविक से हारकर बाहर हो गए थे। वहीं, जोकोविक ने इस साल आस्ट्रेलियन ओपन व फ्रेंच ओपन जीतने के बाद विंबलडन का अपना छठा खिताब भी जीता, जिसके बाद उनके नडाल व फेडरर से 21 साबित होने यानी 21वें ग्रैंडस्लैम पर कब्जा जमाने की चर्चा जोरों पर है। फेडरर का करियर अब ज्यादा नहीं बचा है और वह बढ़ती उम्र के कारण थके हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नडाल भी बीच-बीच में चोट से जूझते रहे हैं। ऐसे में जोकोविक का करियर इन दोनों से ज्यादा लंबा नजर आ रहा है। विंबलडन में जीत के बाद जोकोविक ने नवंबर में होने वाले एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उन्होंने कहा, 'मेरी योजना शुरू से ही ओलिंपिक खेलों में भाग लेने की थी, लेकिन वर्तमान स्थित को देखकर मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। पिछले दो-तीन दिनों में मैंने जो कुछ सुना उससे यह अभी 50-50 जैसी स्थिति है।' दरअसल, जोकोविक ओलिंपिक में प्रशंसकों की अनुपस्थिति की खबर से निराश हैं। उन्होंने पहले कहा था कि अगर प्रशंसक नहीं होंगे तो वह ओलिंपिक में नहीं खेलेंगे।



विंबलडन ट्राफी के साथ जोकोविक • एएफपी

20 ग्रैंडस्लैम खिताब बड़ी बात है और यह आश्चर्यजनक है कि हम तीन खिलाड़ी यहां तक पहुंचे हैं। जोकोविक को बधाई। **-राफेल नडाल**

कास्पारोव पर फिर भारी पड़े आनंद

जगरेब, प्रेट्र : पांच बार के पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने रविवार को यहां क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर के ब्लिट्ज स्पर्धा के 13वें दौर में लगातार दूसरी बार गैरी कास्पारोव को हराया। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले दिन भी कास्पारोव को हराया था। आनंद को यह जीत अनीश गिरी (नीदरलैंड्स), जान-क्रिजस्टोफ डूडा (पोलैंड) और मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव (फ्रांस) के खिलाफ लगातार तीन ड्रा के बाद मिली। उन्होंने इसके बाद 14वें दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के इयान नेपोमिनियाची पर शानदार जीत दर्ज की और गिरी के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। दोनों खिलाड़ियों के नाम 18-18 अंक हैं।

आनंद ने कास्पारोव के खिलाफ काले मोहरों से खेलते हुए 25 चालों में जीत दर्ज की। उन्होंने शनिवार को ब्लिट्ज प्रतियोगिता के शुरुआती दिन चार जीत दर्ज की।

काम आएगा आइपीएल का अनुभव : भुवी

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय सीमित ओवरों की टीम में भले ही छह खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव नहीं है, लेकिन उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि कम अनुभवी होना कोई मसला नहीं है और आइपीएल के कारण पूरी टीम आत्मविश्वास से भरी है।

भारतीय टीम में देवदत्त पडीक्कल, चेतन सकारिया, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, रुतुराज गायकवाड़ और वरुण चक्रवर्ती को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन इन सभी ने आइपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली।

भुवनेश्वर ने कहा, 'हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं। वे भले ही युवा है, लेकिन उनके पास आइपीएल का अनुभव है। वे लंबे समय से टी-20 में खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी टीमों के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए यह टीम के लिए लाभदायक स्थिति है कि वे आइपीएल से मिले आत्मविश्वास के साथ यहां खेलने के लिए उतरेंगे। वे युवा और प्रतिभाशाली हैं। टीम में अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और यह अच्छा दौरा होगा। युवा खिलाड़ी जो अपने पहले दौरे पर आए हैं और जिन्होंने आइपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके टीम में जगह बनाई है यदि वे यहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो इससे उनका मनोबल काफी बढ़ेगा।'

यह सीनियर तेज गेंदबाज पिछले साल के आइपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गया था और फिर आस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं जा पाया था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में वापसी की।

एक्लेस्टोन, कोन्वे आइसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

दुबई, प्रेट्र : इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन भारत की युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा और आलराउंडर स्नेह राणा को पीछे छोड़कर जून के लिए आइसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई, जबकि पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कोन्वे को दिया गया। बायें हाथ की स्पिनर एक्लेस्टोन यह पुरस्कार पाने वाली इंग्लैंड की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। उनसे पहले फरवरी में टैमी ब्यूमोंट को यह पुरस्कार मिला था। एक्लेस्टोन भारत के खिलाफ ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच में सबसे सफल गेंदबाज रही थीं। इस मैच में उन्होंने आठ विकेट लिए थे। उन्होंने इसके बाद दो वनडे में तीन-तीन विकेट हासिल किए थे। भारत की शेफाली वर्मा भी इस पुरस्कार की दौड़ में थीं।

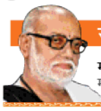
संकट का समय ही हमें शुभ संकल्पों के लिए प्रेरित करता है और अनुकूल स्थिति में लाता है। मोक्ष की अवधारणा इस वक्त हमारे काम की है। कोई भी घटना घट जाए तो उसका शोक मत करो। अतीत का शोक न रहे, वर्तमान का मोह न रहे। भविष्य की चिंता मिट जाए। यही मोक्ष है। मोक्ष के लिए हमारा मरना जरूरी नहीं, बल्कि भीतर की कुप्रवृत्तियों को मारना जरूरी है...



फोटो : इमेजेज बाजार

शुभ संकल्पों की प्रेरणा

सामयिक चिंतन



मोरारी बापू
मानस वक्ता

अक्सर चर्चा होती है कि मोक्ष क्या है। मैं कहता हूं कि मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। अंदर कुछ चीजें मर जाएं तो मोक्ष है। आदमी मृत्यु से नहीं, उसके भय से मर जाता है। मृत्यु टलने वाली नहीं, मगर भय को टाला जा सकता है। तीन बातें हमारे जीते जी मर जाएं तो मृत्यु ही मोक्ष है। आदमी मर जाए, मगर वासनाएं (इच्छाएं) बची रहें तो वह मृत्यु है। वासनाएं मर जाएं और आदमी जीता रहे तो जीवन मुक्ति है। जहां बंधन हो, वहीं मोक्ष आता है। बंधन है ही नहीं, तो मुक्ति कैसी? यहां कोई बंधन है ही नहीं। केवल भ्रम का बंधन है। सही बंधन हो तो खोला जा सकता है। गांठ कैसी भी हो, खोली जा सकती है, मगर भ्रम का बंधन कैसे खोला जाए। माना हुआ बंधन कैसे खोलें। मूल में जो आदमी बंधा ही नहीं, उसको मोक्ष कैसा। जिसको मांगना पड़े, वह मोक्ष कैसा। मांगना, इच्छा करना तो मोक्ष में बाधा है। इच्छा से मुक्त हो जाना ही तो मोक्ष है। इच्छा के साथ मोक्ष कैसा।

हम भोजन तृप्ति के लिए करते हैं। भोजन करना होता है और तृप्ति अपने आप आ जाती है। तृप्ति के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। आहार-विहार ठीक न होने के कारण पचाने के लिए चूर्ण आदि उपाय, क्रिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने आहार-विहार ठीक से साधा नहीं। वैसे ही भजन करना, भक्ति करना जरूरी है। मुक्ति के लिए और कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं है। भिक्षा भाव से भोजन करो तो तुम उपवासी हो। जो आए, वह भोजन स्वीकार। सत्संग से विवेक पाकर अभ्यास करते-करते तीन चीजें मिट जाएं तो जीते जी हम मुक्त हैं- शोक, मोह और चिंता। कोई भी घटना हो तो उसका शोक मत करो। जो क्षय हुआ था, उसे सोने से पहले भूल जाओ। अतीत का शोक न रहे, वर्तमान का मोह न रहे। अच्छा खाना मिला, खा लिया, मगर दोबारा मिलने का मोह न रहे। भविष्य की चिंता मिट जाए। यही मोक्ष है।

जो आदमी मर गया, उसका अतीत, वर्तमान, भविष्य यानी शोक, मोह, चिंता सब उसके साथ चला गया। उसका पूरा परिवार रोता है, मगर वह चैन से है। जो जाता है, उसे वर्तमान का भी मोह नहीं है। स्नान कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। चंदन लगाओ तो ठीक, न लगाओ तो ठीक।

वैष्णव वह है, जो भविष्य की चिंता न करे। विष्णु का सेवक चिंता करे तो उसकी व्यापकता पर दाग है। शोक जितना कम हो, उतना मोक्ष मुट्ठी में है। वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता जितनी कम हो, उतना ही मोक्ष हमारी मुट्ठी में है। पुरुषार्थ जरूर करें, मगर चिंता न करें। प्रकृति का क्रम ऐसा चलता है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वह अनुकूल स्थिति को जन्म देगी ही। ऐसे ही अच्छी स्थिति भी सगर्भा है। वह प्रतिकूल स्थिति को जन्म देगी ही। तुम स्वयं अपने अनुभव से इसे महसूस करो। जब क्रम ही ऐसा है तो कोई शोक क्या करना। कितनी छोटी-सी बात है, अगर समझ में आ जाए। चाय पीने में जो आनंद आता है, वह चाय हो जाने में नहीं आता। इसी तरह से परमात्मा को भजने में जो मजा आता है, वह परमात्मा हो जाने में नहीं आता। तुम श्रद्धा से हरि को भजो तो वही तुम्हारा पितरों के प्रति सच्चा श्राद्ध है। असली तर्पण है प्रेम वाणी। जिन्होंने हमारे खानदान को चार चांद लगाए, उनको याद करते-करते आंख में आंसू आ जाएं तो तर्पण है। आप तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो जरूर करें, मगर भय से नहीं, श्रद्धा से करें। हमारे बाप दादा क्या ऐसे बुरे हैं कि वे हमें डराएंगे। जो डराएं, वे पितृ नहीं, प्रेत होते हैं। श्राद्ध छूट जाए, न कर पाएं तो डरें नहीं। श्रद्धा रखें अपने बाप-दादाओं पर।

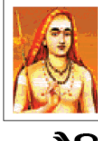
> 'श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि केवल दो बातें अपनाने से कोई भी व्यक्ति संन्यासी हो सकता है। एक, जो व्यक्ति किसी से द्वेष न करे और दो, किसी से कुछ भी अपेक्षा न करे। ऐसा व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी संन्यासी है।'

श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि केवल दो बातें अपनाने से कोई भी व्यक्ति संन्यासी हो सकता है। एक, जो व्यक्ति किसी से द्वेष न करे और दो, जो किसी से कुछ भी अपेक्षा न करे। ऐसा व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी संन्यासी है। द्वेषमुक्त जीवन और कामनामुक्त जीवन ही संन्यास है। विवेक के साथ धीरे-धीरे ऐसा हो सकता है। इस संन्यास के लिए हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। साधक चाहे तो यह हो सकता है, मगर जीवन के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनके प्रति हम इतने गंभीर नहीं हो रहे। मेरा अनुभव है कि अगर आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं तो पूरा अस्तित्व ही आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है।

इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी नजर में 'इह' यानी अपने संसार के साथ-साथ 'पर' यानी दूसरों की दुनिया का भी कल्याण हो। अपने साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। महाभारत में आया है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, उसकी कमाई को खर्च करने का आपका अधिकार है, लेकिन अगर मेहनत कम करके बहुत ज्यादा पैसा आया है तो उस पर प्रजा का अधिकार है। जो लायक इतने हैं कि उन्हें बैंक में नौकरी भी न मिले, मगर उनके बैंक एकाउंट रुपयों से भरे हैं। 'महाभारत' में यह सूत्र आया है- जो संपदा बिना मेहनत के आई है, वह यज्ञ संपदा है, वह प्रजा की संपदा है, वह राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होनी चाहिए।

प्रस्तुति : राज कौशिक

निर्झरिणी



शुद्ध किया गया मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके अलावा कहीं कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं।

- आदि गुरु शंकराचार्य

अलौकिक आनंद का सुख

दृष्टिकोण

सांसारिक सुख और अलौकिक आनंद में एक मूलभूत अंतर है। सांसारिक सुख जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे जीवन असंतुलित और अव्यवस्थित होता जाता है, वहीं अलौकिक आनंद में जितना डूबते जाते हैं, जीवन उतना ही संतुलित और व्यवस्थित होता जाता है। इसका लक्षण यह है कि वाणी में गंभीरता, मन में शांति, हृदय की पवित्रता, प्राणों में जागृति और चेतना अधिक सक्रिय हो जाती है। सांसारिक जीवन में जो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थीं, जो समस्याएं व योजनाएं बढ़ रही थीं, वे अलौकिक आनंद में डूबते ही कम होती दिखने लगती हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों में 'कर्म-क्षय' या 'संस्कार क्षय' होने लगता है।

भारतीय परंपरा में जीवन की पूर्णता के लिए जिन चार पुरुषार्थों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विधान किया गया है, उनमें मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है यानी पहले तीन सांसारिक सुखों से निवृत्ति के बाद परमानंद की शरण में जाने के बाद अलौकिक जीवन की शुरुआत होती है। मोक्ष की शुरुआत का मतलब उस आनंद की शुरुआत है, जो अनंत तक जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सांसारिक जीवन में रहते हुए मोक्ष हासिल नहीं किया जा सकता है? शास्त्र कहते हैं, सांसारिक सुख की धारा अलग है और अलौकिक संसार की धारा अलग। ये नदी के ऐसे दो किनारे हैं, जो मिल तो नहीं सकते, लेकिन कर्म की शुभ और संकल्पी धाराओं के माध्यम से दोनों किनारे जुड़ सकते हैं।

चूंकि जन्म संसार में होता है, इसलिए चारों पुरुषार्थों को पूरा करने के निमित्त सांसारिकता के लिए आवश्यक कर्मों, व्यवहारों, कर्तव्यों और उद्देश्यों को पूरा करना जरूरी है। सांसारिक कर्तव्यों और कर्मों को पूरा करने के लिए वैदिक परंपरा में तीन आश्रमों की व्यवस्था रखी गई और चौथे यानी संन्यास आश्रम यानी मोक्ष के लिए संकल्पवान होकर मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को



समर्पित कर देने की व्यवस्था की गई। चारों पुरुषार्थों में सांसारिक कर्तव्यों और व्यवहारों के लिए तीन पुरुषार्थ हैं और चौथा मोक्ष अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए है।

सांसारिक सुख में शांति, सुरक्षा और प्रसन्नता की गारंटी कोई नहीं दे सकता, जबकि अलौकिक आनंद वस्तुओं से परे होता है, इसलिए यह आपका अपना स्थायी आनंद होता है। क्योंकि अस्थायी सुख उन संसाधनों और वस्तुओं के जरिए हासिल करते हैं, जिनमें स्थायित्व नहीं है। फिर भी हम अस्थायी सुख के लिए रात-दिन श्रम, विचार, तप और संसाधनों को लगाते फिरते हैं। यदि अनुकूलता या सुख की सफलता व उपयोगिता हमारी रुचि या अनुमान के मुताबिक नहीं रहे तो जिन वस्तुओं या संसाधनों के जरिए सुख की लालसा थी, उनसे घृणा या दुराव की स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद सांसारिक सुखों के लिए तृष्णाएं या कामनाएं कम नहीं होतीं। यह विडंबना है कि हम शाश्वत आनंद में डूबने के बजाय सांसारिक क्षणभंगुर सुखों में डूबते-उतराते रहते हैं। स्पष्ट है अलौकिक आनंद न मरता है और न तो क्षय को प्राप्त ही होता है। आनंद के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सुख बिना भौतिक संसाधनों के संभव ही नहीं है। सांसारिक वैभव और सभी तरह के सुखों को भोगने के बाद भी व्यक्ति को न तृप्ति होती है और न ही संतोष होता है।

अखिलेश आर्येन्दु

जीवन से करें प्रेम

चिंतन धरोहर



ओशो

दुख के क्षण तो आते ही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख को ओढ़ लिया जाए। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य रोगों के प्रति ज्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य के प्रति। जब तुम स्वस्थ होते हो तो तुम अपने शरीर के बारे में भूल जाते हो। लेकिन, जैसे ही सिर दर्द होता है या और कोई दर्द या फिर पेट का दर्द तो देह को नहीं भूल पाते। देह तब प्रमुखता से होती है। वह तुम्हारा ध्यान खींचती है।

तुम कहते हो कि बुद्धत्व के लिए तुम उपवास करते रहे हो, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। उपवास और ब्रह्मचर्य का भला बुद्धत्व से क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम कहते हो कि मैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए रात-रात भर जागता रहता हूं, तो दिन में बुद्धत्व प्राप्त करने की



कोशिश क्यों नहीं करते? रात भर कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? कुदरत के विरोध में तुम क्यों खड़े हुए हो? क्यों दुख मोल ले रहे हो।

बुद्धत्व प्रकृति के खिलाफ नहीं होता। वह प्रकृति की परितृप्ति है। वह तो प्रकृति की चरम अभिव्यक्ति है। वह तो जितना संभव हो सकता है, उतनी प्रकृति है। प्रकृति के खिलाफ होने पर नहीं, बल्कि साथ होने पर ही तुम बुद्धत्व तक पहुंचते हो। वह बहाव के खिलाफ तैरने से नहीं, बल्कि उसके साथ बहने से मिलता है। नदी की यात्रा तो पहले से ही समुद्र की तरफ है। तुम्हें उसके खिलाफ तैरना शुरू करने की कोई जरूरत नहीं, जबकि तुम करते यही रहे हो।

मैं तो यही कहूंगा कि जीवन से प्रेम करो और हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करो। जब तुम एकदम प्रसन्न होते हो, जीवन की संभावना तभी होती है, वरना नहीं। इसका कारण यह है कि दुख तुम्हें बंद कर देता है, सुख तुम्हें खोलता है। क्या तुमने यही बात खुद अपने जीवन में नहीं देखी? जब भी तुम दुखी होते हो, बंद हो जाते हो। एक कठोर आवरण तुम्हें घेर लेता है। तुम खुद की सुरक्षा करने लगते हो, तुम एक कवच-सा ओढ़ लेते हो। इसकी वजह यह है कि तुम जानते हो कि तुम्हें पहले से ही काफी तकलीफ है और अब तुम और चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुखी लोग हमेशा कठोर हो जाते हैं। उनकी नरमी खत्म हो जाती है, वे चट्टानों जैसे हो जाते हैं।

एक प्रसन्न व्यक्ति तो एक फूल की तरह है। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वह सारी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता है। वह ऐसे वरदान से संपन्न है कि खुलने की जुर्रत कर सकता है। उसके लिए खुलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सभी कुछ कितना अच्छा है, कितना मित्रतापूर्ण है। पूरी प्रकृति उसकी मित्र है। वह खुल सकता है। वह इस अस्तित्व का आतिथेय बन सकता है। यही वह क्षण है, जब दिव्यता तुममें प्रवेश करती है। केवल उसी क्षण में प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और तुम बुद्धत्व प्राप्त करते हो।

खुद को समझकर होगा दुख का अंत

हमारा जीवन एक अनवरत संघर्ष है और हम यह कह रहे हैं कि इस द्वंद्व का, इस लड़ाई का अंत हो सकता है, जो हमारे खुद के भीतर और बाहर जारी है। इसका अंत तभी हो सकता है, जब आप स्वयं को समझ लें। किसी पुरोहित के अनुसार नहीं, किसी मनोविज्ञानी अथवा किसी प्रोफेसर के अनुसार नहीं, बल्कि अपने को अपने संबंध के दर्पण में देखते हुए आप स्वयं को समझ लें। यही वह दर्पण है, जिसमें आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं- आप क्या हैं, आप क्यों ये बातें सोचते हैं, आप क्यों इस तरह से व्यवहार करते हैं। संबंधों के उस दर्पण में आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे। आप मानव जाति की गाथा हैं। आप ही वह किताब हैं, जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी गुरु या दार्शनिक की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उस किताब को पढ़ सकते हैं, जो कि आप स्वयं ही हैं। जब तक आप इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, इसकी सारी अर्थ-छटाओं को, इसमें जारी सारे क्रियाकलापों को नहीं सुनते, तब तक आपमें हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। आप हमेशा दुख उठाते रहेंगे, हमेशा डरे-डरे रहेंगे। आपको अवलोकन करना होगा। आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी जिंदगी में खुशी की नामौजूदगी को।

जे. कृष्णमूर्ति
(पुस्तक 'मन क्या है' से साभार)

संत समाज को समझने की एक व्यापक दृष्टि

ज्ञान-आलोक



पुस्तक : दादूपंथ के शिखर संत
लेखक : नन्दकिशोर पाण्डेय
प्रकाशन : सामयिक प्रकाशन

पुस्तक में संत दादू दयाल और उनके शिष्यों का जीवनवृत्त, रचनागत विशेषताओं के साथ उनकी बानियां (वाणी) संकलित हैं। अन्य पंथों की तरह दादूपंथ में भी भ्रमण, शिष्य निर्माण, प्रवचन एवं बानियों के संकलन की परंपरा मिलती है। संत रज्जब का 'सर्वंगी' और जगन्नाथ का 'गुणगंजनामा' दादूपंथ के प्रमुख ग्रंथ हैं। 'अनभै वाणी' में संकलित जगजीवन दास की रचनाएं शरीर साधना, योग और आयुर्वेद के ज्ञान से युक्त हैं। भारतीय समाज के लिए दादूपंथ का योगदान बहुआयामी है। पुस्तक दादूपंथ के साथ संत समाज को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती है।



दादूपंथ को आरंभ में 'ब्रह्म संप्रदाय' के नाम से जाना जाता था। दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने दादूपंथ नाम दिया। उस समय गुरुओं के नाम पर पंथ निर्माण का चलन बढ़ चुका था। अन्य पंथों की तरह दादूपंथ का कार्य भी जनसाधारण का मार्गदर्शन करना था। जैसे जनभाषाओं की स्वीकारोक्ति, जातिव्यवस्था का विरोध, अहिंसा पर बल, कविता और संत कर्म को श्रम से जोड़ना, छंदों, संगीत और वाद्ययंत्रों का सृजन, भजन के साथ लंगर, कूप-तालाबों का निर्माण आदि। दादूपंथ के साहित्य में सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक विद्वेष का समाधान भी दिया गया है। ईश्वर और पैगंबर की एकता अनेक पदों में विभिन्न प्रकार से सिद्ध की गई है।

'रज्जब रुचे न राम बिन, सकल भांति के सुख' अध्याय पुस्तक के केंद्र में है। दादू पंथ में जो महत्व रज्जब का है, पुस्तक में वही महत्त्व इस अध्याय का है। सुंदरदास का नाम दादूपंथ में ही नहीं, अपितु पूरे निर्गुण संप्रदाय में सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही दादू की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। उन्होंने ओडिशा, बंगाल, बिहार, लाहौर और बद्रिकाश्रम की यात्रा की थी और वहां सत्संग भी किया था। ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ 'ज्ञान समुद्र' वस्तुतः भारतीय दर्शन का समुद्र है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या विद्वान लोगों का श्रम-कर्म से विमुख होना है। ऐसा लगता है मानो मध्यकाल में सुंदर दास समकालीन समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हों-'ज्ञान क्रिया दोऊ मिलहिं तब ही होइ उबार'।

डा. चंद्रभान सिंह यादव

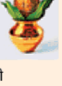
प्रेरक कथा

चलें प्रकृति के संग तादात्म्य रख कर

दार्शनिक कन्फ्यूशियस लू-लियांग जलप्रपात की सैर करने गए। जलप्रपात से पानी सौ फीट नीचे गिर रहा था और दूर-दूर तक उसका पानी उछल रहा था। वह ऐसी जगह थी, जहां मछलियां, कछुए और मगरमच्छ भी नहीं तैर सकते थे। लेकिन वहां उन्होंने एक आदमी को देखा, जो उसे तैरकर पार कर रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई अपनी जान देने पर उतारू है। उन्होंने अपने एक शिष्य को उस आदमी को बचाने के लिए भेजा, लेकिन कुछ दूरी तक तैरने के बाद वह आदमी स्वयं ही बाहर आ गया और गुनगुनाता हुआ किनारे पर चलने लगा। कन्फ्यूशियस ने उससे पूछा, 'तुमने तो अनोखा कारनामा किया। तुम्हें जादू आता है क्या?' उस व्यक्ति ने कहा, 'नहीं, मुझे कोई जादू नहीं आता। मेरे लिए तो यह रोज का काम है। मैं नैसर्गिकता के बीच ही पला-बढ़ा हूं। मैंने निसर्ग से तादात्म्य बना लिया है। जब मैं इस प्रपात में उतरता हूं तो मैं भीतर जाने वाले प्रवाह के साथ उतरता हूं और बाहर जाने वाले प्रवाह के साथ बाहर निकलता हूं। पानी पर अपने स्वभाव को थोपने की बजाय पानी के स्वभाव के साथ चलता हूं। इस प्रकार मैं पानी से तादात्म्य स्थापित कर लेता हूं और पानी की तरह ही किनारे निकल आता हूं।

कथा मर्म : प्रकृति के संग अनुकूलन रखकर जीवन को सहजता से जिया जा सकता है।

सप्ताह के पर्व-त्योहार



14 जुलाई : वैनायकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत
15 जुलाई : गुरु स्कंद षष्ठी व्रत
16 जुलाई : वैवस्वत (सूर्य) पूजा
18 जुलाई : कंदर्प नवमी

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 13 जुलाई, 2021 मंगलवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तृतीया का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 03:00 बजे से 04:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: उत्तर।
आज की भद्रा: रात्रि के 08:14 से 14 जुलाई को प्रातः 08:02 बजे तक।

मेष: बुद्धिकौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।

वृष: दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक महिला से तनाव मिल सकता है। अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी।

मिथुन: वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

कर्क: रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे।

सिंह: सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन भावुकता में नियंत्रण रखें। व्यक्ति विशेष के कारण तनाव मिल सकता है। संयम से काम लें।

कन्या: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। मन खिन्न रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

तुला: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा।

वृश्चिक: किया गया प्रयास सार्थक होगा। महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया से सहयोग मिल सकता है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संबंध मधुर होंगे।

धनु: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। कोई ऐसा कार्य होगा जिससे व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

मकर: जारी प्रयास सार्थक होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे।

कुंभ: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

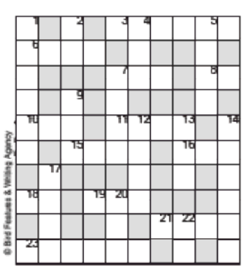
मीन: संतान के आचरण से दुखी हो सकते हैं। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद रहेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कल 14 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: उत्तर।
पर्व एवं त्योहार: गणेश चतुर्थी व्रत।
भद्रा: प्रातः 08:02 बजे तक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 उत्तरायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 08 घंटे 02 मिनट तक, तत्पश्चात् पंचमी पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र 27 घंटे 43 मिनट तक, तत्पश्चात् उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र व्यतिपात योग 13 घंटे 26 मिनट तक, तत्पश्चात् वरियान योग सिंह में चंद्रमा।

वर्ग पहेली-1635

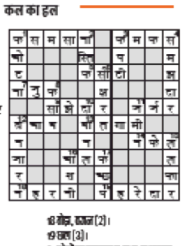


© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
3 [illegible] (5)।
6 [illegible] (4)।
7 [illegible] (3)।
8 [illegible] (2)।
10 [illegible] (3)।
11 [illegible] (4)।
15 [illegible] (4)।
16 [illegible] (3)।
18 [illegible] (2)।
19 [illegible] (3)।
21 [illegible] (4)।
23 [illegible] (3,3)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (2,2,2)।
2 [illegible] (2)।
4 [illegible] (3)।
5 विष, जहर (4)।
7 [illegible] (4)।
9 [illegible] (3)।
12 [illegible] (4)।
13 [illegible] (3)।
14 [illegible] (2,4)।
17 [illegible] (4)।
20 [illegible] (3)।
22 [illegible] (2)।

कल का हल



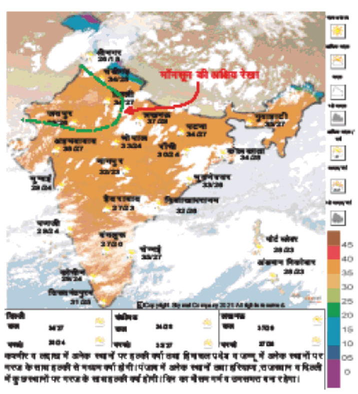
जागरण सुडोकू-1635

		5		6		7		3
6	4				2			5
		1	7			6	4	
3			2			5		1
	7	2			9		8	
8				1				7
7				2		4	3	
	2	8		4			7	
4			1		6			2

कल का हल

5	7	9	3	6	8	2	4	1
1	8	6	4	2	7	3	9	5
4	3	2	5	1	9	6	8	7
2	1	5	7	9	3	4	6	8
6	9	3	1	8	4	5	7	2
8	4	7	2	5	6	1	3	9
9	5	4	8	3	2	7	1	6
3	2	8	6	7	1	9	5	4
7	6	1	9	4	5	8	2	3

मौसम



कश्मीर व लद्दाख में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा तथा हिमाचल प्रदेश व जम्मू में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पंजाब में अनेक स्थानों तथा हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होगी। दिन का मौसम गर्म व उमसभरा बना रहेगा।



सतर्क रहें गंभीर लक्षणों से

कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लोगों को कमजोरी, सांस फूलना, पैरों में सूजन, थकान और नींद न आने की समस्या हो रही है। अगर इस तरह की परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें...

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
मंगलवार 13 जुलाई, 2021
www.jagran.com

भारतीय क्रिकेट टीम ने खेला पहला वनडे मैच

वर्ष 1974 में आज की ही तारीख को लीड्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला था। अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने पहले खेलते हुए 265 रन बनाए। प्रतिद्वंद्वी टीम ने मैच में चार विकेट से जीत दर्ज की थी।





लंदन में चौथे आधुनिक ओलिंपिक की शुरुआत

वर्ष 1908 में आज की ही तारीख को लंदन में चौथे ओलिंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। पहली बार खिलाड़ियों ने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया था। इसी आयोजन के दौरान अमेरिकी खिलाड़ियों ने जजों पर आरोप लगाया था कि वे अपने देश का पक्ष ले रहे हैं।

जब फिल्म करते वक्त साथी अभिनेता को दिल दे बैठीं बीना राय



बॉलीवुड अभिनेत्री बीना राय (असली नाम–कृष्णा सरीन) का जन्म वर्ष 1932 में आज की ही तारीख को लखनऊ में हुआ था। 1951 में 'काली घटा' फिल्म से डेब्यू किया। फिल्म 'औरत' की शूटिंग के दौरान साथी अभिनेता प्रेमनाथ के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा और थोड़े दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। 'घूंघट' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 'अनारकली', 'ताजमहल' जैसी 28 फिल्मों में काम किया। 1967 के बाद फिल्मों को छोड़ घर–गृहस्थी में जुट गईं। पांच दिसंबर 2009 को निधन हो गया।

इधर–उधर की

किराया बचाने के लिए अपनाया अजब तरीका

न्यूयार्क, एजेंसी: इंसान पैसे बचाने के लिए अलग–अलग जुगाड़ खोजता रहता है। न्यूयार्क से भी ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां एक टिकटॉक यूजर ने विमान में यात्रा के दौरान ज्यादा सामान के पैसे बचाने के लिए अजब तरीका अपनाया। दरअसल, एश्लिन को करीब साढ़े तीन हजार रुपये के फ्लाइट के टिकट में सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत थी। उसने दूसरा बैग ले जाने के लिए उसे शर्ट के नीचे बेबी बंप की तरह छिपा लिया। उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ। एश्लिन ने इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो को अभी तक एक करोड़ 32 लाख लोग देख चुके हैं, जबकि 27 लाख लाइक मिले हैं। हालांकि, नियम तोड़ने पर कई लोगों ने उसकी खिंचाई भी की है।



एश्लिन ने दूसरा बैग ले जाने के लिए उसे शर्ट के नीचे बेबी बंप की तरह छिपा लिया। इंटरनेट मीडिया

ऐसे बढ़ सकता है कीमोथेरेपी का असर

तलाशी राह ▶ लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने

इम्यून सेल को सक्रिय कर पैंक्रिएटिक कैंसर के मामले में देखा गया सकारात्मक प्रभाव

वाशिंगटन, एएनआइ : शरीर को बीमारियों से बचाने में इम्यून सेल का बड़ा योगदान होता है। इसे यदि समन्वित रूप में मजबूत और सक्रिय रखा जाए तो कई परेशानियों को कम किया जा सकता है। इसी अवधारणा पर आधारित लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक खास अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि पैंक्रिएटिक (अग्नाश्य) कैंसर के मामलों में इम्यून सेल को एक खास संरचना के लिए एकत्र होने को सक्रिय किया जा सकता है, जो कम से कम प्री-क्लिनिकल माडल में कीमोथेरेपी के असर को बढ़ाता है। यह शोध सेलुलर एंड मालिक्यूलर गैस्ट्रोएंटरोलाजी एंड हेपाटोलाजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में भी यह देखा गया है कि शरीर का इम्यून सिस्टम संक्रमण के बचाव का एक अहम सुरक्षा कवच है। यही इम्यून सिस्टम हमें कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है।

हालांकि, पैंक्रिएटिक कैंसर शरीर के अन्य अंगों के कैंसर से थोड़ा अलग होता है। पैंक्रिएटिक कैंसर सेल एक सघन अभेद्य संरचना स्ट्रोमा से घिरा होता है, जो इम्यून सेल को ट्यूमर तक पहुंचने देने में बाधक होता है। इसलिए, इम्यूनोथेरेपी में कैंसर सेल को मारने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और पैंक्रिएटिक कैंसर के इलाज में इसका असर काफी सीमित होकर रह जाता है। वहीं, यह थेरेपी त्वचा और फेफड़े समेत अन्य कैंसर में काफी प्रभावी रहती है।

इस तरह लगाया पता : शोध में पाया गया है कि पैंक्रिएटिक कैंसर से ग्रस्त कुछ लोगों में इम्यून सेल क्लस्टर के रूप में स्ट्रोमा में जमा हो सकते हैं, जिसे टर्शियरी लिंफायड स्ट्रक्चर (टीएलएस) कहते हैं, जो रोगियों के बचने की संभावना को बढ़ाता है। हालांकि, टीएलएस सभी पैंक्रिएटिक कैंसर के रोगियों में स्वतः ही निर्मित नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने इस विशिष्ट संरचना और टीएलएस की भूमिका की पड़ताल की और ट्यूमर के खिलाफ उसकी गतिविधियों का आकलन किया। टीएलएस की मौजूदगी को ऊतकों में बी सेल, टी सेल और डेंड्रिटिक सेल की अधिकता के आधार पर परिभाषित किया गया है। ये तीनों सेल इम्यून रिस्पांस में अहम भूमिका निभाते हैं। पैंक्रिएटिक कैंसर के रोगियों के सैंपल की जांच के क्रम में इन विशिष्ट सेल्स की मौजूदगी का पता लगाने के लिए स्टेनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें पाया गया कि मात्र एक तिहाई रोगियों में ही टीएलएस मिले।



उपचार में मिलेगी मदद। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

इस तरह मिलती है मदद

इस अध्ययन के प्रमुख क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में लिवर एंड पैंक्रियाज सर्जरी के प्रोफेसर हेमंत कोचर के मुताबिक, पैंक्रिएटिक कैंसर को कोल्ड ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। मतलब यह कि कैंसर सेल के पास पर्याप्त मात्रा में इम्यून सेल नहीं होते हैं, जो उससे लड़ने की कोशिश करें, लेकिन हमने अपने इस अध्ययन में दर्शाया है कि इम्यून सेल को न सिर्फ जमा किया जा सकता है, बल्कि पैंनक्रिएटिक कैंसर में कीमोथेरेपी को अधिक असरदार बनाने के लिए उसे प्री–क्लिनिकल माडल में टीएलएस के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इससे स्ट्रोमा का अवरोध कमजोर किया जा सकता है।



सबसे गहरे स्वीमिंग पूल में गोताखोरी का मजा

डूबे हुए शहर की थीम पर दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्वीमिंग पूल बनाया गया है। यह करीब 60 मीटर (197 फीट) गहरा है, यानी करीब 19 मंजिल के बराबर इसकी गहराई है। इसे सबसे गहरे पूल के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी दर्ज किया गया है। इसमें एक फिल्म स्टूडियो है। डूबे हुए शहर का परिदृश्य मन को मोह लेने वाला है। इतना ही नही, इसमें स्कूबा डाइविंग का अभ्यास भी किया जा सकता है। पूल के अंदर साउंड और लाइटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है। रायटर

पृथ्वी के वायुमंडल से आज या कल टकरा सकता है शक्तिशाली सौर तूफान

जेएनएन, नई दिल्ली: सूर्य की लपटों से उपजा एक शक्तिशाली सौर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसके मंगलवार या बुधवार को धरती के ऊपरी वायुमंडल से टकराने की संभावना है। इसका सीधा असर मोबाइल सिग्नल, जीपीएस नेटवर्क और सेटेलाइट टीवी पर पड़ सकता है। दुनिया के कई हिस्सों में पावर ग्रिड भी बाधित हो सकते हैं।

अमेरिका के मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान के चलते एक बड़े इलाके में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन एक घंटे के लिए बाधित हो सकता है। सबसे पहले इस तूफान का पता तीन जुलाई को चला था। इस तूफान के निकलने पर अमेरिका में थोड़े समय के लिए रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो गई थी।

क्यों आते हैं सौर तूफान : विज्ञानियों के अनुसार प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य की सतह की हलचल और विस्फोट से इतनी भारी मात्रा में विकिरण निकलता है, जो बड़े सौर तूफान लाने की क्षमता रखते हैं। 2019 से इनका नया चरण शुरू है। यह जुलाई 2025 तक चरम पर पहुंचेगा।

कहां–कहां हो सकता है असर

- जीपीएस सिग्नल, मोबाइल नेटवर्क, सेटेलाइट टीवी, आटोमेटिक कार, टैक्सी, प्लेन सेवा पर असर हो सकता है।
- धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर नार्दन, सर्दन लाइट्स की मात्रा और फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है

पहले भी आ चुके हैं सौर तूफान

1972 के सौर तूफान में कई देशों में बिजली और संचार सेवाओं को नुकसान हुआ था। अमेरिकी नौसेना द्वारा उत्तरी वियतनाम के समुद्र में लगाई चुंबकीय प्रभाव से फटने वाली खदान भी स्वयं फट पड़ी।

1989 में कनाडा के क्यूबेक में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप होने से 60 लाख लोग नौ घंटे बिना बिजली के रहे।

2003 में 19 अक्टूबर से पांच नवंबर तक इन तूफानों ने अमेरिका में कई बार रेडियों सेवाएं ठप की। इसे रेडियो ब्लैक आउट कहा गया।

दिन में दो बार बादाम खाने से कम कर सकते हैं डायबिटीज का खतरा

मुंबई, आइएएनएस : दिन में दो बार बादाम खाने से ग्लूकोज मेटाबालिज्म में सुधार करने में मदद मिल सकती है, साथ ही कोलेस्ट्राल के स्तर को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। एक नवीन अध्ययन में बताया गया है कि प्री-डायबिटीज स्टेज पर बादाम के सेवन से ब्लड शुगर के स्तर में सुधार हो सकता है। मुंबई के विठ्ठलदास ठाकरे कालेज आफ होम साइंस के प्रिंसिपल प्रोफेसर जगमीत मदान के मुताबिक, अध्ययन के परिणाम बहुत आशाजनक हैं। हमने पाया कि केवल 12 सप्ताह तक दिन में दो बार बादाम खाने से एलडीएल-कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार हुआ और एचबीए1सी के स्तर में कमी आई। यह अध्ययन 275 लोगों पर किया गया था, जिनमें 59 पुरुष और 216 महिलाएं शामिल थीं। इन्हें 56 ग्राम बादाम दिया गया, जिनमें करीब 340 कैलोरी थी।

काफी से कम हो सकता है कोरोना का खतरा

अनुसंधान

काफी पीने का शौक दुनियाभर में है। हर रोज काफी की चुस्की के बिना तमाम लोगों का दिन ही अधूरा सा रह जाता है। अब एक नए अध्ययन में सामने आया है कि दिन में एक कप काफी आपको कोरोना संक्रमण से बचाने में मदद करती है। काफी पीने वालों को लगभग 10 फीसद कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।

अमेरिका में नार्थ-वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोध में यह भी पाया कि अधिक सब्जियों के सेवन से भी कोरोना संक्रमण की आशंका को कम किया जा सकता है।

यह अध्ययन न्यूट्रिएंट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में बताया गया है कि काफी को एंटी आक्सीडेंट और एंटी इनफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर माना जाता है। काफी का सेवन करने वाले बुजुर्गों में न्यूमोनिया की आशंका भी कम होती है। अब अध्ययन में यह पाया गया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भी दिन में एक कप काफी पीना फायदेमंद है। अध्ययन दल ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ब्रिटेन के 40 हजार वयस्कों के रिकार्ड का विश्लेषण किया। विश्लेषण में कोरोना संक्रमण में एक कप काफी पीने के बहुत सकारात्मक परिणाम मिले। - आइएएनएस



अध्ययन में आया सामने। फाइल /इंटरनेट मीडिया

नेजल कोविड वैक्सीन कोरोना से बचाने में कारगर

एक अध्ययन से पता चला है कि नेजल (नाक के जरिये) कोविड वैक्सीन संक्रमण को रोकने में कारगर है। साइंस एंड एडवांस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस दवाई का प्रयोग पहले चूहों पर किया गया है। चूहों पर प्रयोग सफल रहा है और इस दवाई के बाद चूहों पर कोरोना संक्रमण का कोई असर नहीं पड़ा। अध्ययन दल के सह नेतृत्वकर्ता और जार्जिया विश्वविद्यालय, अमेरिका के प्रोफेसर पाल मैक्रे ने कहा यह अगर इंसानों पर भी उतनी प्रभावी साबित हो जाती है तो इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। - प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

पहली बैठक में ही बन गए थे तुम बिन के दो गाने : निखिल



अपने जोड़ीदार विनय तिवारी के साथ हम तुम्हारे हैं सनम और मुस्कान जैसी फिल्मों को संगीत दे चुके हैं निखिल। सौ. टीम निखिल

संगीतकार निखिल कामत अपने जीवन में साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म तुम बिन को मील का पत्थर मानते हैं। निखिल ने अपने जोड़ीदार विनय तिवारी के साथ मिलकर इस फिल्म को संगीत दिया था। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह फिल्म आज (मंगलवार) अपनी रिलीज के 20 वर्ष पूरे कर रही है। दैनिक जागरण से बातचीत में इस फिल्म से जुड़ीं स्मृतियां साझा करते हुए निखिल बताते हैं, 'निर्माता भूषण कुमार जी के साथ जान एलबम करने के कारण उनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते बन गए थे। एक रात करीब 11 बजे हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच भूषण कुमार जी ने कहा कि हम एक फिल्म शुरू करेंगे, उस बैठक में अनुभव जी भी थे। उसी रात भूषण जी ने मुझे फिल्म के लिए टोकन राशि भी दी। दूसरे दिन भूषण जी के घर बैठक हुई। पहले हमने डिनर किया और फिर अनुभव ने हमें फिल्म की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सुबह तीन बजे तक चली इस बैठक में ही हमारे स्टॉक से फिल्म के दो गाने छोटी छोटी रातें.. और तुम्हारे सिवा.. चुन लिए गए। फिल्म की अभिनेत्री संदली सिन्हा को देखकर मुझे लगता था कि उनके ऊपर के एस चित्रा का गाया गाना ही सटीक बैठेगा। मैंने यह सुझाव भूषण जी को दिया जो उन्हें अच्छा लगा और फिर मैं और अनुभव फिल्म का टाइटल सांग रिकॉर्ड कराने के लिए दक्षिण भारत निकल गए। वहां हमने चित्रा जी के साथ गाना टाइटल सांग और प्यार हमको होने लगा.. रिकॉर्ड किया।'

बीरो का किरदार निभाना मेरा सबसे पसंदीदा अनुभव रहा : सोनम कपूर

एक फिल्म खत्म होने के बाद कलाकार दूसरी फिल्म और किरदार की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन कुछ किरदार कलाकार के दिल के काफी करीब होते हैं। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म भाग मिल्खा भाग में बीरो का किरदार अभिनेत्री सोनम कपूर के लिए कुछ ऐसी ही अहमियत रखता है। सोमवार को इस फिल्म की रिलीज को आठ वर्ष पूरे होने पर सोनम ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'बीरो का किरदार निभाना संभवतः किसी फिल्म के सेट पर मेरा सबसे पसंदीदा अनुभव रहा। एक किरदार जो सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मिल्खा सिंह की कहानी में भी सबसे प्रिय है। आज भाग मिल्खा भाग के आठ वर्ष पूरे होने पर मेरा दिल बीरो की शालीनता और उसके असर के लिए जोर-जोर से धड़क रहा है। मेहरा (राकेश ओमप्रकाश मेहरा), फरहान (फरहान अख्तर) और पूरी भाग मिल्खा भाग की टीम को मुझे यह मौका देने और यह बताने के लिए धन्यवाद कि जब आपका जुनून और लगन एक साथ होता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। फ्लाइंग सिख आपकी विरासत का हिस्सा बनकर मैं बहुत आभारी हूं।' बता दें कि भाग मिल्खा भाग फ्लाइंग सिख के नाम से प्रख्यात पूर्व भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की बायोपिक है। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। सोनम की आगामी फिल्म ब्लाइंट जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।



आगामी दिनों में फिल्म ब्लाइंड में नजर आएंगी सोनम। इंस्टाग्राम

अब भी कोशिश होती है, सार्वजनिक स्थानों पर कतार में ही रहूं : पंकज

सिनेमा के सितारों को प्रसिद्धि मिलने के साथ-साथ कई विशेषाधिकार भी मिल जाते हैं। हालांकि, न्यूटन, स्त्री और कागज जैसी फिल्मों के अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए प्रसिद्धि मिलने का अपना अलग महत्व है। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा के साथ एक लाइव चैट के दौरान उन्होंने अपने लिए प्रसिद्धि मिलने की अहमियत बताते हुए कहा, 'मुझे फेमस होने के बाद यह चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि ज्यादा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जानने लगते हैं और अच्छी-अच्छी कहानियों के आफर ज्यादा मिलते हैं। हर इंडस्ट्री के लोगों को यह लगता है कि फलां शख्स मार्केट में बिक सकता है तो उसे पकड़ो। मैं कभी इसलिए फेमस नहीं होना चाहता था कि मुझे कतार में न खड़ा होना पड़े या मुझे कोई अन्य विशेषाधिकार मिले। मैं फेमस सिर्फ इसलिए होना चाहता था, जिससे मैं अपनी कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है। अब भी मेरा प्रयास रहता है कि एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मैं आम लोगों की कतार में ही जाऊं।'



पंकज की मिमी, 83 और बच्चन पांडे रिलीज की कतार में हैं। सौ. टीम पंकज

लोनावाला की घटना के बारे में मुझे भी जानना है : शरद केलकर

फ्रेंचाइजी फिल्मों और वेब सीरीज में अक्सर देखा जाता है कि निर्माता-निर्देशक सीजन का अंत कुछ इस तरह से करते हैं, जिससे दर्शकों में अगले सीजन के प्रति भी उत्सुकता बरकरार रहे। हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। निर्देशक जोड़ी राज निदिमोरू और कृष्णा डीके निर्देशित इस शो में नायक श्रीकांत तिवारी की पत्नी सुचि और अभिनेता शरद केलकर के किरदार अरविंद के बीच लोनावाला में हुई किसी घटना का जिक्र किया गया है। हालांकि, निर्माताओं ने सीजन के अंत में भी इससे पर्दा नहीं उठाया, जिसको लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में शरद (हंसते हुए) कहते हैं, 'सभी लोगों की तरह मुझे भी जानना है कि अरविंद और सुचि के बीच लोनावाला में क्या हुआ था? वास्तव में इसके बारे में तो सिर्फ शो के निर्देशक राज एंड डीके और सुमंत कुमार को ही पता होगा। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। मेरे दोस्त और करीबी भी इस बारे में अक्सर मुझसे पूछते हैं। उनको मेरे जवाब रहता है कि मुझे खुद नहीं पता तो मैं आप सबको कैसे बताऊं। अभी तो तीसरा सीजन लिखा जाना बाकी है, उम्मीद है कि तीसरे सीजन में इस राज से पर्दा उठेगा। अंतिम निर्णय तो निर्माताओं को ही लेना है। देखते हैं कि तीसरे सीजन में वह इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे या नहीं।' आगामी दिनों में शरद की भुजः द प्राइड आफ इंडिया, देजा वू और एक मराठी फिल्म रिलीज होने की कतार में हैं।



फिल्म भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगे शरद। इंस्टाग्राम

> फिल्मों में शादी मेरे लिए काफी लकी रही है। इसके बारे में मैं कभी शिकायत नहीं कर सकती हूं। जहां तक 14 फेरे की बात है तो यह फिल्म सिर्फ शादी के बारे में नहीं है।

14 फेरे में काम करके समझ में आ गया कि ज्यादा प्लानिंग से कुछ नहीं होता : कृति



एक बार फिर दुल्हन की भूमिका में दिखेंगी कृति खरबंदा ● इंस्टाग्राम

जीवन में शादी जैसे अहम मौकों के लिए लोग काफी प्लानिंग करते हैं। कुछ इसी तरह की प्लानिंग करते दिखे अभिनेता विक्रांत मेस्सी और अभिनेत्री कृति खरबंदा फिल्म 14 फेरे के ट्रेलर में, जो सोमवार को रिलीज हुआ। इस मौके पर आयोजित वर्चुअल कांफ्रेंस में कृति, विक्रांत और फिल्म के अन्य कलाकारों के साथ निर्देशक देवांशु सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान अपनी शादी की प्लानिंग को लेकर कृति ने कहा, इस फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले मुझे मलेरिया हो गया था, उसने मेरी जो बैंड बजाई थी कि कोई प्लानिंग काम नहीं आई। (हंसते हुए) मुझे तो भाग कर एक दिन में शादी करनी है। इतनी तैयारी का झंझट नहीं हो पाता है मुझसे। इस फिल्म में शादी के लिए इतनी तैयारी कर लेने के बाद मुझे समझ में आ गया कि बॉस, ज्यादा प्लानिंग से कुछ नहीं होता है। बस इंसान सही होना चाहिए, शादी तो कहीं भी की जा सकती है। इस फिल्म से पहले कृति शादी में जरूर आना, वीरे दी वेडिंग और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में भी दुल्हन के तौर पर नजर आई हैं। इस पर उन्होंने कहा, फिल्मों में शादी मेरे लिए काफी लकी रही है, जिसके बारे में मैं कभी शिकायत नहीं कर सकती हूं। जहां तक 14 फेरे की बात है तो यह फिल्म सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। फिल्म में संजू और अदिति के प्रेम सफर को दिखाया गया है।

शूटआउट फिल्म सीरीज का हिस्सा होंगे आदित्य

कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म के निर्माता और लेखक संजय गुप्ता शूटआउट सीरीज की तीसरी फिल्म पर काम कर रहे हैं। शूटआउट सीरीज की दूसरी फिल्म शूटआउट एट वडाला साल 2013 में रिलीज हुई थी। शूटआउट सीरीज की तीसरी फिल्म साल 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और माफिया अरुण गवली के गैंग के बीच हुए शूटआउट पर आधारित होगी। अब खबर है कि इस फिल्म के लिए निर्माताओं ने अभिनेता का भी चयन कर लिया है। आशिकी 2 और मलंग जैसी फिल्मों के अभिनेता आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म के लिए निर्माताओं की पहली पसंद हैं। आदित्य फिलहाल अपनी आगामी फिल्म ओम-द बैटल विदिन की शूटिंग में व्यस्त हैं। सूत्रों के अनुसार, फिलहाल एक्शन फिल्मों के लिए आदित्य काफी डिमांड में हैं। ओमः द बैटल विदिन के बाद अब शूटआउट सीरीज फिल्म के निर्माताओं ने आदित्य को इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर कास्ट करने का फैसला किया है। आदित्य और निर्माताओं के बीच बातचीत अंतिम चरणों में है। अभी फिल्म में आदित्य के किरदार और अन्य जानकारियों को गुप्त रखा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म का शीर्षक शूटआउट 3ः गैंग वॉर्स ऑफ बांबे रखा जा सकता है।



फिलहाल फिल्म ओम : द बैटल विदिन की शूटिंग कर रहे हैं आदित्य ● इंस्टाग्राम

बन सकता है हसीन दिलरुबा का सीक्वल

बीते दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म हसीन दिलरुबा में विक्रांत मेस्सी के किरदार में कई शेड देखने को मिले। इसमें उनकी पत्नी की भूमिका में तापसी पन्नू थी। ट्विटर पर कई प्रशंसक इस फिल्म के सीक्वल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इस बाबत दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड से बातचीत में विक्रांत ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है। अगर लोग चाहते हैं और लोगों की डिमांड है तो हम उस बारे में सोचेंगे। फिल्म का अंत एक दिलचस्प मोड़ पर होता है। फिल्म की कहानी कनिका ढिल्लन ने लिखी है। वह बेहतरीन लेखिका हैं। सीक्वल बनाना निर्माताओं पर निर्भर करता है। अगर वह तैयार होंगे तो हम भी करेंगे। जब यह फिल्म मेरे पास आई थी तो मैं इसका ग्रे किरदार निभाना चाहता था। आम तौर पर लोगों को लगता है कि यह कितना प्यारा लड़का है, लेकिन यह मेरी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी है। बतौर कलाकार मैं मानवीय व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। वहीं फिल्म में प्रदर्शित प्यार के प्रति पागलपन पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। इस बाबत विक्रांत कहते हैं, अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं है, तो यह उचित है, लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हम काल्पनिक दुनिया में नहीं रहते हैं। यह लगभग बच्चों के सामने सच मत बोलो जैसा है। हम व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहे थे। यह गूढ़ काल्पनिक दुनिया से संबंधित कहानी है। इसके बाद विक्रांत फिल्म लव हास्टल में सान्या मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगे।



फिल्म लव हास्टल में सान्या मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगे विक्रांत ● इंस्टाग्राम

ईशा देओल तख्तानी बनीं निर्माता

ईशा देओल तख्तानी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भरत ईशा फिल्म्स की शुरुआत कर दी है। उनकी निर्माण कंपनी में बनने वाली पहली फिल्म होगी एक दुआ। खास बात यह है कि एक दुआ फिल्म में ईशा अभिनय भी करेंगी। वह फिल्म में मुख्य भूमिका में होंगी। रामकमल मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म महिलाओं पर एक सार्थक संदेश भी देगी। ईशा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी दो बेटियों की देखभाल करने में व्यस्त हूं। मैं हमेशा चाहती थी कि फिल्मों में वापसी करूं, लेकिन मैं एक खास स्क्रिप्ट के साथ वापसी करना चाहती थी। अब जब मेरी बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं और मुझे दिलचस्प प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि यह मेरे लिए सही समय है एक बार फिर से कैमरे के सामने आने का। मैं ऐसी फिल्म करना चाहती थी जो बदलाव को भी प्रेरित करे। फिल्म की कहानी सुनी, तो यह मुझे छू गई। मैंने निर्णय लिया कि एक्टिंग के अलावा निर्माता के तौर पर भी जुड़ना चाहिए।



डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू करने वाली हैं ईशा ● इंस्टाग्राम